FOCUS NEWS
फोकस न्यूज

facebook.com/fnind
twitter.com/fnind
focusnewsindia.blogspot.in

www.focusnews.co.in
+focusnewsin

...आपका अपना अखबार

राष्ट्रीय संस्करण। नई दिल्ली। गुरुवार 12 फरवरी 2026। एकादशी, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष। 2081 विक्रम संवत । पेज – 12 । मूल्य 2 रु । वर्ष : 13। अंक : 210

'विकसित केरलम' प्रशिक्षण के लिए दिल्ली आए केरल के भाजपा पार्षद

केरल में तिरुवनंतपुरम नगर निगम के नवनिर्वाचित भाजपा पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल तीन दिवसीय प्रशासनिक और शासन कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बुधवार को दिल्ली पहुंचा।

सूर्य भाई और मैं जरूरत पड़ने पर सूत्रधार की भूमिका निभा सकते हैं: तिलक वर्मा

अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर तिलक वर्मा ने बुधवार को यहां कहा कि मौजूदा टी20 विश्व कप में जरूरत पड़ने पर वह भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ पारी के सूत्रधार की भूमिका निभा सकते हैं।

वैश्विक भरोसे का प्रतीक भारतवर्ष

भारतवर्ष कभी किसी देश पर आक्रमण करना नहीं चाहता और ना ही भारत कभी विश्व विजय की बात करता है। भारतवर्ष हमेशा विश्व के एकीकरण की बात करता है अर्थात विश्वबंधुत्व की बात करता है।

यूं पायें तनाव से मुक्ति

आजकल समय ही ऐसा आ गया है कि हर दूसरा आदमी तनाव से पीड़ित है। यदि आप तनावग्रस्त हैं तो आप निम्न सुझावों पर अवश्य अमल करें। आपको शीघ्र ही तनाव से मुक्ति मिल जायेगी।

'वाराणसी' प्रियंका चोपड़ा जोनास की अगली बड़ी फिल्म होगी : निक जोनास

पॉप गायक निक जोनास को पूरा यकीन है कि उनकी पत्नी प्रियंका चोपड़ा जोनास की आने वाली तेलुगु भाषा की एक्शन–एडवेंचर फिल्म 'वाराणसी' शानदार होगी।

भारत–अमेरिका व्यापार करार से कुछ फल उत्पादक परेशान, तो कुछ ने बताया अवसर

जम्मू–कश्मीर में कुछ फल उत्पादक और डीलर भारत–अमेरिका व्यापार समझौते के स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बुरे असर को लेकर परेशान हैं, लेकिन इस समूह में कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इस समझौते से कीमतें स्थिर होंगी और स्थानीय पैदावार की गुणवत्ता बेहतर होगी।

एसबीआई बाजार पूंजीकरण के मामले में चौथे स्थान पर, टीसीएस को पीछे छोड़ा

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) मजबूत तिमाही नतीजों के बाद आई तेजी के दम पर बुधवार को बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की चौथी सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी बन गई है।

रोल्स–रॉयस के सीईओ ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की

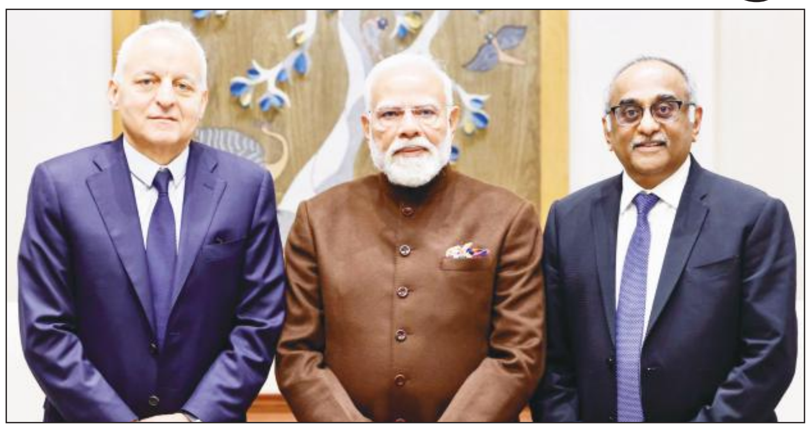

नयी दिल्ली, फोकस न्यूज, आलीशान कार बनाने वाली रोल्स–रॉयस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तूफन एर्गिनबिल्जिक ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और विकसित भारत का हिस्सा बनने के लिए देश में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने की योजना साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''आज रोल्स–रॉयस के सीईओ तूफन एर्गिनबिल्जिक से मुलाकात शानदार रही।'' उन्होंने कहा, ''हम भारत में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने और हमारे नवोन्मेषी एवं गतिशील युवाओं के साथ साझेदारी करने के लिए रोल्स–रॉयस के उत्साह का स्वागत करते हैं।'' वह एर्गिनबिल्जिक के साथ मुलाकात पर रोल्स–रॉयस के एक पोस्ट का जवाब दे रहे थे। ब्रिटेन की विनिर्माण कंपनी ने पोस्ट में कहा, ''हमारे सीईओ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और चर्चा की कि कैसे रोल्स–रॉयस विकसित भारत का हिस्सा बनने के लिए आगे बढ़ रही है, जिसमें अपने विनिर्माण केंद्र को विश्व स्तर पर सबसे बड़ा बनाने, जटिल विनिर्माण का सह–निर्माण और इंजीनियरिंग दक्षता का विकास करना शामिल है।''

'वायुशक्ति' में भाग लेंगे राफेल, तेजस; 'ऑपरेशन सिंदूर' में वायुसेना की सफल भूमिका की झलक पेश करेंगे

नयी दिल्ली, फोकस न्यूज, सैन्य अभ्यास 'वायुशक्ति' में राफेल, सुखोई–30, मिग–29, तेजस, जगुआर और अन्य लड़ाकू विमान शामिल होंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना की "सफल भूमिका" की झलक पेश करेंगे। वायुसेना के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। वायुशक्ति 27 फरवरी को राजस्थान के 'पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज' में आयोजित किया जाएगा। वायुसेना उपाध्यक्ष एयर मार्शल नागेश कपूर ने बताया कि राजस्थान के पोकरण में इस सैन्य शक्ति अभ्यास के दौरान "लंबी दूरी के लक्ष्य बनाने'' का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि द्विवार्षिक इस अभ्यास को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह पिछले वर्ष के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आयोजित किया जा रहा है।

वायुसेना अधिकारी ने बताया कि लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और परिवहन विमान सहित 120 से अधिक विमान इस अभ्यास में भाग लेंगे। अधिकारी ने संवाददाता सम्मेलन में दिए गए प्रस्तुतीकरण में कहा कि इस अभ्यास में राफेल, सुखोई–30, मिग–29, तेजस, जगुआर और मिराज–2000 के अलावा अपाचे, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या पश्चिमी सीमा के पास हो रहे इस अभ्यास से पाकिस्तान को कोई रणनीतिक संदेश जाएगा, उन्होंने कहा, "हम अपना अभ्यास करेंगे। इससे किसे क्या संदेश जाएगा, यह आप पर निर्भर करता है।"

श्रमिकों के बच्चों के सपनों को उड़ान... सीएम रेखा गुप्ता ने 12.40 करोड़ की शिक्षा सहायता सीधे बैंक खातों में भेजी

नई दिल्ली। फोकस न्यूज। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने त्यागराज स्टेडियम में निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए आर्थिक सहायता कार्यक्रम और गांवों से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के 15,706 बच्चों के लिए 12.40 करोड़ रुपये से अधिक की पढ़ाई से जुड़ी सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की। साथ ही, दिल्ली के दो गांवों में नए बने पंचायत घरों का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा 37 गांवों में 59 नई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई, जिनकी कुल अनुमानित लागत 134 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित हजारों श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली केवल इमारतों और सड़कों से नहीं बनती, बल्कि श्रमिकों के श्रम से बनती है। जो हाथ दिल्ली को गढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा, सम्मान और भविष्य की जिम्मेदारी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में दिल्ली के श्रम एवं रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा, दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार चौहान, श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि का स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार 'अंत्योदय' के सिद्धांत पर काम कर रही है, जिसका अर्थ है समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाना। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साझा करते हुए कहा कि सत्ता हमारे लिए सुख भोगने का साधन नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने श्रमिकों के कल्याण के लिए जमा भारी (शेष पेज दो पर)

उत्तराखंड में कानून–व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा: सीएम धामी

देहरादून, फोकस न्यूज, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सख्त शब्दों में कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यहां कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को निर्देश दिए कि सभी प्रकार के अपराधों पर तत्काल मुकदमे दर्ज किए जाएं और अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। धामी ने इस दौरान विशेष रूप से आदतन एवं संगठित अपराध में संलिप्त अपराधियों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए और कहा कि ऐसे तत्वों की पहचान (शेष पेज दो पर)

पेश हुआ योगी सरकार का 10वां बजट, जानिए उत्तर प्रदेश के बजट की प्रमुख घोषणाएं

लखनऊ, फोकस न्यूज, योगी सरकार ने अपना 9,12,696 करोड़ रुपये का विशाल बजट पेश कर दिया है, जिसे 2027 के चुनाव से पहले राज्य के विकास का मास्टरप्लान माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पेश किए गए इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं और श्रमिकों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आइए आपको बताते हैं यूपी के बजट की खास घोषणाएं। **छात्राओं और शिक्षा के लिए बड़े ऐलान– मेधावी छात्राओं को स्कूटी:** 'रानी लक्ष्मीबाई योजना' के तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। **भारी–भरकम शिक्षा बजट:** बेसिक शिक्षा के लिए ₹77,622 करोड़ और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए ₹6 करोड़ की व्यवस्था (शेष पेज दो पर)

सुशासन और समृद्धि के संकल्प को साकार करने वाला है उप्र का प्रस्तावित बजट : पंकज चौधरी

लखनऊ, फोकस न्यूज, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को जन आकांक्षाओं को समर्पित और समृद्धि के संकल्प को साकार करने वाला ऐतिहासिक बजट बताया। उप्र सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट पेश किया। भाजपा राज्य मुख्यालय से जारी बयान में प्रस्तावित बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चौधरी ने कहा, ''यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता का परिणाम है, जो उत्तर प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में (शेष पेज दो पर)

इंटरनेट पर निजी फोटो या संवेदनशील कंटेंट से परेशान होने की अब जरूरत नहीं, गूगल ने कर दी इसे हटाने की व्यवस्था; जानिए तरीका

नई दिल्ली। मोबाइल से फोटो खींचना भला किसे पसंद नहीं, लेकिन लोगों को ये डर भी रहता है कि उनके निजी फोटो कहीं इंटरनेट पर सार्वजनिक न हो जाएं। अब किसी को ऐसा डर नहीं रहेगा। यूजर्स की प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए गूगल नया टूल लाया है। इस टूल की मदद से यूजर्स गूगल सर्च में मौजूद अपनी निजी फोटो या संवेदनशील जानकारियों को तुरंत डिलीट कर सकेंगे। गूगल ने बताया है कि अपडेटेड सर्च सिस्टम ऐसे लोगों की मदद करेगा, जो अपनी निजी फोटो या संवेदनशील कंटेंट लीक का शिकार हुए हैं। गूगल के नए टूल से यूजर्स अपनी सिलेक्टेड जानकारी ऑनलाइन दिखा सकेंगे। गूगल ने ब्लॉग पोस्ट में बताया है कि नए टूल से लोग सर्च रिजल्ट में अपने बारे में आपत्तिजनक कंटेंट को रिपोर्ट कर सकेंगे। इस टूल की मदद लेकर एक नहीं, बल्कि यूजर्स अपनी कई फोटो को रिपोर्ट कर सकते हैं। हर फोटो या संवेदनशील जानकारी के लिए अलग–अलग रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही गूगल का नया टूल आसान है। जिसमें सर्च रिजल्ट से कई फोटो हटाने का यूजर्स आग्रह कर सकते हैं। गूगल का नया टूल यूजर्स को तमाम सेफगार्ड ऑप्शन भी देता है। किसी भी अतिरिक्त सर्च रिजल्ट को वो फिल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा यूजर्स को लीगल और इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है। गूगल के यूजर्स त्मेनसजे इवनज लवन में (शेष पेज दो पर)

कांग्रेस ने पूर्वोत्तर, विशेषकर असम का 'वोट बैंक की राजनीति' के लिए इस्तेमाल किया : शिवराज

गुवाहाटी, (भाषा) केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पूर्वोत्तर, विशेषकर असम का ''वोट बैंक की राजनीति'' के लिए इस्तेमाल किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूर्वोत्तर पर उचित ध्यान दिया है और इस क्षेत्र को देश के विकास का केंद्र बनाया है। चौहान ने कहा, ''दशकों तक, कांग्रेस ने पूर्वोत्तर, विशेषकर असम को अपनी कुख्यात वोट बैंक की राजनीति को अंजाम देने की जगह के रूप में माना। उसके कार्यकाल के दौरान जर्जर सड़कें, खराब रेल नेटवर्क, कोई उद्योग नहीं था और कोई रोजगार सृजन नहीं था।'' उन्होंने कहा, जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने कार्यभार संभाला तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वोत्तर के विकास पर ध्यान केंद्रित किया और क्षेत्र की सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। चौहान ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026–27 के केंद्रीय बजट ने विकसित भारत का पूरा खाका तैयार किया है। उन्होंने कहा, ''पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला 'चिकन नेक कॉरिडोर' भारत की एकता का पुल और देश की (शेष पेज दो पर)

क्या कभी खाई है सिंधी कढ़ी, चखते ही आ जाएगा मजा, नोट कर लीजिए आसान सी रेसिपी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भुने हुए बेसन और टमाटर वाली सिंधी कढ़ी महज आधे घंटे के अंदर बन जाती है। इस कढ़ी में सहजन, भिंडी, ग्वार फली, आलू और बैंगन भी डाला जा सकता है। सिंधी कढ़ी बनाने के लिए 4 बड़ी स्पून बेसन, सहजन, आलू, तली हुई भिंडी, गाजर, कटा हुआ बैंगन, राई, जीरा, मेथी दाना, हींग, करी पत्ता, अदरक–मिर्च का पेस्ट, एक कप टमाटर की प्यूरी, 3–4 बड़ी स्पून इमली का गूदा और 2 बड़ी स्पून तेल की जरूरत पड़ेगी।

पहला स्टेप– सबसे पहले कड़ाही में तेल गर्म कर इसमें मेथी दाना, राई, हींग और जीरे का तड़का लगाइए। अब इस तड़के में बेसन एड कर इसे तब (शेष पेज दो पर)

विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चढ़ाएं ये चीजें, श्री हरि की मिलेगा अपार कृपा, पूरी होगी हर मनोकामना

विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी, शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 12 फरवरी को 12:22 पी एम बजे से होगा। एकादशी तिथि का समापन 13 फरवरी 02:25 पी एम बजे होगा। विजया एकादशी का व्रत करने से हर काम में विजय प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा करें। इसके साथ ही विजया एकादशी के दिन नारायण को ये चीजें भी अर्पित करें। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आइए जानते हैं विजया एकादशी के दिन क्या–क्या चीजें भगवान विष्णु को चढ़ाएं। **तुलसी:** भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा और भोग दोनों ही अधूरी मानी जाती है। तो श्री हरि को तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। **पंचामृत:** विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत चढ़ाएं। पंचामृत का भोग (शेष पेज दो पर)

निर्वाचन आयोग बंगाल की 78 बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में मतदान केंद्र स्थापित करेगा

कोलकाता, (भाषा) निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 78 बड़े आवासीय परिसरों में मतदान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है और इन आवासीय समितियों की सूची 25 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह निर्णय मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनीक्षण (एसआईआर) के बीच आया है, जिससे राज्य में मतदाताओं की संख्या घटने की आशंका है। पश्चिम बंगाल में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अधिकारी ने बताया, "मतदान केंद्रों की स्थापना के लिए 78 आवासीय परिसर चिह्नित किए गए हैं। विस्तृत सूची 25 फरवरी को सार्वजनिक की जाएगी। एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाताओं की संख्या में भारी कमी आने की आशंका है, इसलिए मतदान केंद्रों की कुल संख्या भी कम हो जाएगी।"

श्रमिकों के... (पेज एक का शेष) सेस फंड का कभी सही उपयोग नहीं किया। पिछली सरकारों की नजर कभी गरीबों पर नहीं पड़ी, लेकिन हमारी सरकार ने अपने 365 दिन दिल्ली के लिए पसीना बहाने वाले मजदूर साथियों को समर्पित किए हैं। जब श्रमिक मजबूत होगा, तभी दिल्ली मजबूत बनेगी।

वित्तीय सहायता योजना : मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता योजना चला रहा है, ताकि आर्थिक तंगी उनकी पढ़ाई में बाधा न बने। इस योजना के तहत पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को 500 रुपये/माह, 9वीं और 10वीं के छात्रों को 700 रुपये/माह, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को 1,000 रुपये/माह और स्नातक स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों को 3,000 रुपये/माह की सहायता दी जाती है। वहीं आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल और एमबीए जैसे तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले छात्रों को 10,000 रुपये/माह तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

श्रमिक कल्याण एवं श्रम सुधार : दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी देश में सर्वाधिक स्तर पर निर्धारित की गई है, जिसमें अन स्किल्ड श्रमिकों के लिए 18,456 रुपये, सेमी स्किल्ड श्रमिकों के लिए 20,371 रुपये और स्किल्ड श्रमिकों के लिए 22,411 रुपये प्रतिमाह तय किए गए हैं। राज्य में 44 से अधिक श्रम कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है, ताकि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। श्रमिकों की सहायता के लिए 155214 हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। इसके अलावा, 36 लाख से अधिक असंगठित श्रमिकों का ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है। बाल श्रम के विरुद्ध चलाए गए 72 विशेष अभियानों के माध्यम से 1,028 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया है।

दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड की पहल : दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का पुनर्गठन कर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों को नई गति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत 776 परियोजनाओं के प्रस्ताव दिए गए, जिनकी अनुमानित लागत 1715.05 करोड़ रुपये है। इनमें से 705 परियोजनाओं को 1,556 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही, 702 परियोजनाओं के लिए प्रथम किश्त के रूप में 157 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से सड़क, तालाब, पार्क, श्मशान घाट, चौपाल, पुस्तकालय और सामुदायिक भवनों का विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली के गांवों की उपेक्षा हुई, जिसे बदलने के लिए सरकार ने पहले ही बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान किया था। आज 705 परियोजनाओं के माध्यम से गांवों में सड़कों, चौपालों, बारात घरों, ओपन जिम और पार्कों का निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह केवल योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर परिणाम देने का प्रयास है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्रमिक कल्याण, शिक्षा और ग्रामीण विकास इन तीनों स्तंभों पर कार्य कर दिल्ली को विकसित दिल्ली और विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सेवा के संकल्प के साथ श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि पिछले वर्षों में श्रमिकों से जुड़े विभागों के कार्य ठप पड़े थे। लेकिन अब तेजी से सुधार किया जा रहा है। दिल्ली के सभी लेबर कोर्ट को ई–कोर्ट में परिवर्तित किया जा रहा है। निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया तेज की गई है, स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, आधुनिक टूल और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महिला श्रमिकों को 24 घंटे किसी भी शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से रुके विकास कार्य अब व्यापक स्तर पर शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें से कई का उद्घाटन और शिलान्यास आज किया गया।

कांग्रेस ने... (पेज एक का शेष) अखंडता की रीढ़ है।'' बजट को "ऐतिहासिक" बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित समूचे देश में सकारात्मक बदलाव लाएगा।

उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय को 6,812 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले बजट से 897 करोड़ रुपये अधिक है। चौहान ने पूर्वोत्तर के लिए सरकार की विभिन्न पहल का जिक्र करते हुए कहा, ''यह बढ़ा हुआ आवंटन क्षेत्र में विकास को गति देने की दिशा में केंद्र सरकार की प्राथमिकता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।''

विजया एकादशी... (पेज एक का शेष) लगाने से घर में धन–धान्य में बरकत होती है। **सूखे मेवे:** एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सूखे मेवे जरूर चढ़ाएं। सूखे मेवे में बादाम, मूंगफली, अखरोट, काजू और पिस्ता आदि चीजें आती हैं। **फल:** विजया एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी को मौसमी फलों का भोग लगाएं। फल में केला को जरूर रखें। फल का भोग लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है।

मखाने की खीर: एकादशी के दिन विष्णु जी को मखाने की खीर का भोग लगाएं। मखाने की खीर भगवान विष्णु को अति प्रिय है। **फूल:** विजया एकादशी के भगवान विष्णु को कमल, गुलाब, गेंदा के फूल और माला चढ़ाएं। इसके अलावा चंपा, चमेली, पारिजात (हरसिंगार), मालती, कनेर के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। **पीला वस्त्र** : एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र चढ़ाएं। पीला रंग नारायण को अति प्रिय है। इसके अलावा चौकी पर पीले रंग के कपड़े बिछाक हीर भगवान विष्णु की मूर्ति और तस्वीर रखें। फिर पूजा आरंभ करें। **चंदन:** एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चंदन प्रिय है। श्री हरि विष्णु को चंदन अर्पित करें। एकादशी के दिन पूजा के समय विष्णु जी को चंदन का तिलक जरूर लगाएं।

क्या कभी... (पेज एक का शेष) तक धीमी आंच पर भूनिए, जब तक ये गोल्डन ब्राउन न हो जाए। दूसरा स्टेप– इसके बाद आपको भुने हुए बेसन में 4 से 5 कप गुनगुना पानी धीरे–धीरे करके मिलाना है। अब टमाटर की प्यूरी, नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर को भी मिक्स कर लीजिए।

तीसरा स्टेप– सभी चीजों को लगभग 10 से 12 मिनट के लिए पका लीजिए। अब इस मिक्सचर में आलू, सहजन और गाजर समेत दूसरी सब्जियों को मिलाकर, कड़ाही को ढक दीजिए जिससे सब्जियां नरम हो जाएं।

चौथा स्टेप– इसके बाद मिश्रण में तली हुई भिंडी और बैंगन को भी मिला लीजिए। थोड़ी देर तक सब्जियों को पकने दीजिए।

पांचवां स्टेप– सिंधी कढ़ी के स्वाद को बढ़ाने के लिए आप इस मिश्रण में इमली का पल्प और थोड़ा सा गुड़ भी मिला लीजिए।

छठा स्टेप– लगभग 2 मिनट तक सिंधी कढ़ी को बॉइल कर लीजिए। गार्निशिंग के लिए हरे धनिए का इस्तेमाल किया जा सकता है।

बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को सिंधी कढ़ी का टेस्ट काफी ज्यादा पसंद आएगा। सिंधी कढ़ी स्वाद में जितनी अच्छी लगती है, आपकी सेहत को भी उतना ही ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है। आप रोटी या फिर चावल के साथ सिंधी कढ़ी का लुत्फ उठा सकते हैं।

इंटरनेट पर... (पेज एक का शेष) जाकर अपने सभी आग्रह का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जब गूगल कोई फैसला लेगा, तो उसकी जानकारी ई–मेल के जरिए भी देगा। गूगल ने बताया है कि संवेदनशील कंटेंट हटाने के लिए बने नए टूल को ज्यादातर देशों के यूजर्स को दे दिया जाएगा। यूजर्स को संवेदनशील जानकारी के बारे में रिपोर्ट करने के लिए सीधे सर्च रिजल्ट में ऊपर दायीं तरफ के डॉट आइकन पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद मेन्यू में त्मउवअम तमेनसज पर क्लिक करना होगा। इस पर गूगल इसकी वजह पूछेगा कि क्या फोटो निजी या संवेदनशील है। इस बारे में बताने के बाद गूगल इंटरनेट से उस फोटो या कंटेंट को हटा देगा।

सुशासन और... (पेज एक का शेष) निरंतर कार्य कर रहे हैं।'' चौधरी ने कहा, ''राज्य सरकार ने 9.12 लाख करोड़ से अधिक का विशाल बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.9 प्रतिशत अधिक है। इससे प्रदेश में विकास और जनकल्याणकारी योजनाएं और अधिक गति से चलेंगी। प्रदेश सरकार ने विकास और विश्वास का जो मॉडल स्थापित किया है, यह बजट उसी प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतिबिम्ब है।'' चौधरी ने कहा कि इस बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा, "मातृशक्ति की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं, जिससे महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से और अधिक सशक्त बन सकें। युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए व्यापक योजनाएं इस बजट में सम्मिलित हैं, जो उन्हें सक्षम और आत्मनिर्भर बनाएंगी।" प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" की भावना को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश को विकास के नए आयामों तक पहुंचाएगा।

उत्तराखंड में... (पेज एक का शेष) कर उनके विरुद्ध विधिक प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाए ताकि समाज में कानून का भय स्थापित हो और आमजन स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस पूरी सक्रियता, सतर्कता व जवाबदेही के साथ कार्य करे, थानों व चौकियों की कार्यप्रणाली को अधिक सुदृढ़ किया जाए और संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त व निगरानी बढ़ाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और कानून हाथ में लेने वालों, असामाजिक तत्वों और प्रदेश की शांति भंग करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में बुधवार को अज्ञात स्कूटी सवारों ने एक व्यवसायी की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी जबकि दो फरवरी को शहर में एक युवती की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गयी थी।

पेश हुआ.. (पेज एक का शेष) की गई है।

गरीब कन्याओं का विवाह: आरक्षित वर्ग की बेटियों की शादी के लिए ₹100 करोड़ और सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की बेटियों के लिए ₹50 करोड़ का प्रस्ताव है।

चिकित्सा के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भारी निवेश: मेडिकल कॉलेज और सीटें: राज्य में 14 नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए ₹1,023 करोड़ दिए गए हैं। प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें अब 4,540 से बढ़कर 12,800 हो गई हैं।

असाध्य रोगों का इलाज: कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए ₹315 करोड़ और असाध्य रोगों के मुफ्त इलाज के लिए ₹130 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

आयुष्मान भारत: मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए ₹500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

उद्योगों और युवाओं के लिए 'बूस्टर डोज': डैडम् सेक्टर: सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए ₹3,822 करोड़ दिए गए हैं। प्रदेश का डैडम् सेक्टर देश में सबसे अधिक 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है।

नई औद्योगिक योजना: 'सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्प्लायमेंट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन' के लिए ₹575 करोड़ प्रस्तावित हैं।

युवा उद्यमी विकास: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए ₹1,000 करोड़ का बजट है, जिसका लक्ष्य हर साल 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना है।

'एक जनपद एक व्यंजन': 'एक जनपद एक उत्पाद' की सफलता के बाद अब सरकार ने 'एक जनपद एक व्यंजन' की नई योजना शुरू की है, जिसके लिए ₹75 करोड़ का बजट रखा गया है।

श्रमिकों को रोजगार के लिए नई पहल: लेबर अड्डों का निर्माण: शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए विशेष 'लेबर अड्डों' का निर्माण कराया जाएगा।

दुर्घटना सहायता: ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता पर ₹2 लाख और आंशिक दिव्यांगता पर ₹1 लाख की सहायता दी जा रही है।

रोजगार मिशन: युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौकरी दिलाने के लिए 'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' का गठन किया गया है।

लखनऊ और अयोध्या के लिए विशेष प्रावधान

नाइट सफारी: लखनऊ के कुकरैल इलाके में पर्यटकों के लिए 'नाइट सफारी' विकसित करने हेतु 207 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

अयोध्या का विकास: रामनगरी अयोध्या की सुंदरता और सुविधाओं के विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था की गई है।

संस्कृति और विरासत: प्रदेश में एक नए संस्कृति संग्रहालय का निर्माण पूरा कर उसका लोकार्पण किया जा चुका है, जो राज्य की विरासत को सहेजेगा।

हर घर नल और स्वच्छ गंगा के लिए बड़ा बजट

नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए कुल 22,676 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

जल जीवन मिशन: इस मिशन के अलग–अलग कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2026–2027 में लगभग 22,452 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। नल से जल का लक्ष्य: प्रदेश के कुल 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से अब तक 2.43 करोड़ घरों को पाइप के जरिए पानी के कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है। प्रदूषण मुक्त गंगा: गंगा नदी में गंदा पानी गिरने से रोकने के लिए कुल 74 सीवरेज परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनमें से 41 प्रोजेक्ट्स पूरे होकर चालू हो चुके हैं और बाकी पर काम चल रहा है।

यूपी बजट 2026 की प्रमुख घोषणाएं– शहरों का विकास: मेरठ, मथुरा और कानपुर में नई विकास योजनाओं के लिए 750 करोड़ रुपये और अयोध्या की नई योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

Although every possible care and caution has been taken to avoid errors or omissions, this publication is being sold on the condition and understanding that information given in this publication is merely for reference and must not be taken as having the authority of or binding in any way on the writers, editors, publishers, and printers and sellers who do not owe any responsibility for any damage or loss to any person, a purchaser of this publication or not for the result of any action taken on the basis of this work. All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent court and forums in Delhi/New Delhi only

Published, Printed, Edited and Owned by Krishna Aggarwal Published from New Delhi, Tel- 011-43560023 E-mail- info@focusnews.co.in, focusnews9@gmail.com
RNI NUMBER - DELBIL/2013/56173, Printed from Vibha Publication Pvt Ltd- D-160 B, Noida Phase - I, Uttar Pradesh - 201301

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के प्रणेता एवं राष्ट्रवाद के मजबूत स्तम्भ थे : डॉ. सतीश पूनिया

नूंह, फोकस न्यूज, अंत्योदय के प्रणेता एवं राष्ट्रवाद के मजबूत स्तम्भ श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस संगोष्ठी का नूंह स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश प्रभारी डा. सतीश पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार एवं हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार जनकल्याणकारी नीतियों से 'लक्ष्य अंत्योदय–प्रण अंत्योदय' के संकल्प के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने का कार्य प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि राष्ट्रहित एवं मोदी सरकार की जनकल्याण की नीतियों को जन–जन तक पहुंचाने को लेकर कार्यकर्ता संकल्पित होकर कार्य करें। इससे पहले डा. पूनिया ने पंडित दीनदयायल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। डॉ. सतीश पूनिया ने कहा कि भाजपा सरकार में योजनाओं का सभी को समान रूप से लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि काबलियत के मामले में ना कोई जाति होती और ना कोई धर्म होता। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनें, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सच्चे मुसलमान थे और देश से प्यार करते थे और देश को ताकत देते थे। डा. पूनिया ने कहा कि जनता पार्टी का हिस्सा जनसंघ था और डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत कश्मीर में हुई क्योंकि डा. मुखर्जी कश्मीर को देश से अलग देखना नहीं चाहते थे। डा. श्याम प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। डा. पूनिया ने कहा कि पंडित दीनदयाल का कहना था कि हर हाथ को काम और हर पेट को रोटी मिलनी चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिखाए मार्ग पर चलते हुए भाजपा सरकार लगातार गरीब कल्याण की योजनाएं बनाकर जनता की सेवा कर रही है। भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कहा कि भाजपा आज सत्ता और संगठन दोनों स्तर पर विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस और नेहरू का पूरे देश में दबदबा था और भाजपा के पास केवल तीन सांसद थे, लेकिन जनसंघ से लेकर भाजपा तक के सफर में पार्टी ने संघर्ष, त्याग और बलिदान के बल पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। डा. सतीश पूनिया ने कहा कि डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संगठन को खड़ा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय राजनीति में एक विचारक, दार्शनिक और चिंतक के रूप में जाना जाता है। उनके 'एकात्म मानव दर्शन', 'अंत्योदय', 'हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी और खेत को पानी' जैसे विचार आज भी भाजपा की नीतियों की आधारशिला है। डॉ. पूनिया ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलते हुए देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

भारत–अमेरिका व्यापार समझौता किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगाः सुनील जाखड़

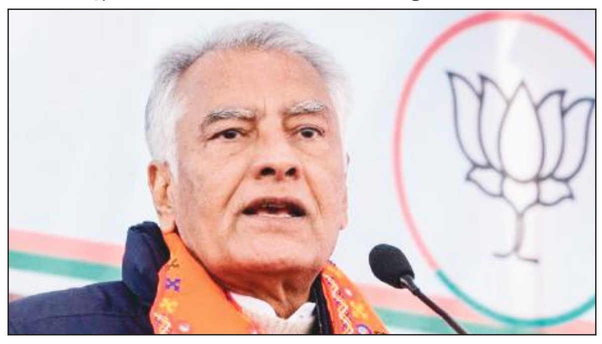

मोहाली, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पंजाब इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ ने बुधवार को कहा कि भारत–अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का किसानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे उद्योग और व्यापार को लाभ होगा एवं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने किसान संगठनों को बातचीत के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि यदि उन्हें व्यापार समझौते में कोई खामी नजर आती है, तो उन्हें आंदोलन के बजाय बातचीत का रास्ता चुनना चाहिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब में उगाई जाने वाली फसलें– गेहूं, धान, मक्का और गन्ना, समझौते के दायरे से बाहर रखी गई हैं तथा यह किसानों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। जाखड़ ने कहा कि हर किसान यह मानता है कि कृषि कोई अत्यधिक लाभदायक पेशा नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे परिवारों का भरण–पोषण तो हो जाता है, लेकिन बच्चों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय नहीं होती। उन्होंने कहा, ''हर परिवार चाहता है कि उनके बच्चे खेती से हटकर अन्य रोजगार तलाशें। लेकिन यह तभी संभव होगा जब नए उद्योग स्थापित हों और व्यापार का विस्तार हो।'' जाखड़ ने कहा कि यह समझौता इसी दिशा में एक कदम है, क्योंकि इससे भारत के उद्योग और व्यापार को 30,000 हजार अरब डॉलर की अमेरिकी अर्थव्यवस्था तक पहुंच मिलेगी। उन्होंने कहा कि उद्योग और व्यापार के विकास से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

'विकसित केरलम' प्रशिक्षण के लिए दिल्ली आए केरल के भाजपा पार्षद

नयी दिल्ली, (भाषा) केरल में तिरुवनंतपुरम नगर निगम के नवनिर्वाचित भाजपा पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल तीन दिवसीय प्रशासनिक और शासन कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बुधवार को दिल्ली पहुंचा। इनके साथ केरल के अन्य नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में नगरपालिका अध्यक्ष, ग्राम पंचायत अध्यक्ष और विधायी दल के नेता शामिल हैं, जो यहां राष्ट्रीय राजधानी में स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुख्यालय में आयोजित होने वाले चार विशेष प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेंगे। भाजपा ने बुधवार को एक बयान में कहा, '' तिरुवनंतपुरम नगर निगम के भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षदों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें राज्य के अन्य नगर निकाय प्रतिनिधि भी शामिल हैं, महापौर वी.वी. राजेश के नेतृत्व में आज दिल्ली पहुंचा।'' केरल के भाजपा नेताओं का यह दौरा 'भाजपा 4 विकसित केरलम' नामक एक व्यापक तीन दिवसीय प्रशासनिक और शासन कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे स्थानीय नेताओं को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक तंत्रों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। बयान के मुताबिक, '' निर्वाचित प्रतिनिधि कल (बृहस्पतिवार) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवास पर उनसे मुलाकात करेंगे।''

राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया जवाब, बताया कब और किस संदर्भ में एपस्टीन से हुई थी मुलाकात

नई दिल्ली। लोकसभा में आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका में जारी हुई एपस्टीन फाइल्स को जिक्र किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम लेते हुए कहा कि उद्योगपति अनिल अंबानी को एपस्टीन से किसने मिलवाया था? राहुल गांधी के इस आरोप पर अब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जवाब देते हुए पलटवार किया है। पुरी ने कहा कि एक डेलीगेशन का हिस्सा रहते हुए मेरी एपस्टीन से तीन–चार मुलाकातें हुईं हैं और यह सार्वजनिक है। राहुल गांधी को बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत है। पुरी ने कहा, आज संसद सत्र के दौरान एपस्टीन फाइलों से जुड़े कुछ घटनाक्रमों के संदर्भ में मेरा नाम लिया गया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये सभी तथ्य सार्वजनिक हैं। मई 2009 में जब मैंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला से लेकर 2017 में मंत्री बनने तक की अवधि के 30 लाख ईमेल जारी किए गए हैं। इस अवधि के दौरान, केवल तीन या चार बैठकों का ही जिक्र है और मेरी बातचीत पूरी तरह से पेशेवर थी, जो इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन मल्टीलेटरलिज्म पर आधारित थी। मुझे अंतर्राष्ट्रीय शांति संस्थान में शामिल होने का निमंत्रण मिला था। मेरी एपस्टीन से बातचीत पेशेवर स्तर पर हुई और यह बहुपक्षवाद पर स्वतंत्र आयोग से संबंधित थी, जिसके अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे और मैं उसका महासचिव था। IPI में मेरे बॉस टेर्जे लार्सन, एपस्टीन को जानते थे और मेरी मुलाकात एपस्टीन से केवल संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने वाले प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में हुई थी। हरदीप सिंह ने बताया कि मेरी मुलाकात लिंक्डइन के संस्थापक रीड हॉफमैन से भी हुई थी, लेकिन केवल भारत में इंटरनेट और व्यावसायिक अवसरों पर पेशेवर चर्चा के संदर्भ में। इसका किसी भी गलत काम से कोई लेना–देना नहीं था। एपस्टीन की आपराधिक गतिविधियों से मुझे जोड़ने वाले सभी दावे निराधार हैं। पुरी ने कहा कि नेता दो तरह के होते हैं, एक वो जो पॉलिटिकल सिस्टम में जिम्मेदारी लेते हैं और अपना जीवन समाज सेवा, देश को बदलने में लगा देते हैं। दूसरे नेता वो हैं जो कभी–कभी देश में रहते हैं और जब वे संसद में आते हैं, तो जब कोई उन्हें ठोस जवाब देता है तो वे सदन से चले जाते हैं। वह (राहुल गांधी) आज भी अपनी ही स्पीच के बाद चले गए।

सरकार वाहन उद्योग की वृद्धि के लिए स्थिर नीतिगत माहौल देने को प्रतिबद्धः कुमारस्वामी

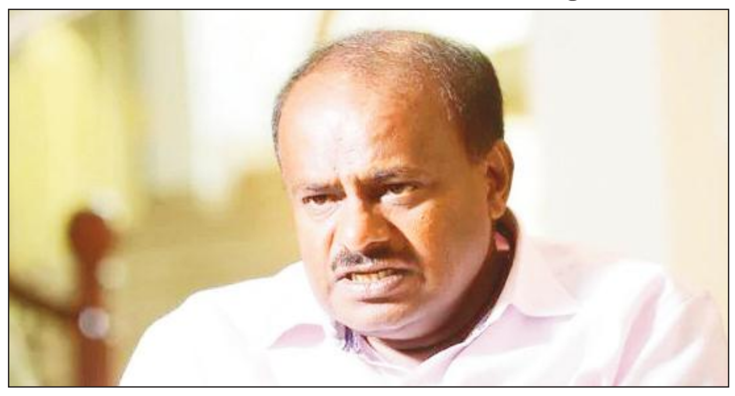

नयी दिल्ली, (भाषा) भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा कि केंद्र सरकार का स्थिर नीतिगत माहौल बनाए रखने पर ध्यान है ताकि घरेलू वाहन कलपुर्जा उद्योग वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को आकार देने में अहम भूमिका निभा सके। कुमारस्वामी ने वाहन कलपुर्जा विनिर्माताओं के संगठन एक्मा के एक कार्यक्रम में कहा कि विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में बढ़ रहे भारत के लिए अगली पीढ़ी की आपूर्ति श्रृंखलाओं में वाहन कलपुर्जा उद्योग केंद्रीय भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा, ''इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, हल्की एवं हल्के वजन वाली सामग्री और बुद्धिमत्ता प्रणाली जैसे क्षेत्रों में नवाचार वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। सरकार स्थिर नीतिगत माहौल देने, प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने और उद्योग के साथ मिलकर पैमाना, गुणवत्ता और निर्यात बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।'' उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य भारतीय विनिर्माताओं को केवल वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदार बनाना ही नहीं, बल्कि उनमें नेतृत्व की भूमिका निभाने के लायक बनाना है। कुमारस्वामी ने व्यापार के मोर्चे पर कहा, ''भारत ने प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ संतुलित और रणनीतिक जुड़ाव अपनाया है। यूरोपीय संघ के साथ समझौता गैर–शुल्क बाधाओं, नियामकीय सहयोग और विशेषकर उत्सर्जन टिकाऊपन और उन्नत वाहन प्रौद्योगिकियों में मानक समन्वय पर केंद्रित है।'' उन्होंने भारत–अमेरिका व्यापार समझौते के तहत चुनिंदा वाहन कलपुर्जों को तरजीही बाजार पहुंच देने संबंधी प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री ने भारतीय वाहन उद्योग को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक बताते हुए कहा कि वाहन उत्पादन 2023–24 के 2.84 करोड़ इकाइयों से बढ़कर 2024–25 में करीब 3.1 करोड़ इकाइयों तक पहुंच गया है। इस दौरान वाहन निर्यात भी 45 लाख से बढ़कर 53 लाख इकाई से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि सरकार दुर्लभ मृदा विनिर्माण और संबंधित गलियारों के निर्माण सहित विभिन्न पहल के जरिये इस क्षेत्र को समर्थन दे रही है। केंद्रीय बजट में निर्माण एवं अवसंरचना उपकरण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है, जिससे भारी इंजीनियरिंग और अवसंरचना विकास को बल मिलेगा।

हरियाणा सरकार सूरजकुंड हादसे के बाद देश की पहली झूला नीति बनाएगी

चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को कहा कि हरियाणा सरकार मेले और झूलों को विनियमित करने के लिए देश की पहली व्यापक नीति तैयार करेगी। यह फैसला फरीदाबाद के सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में पिछले शनिवार को झूला गिरने की घटना के कुछ दिनों बाद लिया गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार पेंडुलम झूला एक तरफ झुक गया और जमीन पर गिर गया। इस हादसे में कम से कम 19 लोग सवार थे। मेले में ड्यूटी पर तैनात निरीक्षक जगदीश प्रसाद (59) की फंसे हुए लोगों को बचाने के प्रयास में मौत हो गयी। इस हादसे में बारह लोग घायल हो गए। सैनी ने पत्रकारों से कहा, ''हमने एक व्यापक नीति बनाने का फैसला किया है, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। यह देश में इस तरह की पहली नीति होगी।'' मुख्यमंत्री ने झूला गिरने के कारणों का पता लगाने के लिए उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और अधिकारियों को मेले एवं अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों को एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता और सभी घायलों के मुफ्त इलाज की भी घोषणा की। हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने निरीक्षक प्रसाद के परिवार के लिए एक करोड़ रुपये के मुआवजे, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और जान गंवाने वाले निरीक्षक को शहीद का दर्जा देने की घोषणा की है। रविवार को झूले के संचालक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया।

सत्तापक्ष व्यवधान पैदा न कर सके, इसलिए बजट पर राहुल ने चर्चा शुरू नहीं कीः सूत्र

नयी दिल्ली, (भाषा) विपक्ष के कई नेता चाहते थे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी बजट पर चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसा करने से सत्तापक्ष की ओर से ''सुनियोजित व्यवधान'' पैदा किया जा सकता है और इससे इस महत्वपूर्ण बहस चर्चा पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, गांधी बुधवार को केंद्रीय बजट पर बोल सकते हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संसद परिसर स्थित कक्ष में हुई विपक्षी नेताओं की बैठक में विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने अपनी रणनीति पर विचार–विमर्श किया। सूत्रों ने बताया कि कई नेताओं की राय थी कि गांधी को ही चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन खुद कांग्रेस नेता ने कहा कि इससे सत्तापक्ष द्वारा जानबूझकर व्यवधान पैदा किया जा सकता है। राहुल गांधी ने जोर दिया कि बजट पर चर्चा बेहद अहम है क्योंकि इससे सभी विपक्षी दलों को जनता से जुड़े मुद्दे उठाने और सरकार को घेरने का अवसर मिलेगा।

बस्तर में अब राष्ट्रवाद के साथ जनजातीय संस्कृति के उत्सव की बयार

छत्तीसगढ़ का बस्तर कभी वामपंथी आतंकवाद के लिए कुख्यात रहा है। अब यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आवाज गूँज रही है और सुनने वालों में पूर्व नक्सली भी थे। 'बस्तर पंडुम' के जरिए माँ दंतेश्वरी की इस पुण्यभूमि की समृद्ध जनजातीय संस्कृति–विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने 7 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के सबसे बड़े उत्सव 'बस्तर पंडुम' का आज जगदलपुर में उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर के लोग जीवन को उत्सव की तरह जीते हैं और यह महोत्सव दुनिया को बस्तर की समृद्ध आदिवासी संस्कृति की झलक देता है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और अन्य मंत्री मौजूद रहे।'बस्तर पंडुम' महोत्सव को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्हें छत्तीसगढ़ आना, अपने घर आने जैसा लगता है। उन्होंने कहा, ''बस्तर की सुंदरता को देखकर लगता है कि माँ दंतेश्वरी ने स्वयं इसे अपने हाथों से सजाया है।'' राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ करते हुए कहा, ''इस वर्ष के पंडुम में पचास हजार से अधिक लोगों द्वारा जनजातीय संस्कृति तथा जीवन–शैली से जुड़े अनेक प्रदर्शन किए जाएँगे। बस्तर की जनजातीय संस्कृति से देशवासियों को अवगत कराने के इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना करती हूं।''राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान माओवाद से मुख्य धारा में लौट रहे बस्तर की सुंदरता की तारीफ की और कहा कि यहाँ विकास का नया सूर्योदय हो रहा है। उन्होंने कहा, ''माओवाद के कारण यहाँ के निवासियों ने अनेक कष्ट झेले। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के युवाओं, आदिवासियों और दलित भाई–बहनों को हुआ। भारत सरकार की माओवादी आतंक पर निर्णायक कार्रवाई के परिणामस्वरूप वर्षों से व्याप्त असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण अब समाप्त हो रहा है। माओवाद से जुड़े लोग हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं जिससे नागरिकों के जीवन में शांति लौट रही है।'' उन्होंने कहा, ''बड़ी संख्या में नक्सलियों ने हथियार छोड़े हैं। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि जो लोग हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटे हैं, वो सामान्य जीवन जी सकें। उनके लिए अनेक विकास और कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार की 'नियद नेल्लानार योजना' ग्रामीणों के सशक्तिकरण में

महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार के प्रयास और इस क्षेत्र के लोगों के सहयोग के बल पर आज बस्तर में विकास का नया सूर्योदय हो रहा है। गाँव–गाँव में बिजली, सड़क, पानी की सुविधा उपलब्ध हो रही है। वर्षों से बंद विद्यालय फिर से खुल रहे हैं और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।'' राष्ट्रपति ने नक्सलवाद छोड़ मुख्यधारा में लौटे लोगों से देश के संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखने की अपील करते हुए कहा, ''यह लोकतंत्र की ताकत ही है कि ओडिशा के एक छोटे से गाँव की यह बेटी, भारत की राष्ट्रपति के रूप में आपको संबोधित कर रही है।'' उन्होंने कहा कि गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों का कल्याण करना सरकार की विशेष प्राथमिकता है। पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे पिछड़ी जनजातियों के गाँवों को विकास से जोड़ा जा रहा है। जानकारों के अनुसार यहाँ बस्तर पंडुम कार्यक्रम में राष्ट्रपति के संबोधन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँचे, जिनमें सरेंडर कर चुके पूर्व नक्सली भी शामिल थे। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद कुछ पूर्व नक्सलियों ने बताया कि वे राष्ट्रपति के विचारों को सुनने और भविष्य को लेकर उनके संदेश को समझने के उद्देश्य से यहाँ आए थे।राष्ट्रपति मुर्मु ने इस दौरान बस्तर की माटी की सुगंध और आदिम जनजातीय परंपराओं को समर्पित भव्य प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान वे कई स्टॉलों पर पहुँचीं और वहाँ मौजूद स्थानीय निवासियों और कारीगरों से कलाओं–उत्पादों के बारे में जानकारी ली। राष्ट्रपति ने ढोकरा हस्तशिल्प कला, टेराकोटा, वुड कार्विंग, सीसल कला, बाँस कला, लौह शिल्प, जनजातीय वेश–भूषा व आभूषण, तुम्बा कला, बस्तर की जनजातीय चित्रकला, स्थानीय व्यंजन और लोक चित्रों पर आधारित स्टॉल्स को देखा।बस्तर पंडुम जनजातीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी में आदिवासी कला और संस्कृति की खूबसूरत झलक देखने को मिली। सबसे खास आकर्षण ढोकरा कला से बनी धातु की वस्तुएँ रहीं। इस कला में एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पहले मोम से आकृति बनाई जाती है और फिर धातु से उसे आकार दिया जाता है। ढोकरा कला भारत की बहुत पुरानी जनजातीय परंपरा है, जिसमें प्रकृति, देवी–देवताओं और गाँव के जीवन से जुड़े दृश्य साफ दिखाई देते हैं। ढोकरा की हर वस्तु पूरी तरह हाथ से बनाई जाती है। इसे बनाने में मिट्टी, मोम, तार, पीतल और भट्टी जैसी चीजों का इस्तेमाल होता है। प्रदर्शनी में मिट्टी से बनी टेराकोटा मूर्तियाँ भी दिखाई गईं। ये मूर्तियाँ लोक आस्था, गाँव के जीवन और पुराने विश्वासों को जीवंत रूप में दिखाती हैं। इन्हें देखकर लगता है जैसे गाँव की संस्कृति सामने आ गई हो। लकड़ी की नक्काशी की कला भी लोगों का ध्यान खींच रही थी। सागौन, साल और दूसरी लकड़ियों से बनी मूर्तियों और आकृतियों में कारीगरों की मेहनत और कल्पना साफ नजर आई। पारंपरिक औजारों से बनाई गई ये कलाकृतियाँ सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को सुंदर तरीके से दर्शाती हैं।'पंडुम' शब्द का अर्थ उत्सव होता है लेकिन बस्तर पंडुम केवल उत्सव भर नहीं है। यह बस्तर की सांस्कृतिक आत्मा, जनजातीय चेतना और सामूहिक जीवन परंपरा का जीवंत प्रतीक बन चुका है। यह आयोजन आज सिर्फ सांस्कृतिक मंच नहीं रहा बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही जनजातीय विरासत को सहेजने और आगे बढ़ाने का एक मजबूत माध्यम बनकर उभरा है।इस वर्ष 'बस्तर पंडुम' का आयोजन तीन चरणों में किया जा रहा है– पहला ग्राम पंचायत स्तर पर, दूसरा विकासखंड एवं जिला स्तर पर और तीसरा संभाग तथा राज्य स्तर पर होने वाले भव्य समापन समारोह के रूप में। इन तीनों चरणों के माध्यम से बस्तर संभाग के दूर–दराज और सुदूर अंचलों में रहने वाले आदिवासी कलाकारों, शिल्पकारों, लोक गायकों और नृत्य दलों को अपनी कला और प्रतिभा प्रदर्शित करने का व्यापक मंच मिलेगा। वहीं, मांदर, ढोल, तिरिया और बांसुरी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज पूरे वातावरण को उत्सव और उल्लास के रंगों से भर देगी, जिससे बस्तर की सांस्कृतिक आत्मा सजीव होकर सामने आएगी।

रामस्वरूप रावतसरे

गुजरात का 'लघु कुंभ': जूनागढ़ के भवनाथ महादेव मंदिर में वार्षिक महाशिवरात्रि मेला शुरू

जूनागढ़, (भाषा) गुजरात के 'लघु कुंभ' के नाम से प्रसिद्ध वार्षिक महाशिवरात्रि मेले की शुरुआत बुधवार को भवनाथ महादेव मंदिर में हुई। इस दौरान शहर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, आध्यात्मिक गुरुओं, संतों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित भव्य समारोह में मंदिर के शिखर पर 55 किलोग्राम का ध्वज फहराया गया, जिसके साथ पांच दिवसीय उत्सव का शुभारंभ हुआ। यह मंदिर गिरनार पर्वत की तलहटी में सुवर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। मंगलवार शाम से ही श्रद्धालुओं का तीर्थनगरी में बड़ी संख्या में आगमन शुरू हो गया था। मेले के मद्देनजर प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। भारदावाव और गिरनार द्वार से वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। मेले में भजन–कीर्तन, सामुदायिक रसोई और देश–विदेश से आए श्रद्धालुओं के लिए भोजन स्टॉल लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों सहित राज्य रिजर्व पुलिस की कंपनियां, होमगार्ड और ग्राम रक्षक दल के जवानों समेत करीब 3,500 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। मेला क्षेत्र को पांच क्षेत्रोंदामोदर कुंड, रुपायतन, भवनाथ, गिरनार और सिटी क्षेत्र में विभाजित किया गया है। करीब 570 सीसीटीवी कैमरे और निगरानी टावर लगाए गए हैं। निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और भवनाथ पुलिस थाने में एक समर्पित नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि बम निरोधक दस्ता, श्वान दस्ता और त्वरित प्रतिक्रिया दल भी अलर्ट पर हैं। पहली बार 800 स्वयंसेवक भीड़ प्रबंधन में पुलिस की सहायता कर रहे हैं। पार्किंग स्थलों की संख्या आठ से बढ़ाकर 24 कर दी गई है, जबकि 108 एंबुलेंस, चिकित्सा दल, दमकल वाहन और बचाव दल को रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया है। जूनागढ़ कलेक्टर अनिल कुमार राणावसिया और पुलिस अधीक्षक सुबोध ओदेदरा ने मंगलवार को अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

भारत और थाईलैंड की वायुसेनाएं आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए संयुक्त अभ्यास कर रहीं

नयी दिल्ली, (भाषा) रॉयल थाई वायुसेना और भारतीय वायुसेना आपसी समन्वय और तालमेल को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त अभ्यास में हिस्सा ले रही हैं जिसमें भारत के लड़ाकू विमान एसयू–30 एमकेआई के अलावा ईंधन भरने वाला विमान आईएल–78 और अन्य महत्वपूर्ण साजो–सामान को शामिल किया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप: आकृति ने रजत, अंजुम ने कांस्य जीता

नयी दिल्ली, (भाषा) भारत की आकृति दहिया और अंजुम मौदगिल ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन (3पी) स्पर्धा में मंगलवार को यहां क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में कजाकिस्तान की सोफिया शुलझेंको ने कर्णी सिंह परिसर में नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सोफिया ने 35 शॉट के फाइनल में 358.2 अंक हासिल किए, जो रजत पदक विजेता आकृति दहिया से चार अंक अधिक थे। विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता अंजुम मौदगिल ने 340.4 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। सोफिया के इस स्कोर के साथ तीन नये रिकॉर्ड विश्व जूनियर, एशियाई और एशियाई जूनियर कायम किये। जूनियर महिलाओं की 3पी स्पर्धा में भारत की प्राची गायकवाड़ ने 353.3 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। 14 वर्षीय कजाकिस्तान की निशानेबाज टोमिरिस अमानोवा ने 351.4 अंक के साथ रजत पदक हासिल किया, जबकि भारत की अनुष्का ठाकुर ने 341.1 अंक के साथ कांस्य पदक जीता।

प्राची, अनुष्का और हेजल की तिकड़ी ने टीम स्पर्धा में 1748 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता, जो कजाकिस्तान से सात अंक अधिक था। सीनियर महिला 3पी टीम स्पर्धा में कजाकिस्तान ने 1760 अंकों के साथ भारत को चार अंकों से पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में भारत के आदर्श सिंह ने प्रिसीजन चरण के बाद 291 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। अनीश भानवाला 287 अंकों के साथ फाइनल की दौड़ में बने हुए हैं, जबकि नीरज कुमार के नाम 277 अंक है। उन्हें फाइनल की दौड़ में शामिल होने के लिए बुधवार को बेहतर प्रदर्शन की जरूरत होगी। टूर्नामेंट में भारत 39 स्वर्ण, 15 रजत और 12 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है।

सूर्य भाई और मैं जरूरत पड़ने पर सूत्रधार की भूमिका निभा सकते हैं: तिलक वर्मा

नयी दिल्ली, (भाषा) अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर तिलक वर्मा ने बुधवार को यहां कहा कि मौजूदा टी20 विश्व कप में जरूरत पड़ने पर वह भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ पारी के सूत्रधार की भूमिका निभा सकते हैं। चोट से उबरने के बाद तिलक वर्मा ने आईसीसी टूर्नामेंट से पहले भारतीय टीम में सफल वापसी की है। भारत ने सात फरवरी को अमेरिका के खिलाफ टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में छह विकेट जल्दी गंवा दिए थे लेकिन बाद में वापसी करते हुए आराम से जीत दर्ज की। नामीबिया के खिलाफ मैच की पूर्व संध्या पर तिलक ने कहा, ''मुख्य कोच (गौतम गंभीर) ने हमसे कहा है कि अगर अमेरिका के खिलाफ हुए मैच की तरह विकेट जल्दी–जल्दी गिरें तो हमें सावधानी से खेलना चाहिए। जरूरत पड़ने पर सूर्यकुमार भाई और मैं सूत्रधार की भूमिका निभा सकते हैं। '' उन्होंने यह भी बताया कि स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बृहस्पतिवार को होने वाले मुकाबले के लिए फिट हैं जो पहला मैच नहीं खेल पाए थे। उन्होंने कहा, ''जसप्रीत बुमराह फिट हैं और नामीबिया के खिलाफ कल के मैच के लिए उपलब्ध हैं। '' कोलंबो में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मुकाबले पर तिलक ने कहा, ''हम एक समय में एक मैच पर ही ध्यान दे रहे हैं। हम श्रीलंका की परिस्थितियों और मैच के लिए तैयार हैं। '' तिलक ने अभ्यास मुकाबलों में शानदार वापसी की जिसमें उन्होंने अमेरिका के खिलाफ 24 गेंद में 38 रन और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 19 गेंद में 48 रन बनाकर अपनी फॉर्म और तैयारी दिखाई।

बुमराह का यॉर्कर किशन के बायें पैर पर लगा, अभिषेक की जगह खेलने को तैयार संजू

नयी दिल्ली, (भाषा) ईशान किशन ने बुधवार को नेट अभ्यास पर अपना जबर्दस्त फॉर्म बरकरार रखा लेकिन बाद में जसप्रीत बुमराह का यॉर्कर उनके बायें पैर पर लगा । बुमराह ने लगातार दूसरे दिन जमकर गेंदबाजी का अभ्यास किया । वह अमेरिका के खिलाफ पहला मैच नहीं खेले थे । किशन गेंद लगने के बाद नेट्स से चले गए । वह बाद में बल्लेबाजी के लिये आये लेकिन ज्यादा देर बल्लेबाजी नहीं की । नामीबिया के खिलाफ बृहस्पतिवार को बुमराह का खेलना तय लग रहा है । यह मैच पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को कोलंबो में होने वाले मुकाबले की तैयारी के लिये अहम है । बुमराह ने गेंदबाजी के बाद कैचिंग का भी अभ्यास किया । खराब फॉर्म के कारण टीम से बाहर संजू सैमसन को अभिषेक शर्मा के नहीं खेलने पर मौका मिल सकता है । अभिषेक पेट में संक्रमण के कारण दो दिन अस्पताल में थे हालांकि उन्हें आज छुट्टी मिल गई । संजू बल्लेबाजी का अभ्यास करने सबसे पहले आने वालों में थे । वॉशिंगटन सुंदर ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी की जबकि सूर्यकुमार यादव के साथ डीडीसीए अधिकारियों ने खूब सेल्फी खिंचवाई । कुलदीप यादव और रिंकू सिंह के साथ भी डीडीसीए अधिकारियों और उनके परिवारों ने सेल्फी ली ।

इसे बयां करने के लिए शब्द भी नहीं हैं, बस खुशी है कि हम जीत गए: रिकेल्टन

अहमदाबाद, (भाषा) दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर–बल्लेबाज रेयान रिकेल्टन को दो सुपर ओवर के बाद अफगानिस्तान पर रोमांचक टी20 विश्व कप मैच में मिली जीत को बयां के लिये शब्द नहीं मिल रहे थे और उन्होंने कहा कि आखिर में जीत हासिल करके खुश हैं। दक्षिण अफ्रीका एक यादगार मैच में दो उतार–चढ़ाव वाले सुपर ओवर के बाद अफगानिस्तान को हराने में कामयाब रहा। रिकेल्टन (28 गेंद में 61 रन) और क्विंटन डिकॉक (41 गेंद में 59 रन) ने अर्धशतक बनाने के साथ शानदार शतकीय साझेदारी की जिससे दक्षिण अफ्रीका ग्रुप डी मैच में छह विकेट पर 187 रन बनाने में कामयाब रहा। अफगानिस्तान ने इस स्कोर की बराबरी की। फिर पहले सुपर में भी बराबर रही लेकिन दूसरे ओवर में दक्षिण अफ्रीका जीत गया। रिकेल्टन ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ''पहला ख्याल आता है कि क्रिकेट खराब खेल है। निश्चित रूप से यह एक रोमांचक मैच था। मेरे पास इसे बताने के लिए ज्यादा शब्द नहीं हैं। आखिर में हम जीत गए, इससे बहुत खुश हूं। ''

इस तरह की हार लंबे समय तक चुभती है, कहा अफगानिस्तान के कोच ट्रॉट ने

अहमदाबाद, (भाषा) अफगानिस्तान के कोच जोनाथन ट्रॉट ने टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका से दूसरे सुपर ओवर में मिली हार के बाद कहा कि इस तरह की हार लंबे समय तक चुभती है लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि दक्षिण अफ्रीका ने क्षेत्ररक्षण में उनकी टीम को कमजोर साबित किया । टी20 विश्व कप के इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक में दक्षिण अफ्रीका ने दो सुपर ओवर के बाद अफगानिस्तान को हराया । ट्रॉट ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,'' इससे साबित होता है कि हमारे पास कितनी शानदार टीम है । हमारे पास कुछ बेहतरीन खिलाड़ी हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ दिन पहले मिली हार के बाद दक्षिण अफ्रीका से करीबी मुकाबला हारना दिल तोड़ने वाला है । हमें कठिन ग्रुप भी मिला है ।'' दक्षिण अफ्रीका में जन्मे इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ट्रॉट ने कहा कि इस तरह की हार लंबे समय तक चुभती है । उन्होंने कहा ,'' टीम को अपने प्रदर्शन पर गर्व होना चाहिये लेकिन कई बार इस तरह की हार लंबे समय तक चुभती है । अब अहम यह है कि हम इसके सकारात्मक पहलुओं को देखें और यह भी प्रयास करें कि जहां गलतियां हुई हैं, उनमें सुधार हो ।'' ट्रॉट ने कहा ,'' दक्षिण अफ्रीका की फील्डिंग बहुत अच्छी थी । रन आउट, सीमा पर कैच और रन बचाने के प्रयास । जबर्दस्त फील्डिंग और शायद यही फर्क था ।'' ट्रॉट के कोच रहते अफगानिस्तान पिछले टी20 विश्व कप सेमीफाइनल और 2023 वनडे विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी । इस विश्व कप के बाद वह टीम से विदा ले रहे हैं लेकिन अभी इस बारे में उन्होंने कुछ कहने से इनकार किया । उन्होंने कहा ,'' टूर्नामेंट खत्म होने के बाद इस पर बात करेंगे । अभी दो अहम मैच खेलने हैं । अभी कुछ और बात करने का समय नहीं है । मैं अभी भी कोच हूं और मुझे यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में यूएई के खिलाफ हम अच्छा खेलें ।''

रदरफोर्ड और मोती ने वेस्टइंडीज को इंग्लैंड पर दिलाई शानदार जीत

मुंबई, (भाषा) शेरफेन रदरफोर्ड के नाबाद 76 रन और गुडाकेश मोती के तीन विकेट की मदद से वेस्टइंडीज ने बुधवार को टी20 विश्व कप के ग्रुप सी के अहम मुकाबले में इंग्लैंड को 30 रन से हरा दिया । रदरफोर्ड ने चिर परिचित कैरेबियाई अंदाज में खेलते हुए 42 गेंद में पांच छक्कों और दो चौकों की मदद से नाबाद 76 रन बनाकर वानखेड़े स्टेडियम पर मौजूद करीब 21000 दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया । वहीं मोती ने गेंदबाजी में 32 रन देकर तीन विकेट चटकाये । जीत के लिये 197 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 19 ओवर में 166 रन पर आउट हो गई । सैम कुरेन ने सर्वाधिक 43 रन की नाबाद पारी खेली । फिल साल्ट ने 14 गेंद में 30 रन बनाये जिसमें चार चौके और दो छक्के शामिल थे । उन्होंने जैसन होल्डर के दूसरे ओवर में 24 रन निकाले । साल्ट को रोमारियो शेफर्ड ने कवर में रदरफोर्ड के हाथों लपकवाया । पावरप्ले के बाद इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट पर 67 रन था । जोस बटलर (21) भी ज्यादा देर टिक नहीं सके । वह रोस्टन चेस की गेंद पर लांग आन में पॉवेल को कैच देकर लौटे । इसके बाद मोती ने इंग्लैंड को दोहरे झटके दिये । पहले उन्होंने टॉम बेंटोन (दो) को कवर में कैच आउट कराया और इसके बाद जैकब बेथेल (33) को चाइनामैन गेंद पर आउट किया । इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक (17) मोती को रिटर्न कैच देकर लौटे । इससे पहले रदरफोर्ड के नाबाद 76 रन की मदद से वेस्टइंडीज ने खराब शुरूआत से उबरते हुए छह विकेट पर 196 रन बनाये । वेस्टइंडीज ने दस ओवर के बाद 79 रन पर चार विकेट गंवा दिये थे । लेकिन आखिरी दस ओवर में 117 रन बने । रदरफोर्ड ने पांचवें विकेट के लिये रोवमैन पॉवेल (14) के साथ 51 रन की साझेदारी की । इसके बाद पूर्व कप्तान जैसन होल्डर (17 गेंद में चार छक्कों, एक चौके की मदद से 33 रन) के साथ छठे विकेट के लिये 32 रन जोड़े । टेस्ट कप्तान रोस्टन चेस ने चौथे नंबर पर उतरकर 34 रन बनाये । होल्डर ने आखिरी ओवरों में सैम कुरेन को एक ही ओवर में तीन छक्के लगाये । रदरफोर्ड को 18वें ओवर में आदिल रशीद ने जीवनदान दिया था । होल्डर ने आतिशी पारी खेलकर रदरफोर्ड पर से दबाव कम किया । पिछले मैच में नेपाल के बल्लेबाजों से नसीहत पाने वाले रशीद ने मजबूती से वापिस की और 16 रन देकर दो विकेट चटकाये । वेस्टइंडीज की शुरूआत खराब रही और दो विकेट आठ रन पर ही गिर गए । कप्तान शाइ होप ने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर कवर प्वाइंट पर टॉम बेंटोन को कैच थमाया जबकि कुरेन ने ब्रेंडन किंग को स्वीपर कवर में लपकवाया । चेस ने पांचवें ओवर में विल जैक्स को लगातार तीन चौके लगाये जबकि शिमरोन हेटमायेर ने एक छक्का जड़ा । जैमी ओवर्टन ने 33 रन देकर दो विकेट चटकाये । उन्होंने हेटमायेर (23) का विकेट भी चटकाया जिन्होंने शॉर्ट फाइनल लेग पर कुरेन को कैच दिया ।

कोलंबो में भारत–पाक मुकाबले पर तिलक ने कहा, हम तैयार हैं

नयी दिल्ली, (भाषा) भारत के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने बुधवार को यहां कहा कि टीम 15 फरवरी को टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए उत्साहित हैं। पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और अन्य सदस्य देशों के दबाव के बाद कोलंबो में भारत के खिलाफ मुकाबले के बहिष्कार पर 'यू–टर्न' लेकर खेलने का फैसला किया।तिलक ने कहा, ''सच कहूं तो हम इस मैच में खेलने को लेकर बहुत उत्साहित हैं। हमें कल पता चला कि मैच होने वाला है। हम खेलने के लिए तैयार हैं। हम सभी टीमों पर नजर रखे हैं। हम गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को देख रहे हैं। '' उन्होंने कहा, ''सभी खिलाड़ी और टीम के सदस्य खेलने के लिए तैयार हैं। अब हम 'मैच जोन' में हैं। योजना शुरू होगी। '' भारत के सहायक कोच रयान टेन डोएशे ने कहा था कि पाकिस्तान को कुछ फायदा हो सकता है क्योंकि वे कुछ समय से श्रीलंका में ही हैं और अपने सभी मैच वहीं खेलेंगे। तिलक ने मैच के बारे में आगे कहा, ''हम एक बार में एक मैच पर ही ध्यान लगा रहे हैं तो देखेंगे। हमारे पास वीडियो विश्लेषण और तकनीक है, तो हम देखेंगे कि हम कैसे खेल रहे हैं। विकेट किस तरह बर्ताव कर रहा है। हम तैयार हैं। हर टीम के खिलाड़ी अलग–अलग तरह के शॉट खेलते हैं। हमें कौन से शॉट इस विकेट पर खेलने हैं और किन गेंदबाजों को कैसे खेलना है, उसकी योजना पहले से तैयार है। ''

एएफसी ने भारत और हांगकांग के 2027 एशियाई कप क्वालीफायर के स्थल के लिए रांची को खारिज किया

नयी दिल्ली, (भाषा) एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) ने 31 मार्च को भारत और हांगकांग के बीच होने वाले 2027 एशियाई कप क्वालीफायर मैच के लिए रांची को आयोजन स्थल के रूप में खारिज कर दिया है क्योंकि यह स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की मेजबानी के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे के मानकों को पूरा नहीं करता है। अब इस मैच की मेजबानी के लिए सबसे संभावित विकल्प केरल का कोच्चि है। भारतीय टीम पहले ही पिछले साल खराब प्रदर्शन के कारण 2027 एशियाई कप मुख्य टूर्नामेंट में प्रवेश के दावेदारों से बाहर हो चुकी है। फुटबॉल को नए स्थानों और छोटे शहरों तक पहुंचाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में भारत बनाम हांगकांग मैच आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था। एआईएफएफ के शीर्ष सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा, ''हां, एएफसी को अंतरराष्ट्रीय मैच की मेजबानी के लिए रांची स्टेडियम में जरूरी बुनियादी ढांचे (ड्रेसिंग रूम में सुविधाएं जिसमें वॉशरूम की कमी) की कमी मिली है। अब कोच्चि के नाम पर विचार किया जा रहा है। ''

जोहेब को 'टीम कल्याण संबंधी मुद्दों' के कारण यूएई टीम से हटाया गया, हैदर चुने गए

दुबई, (भाषा) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की तकनीकी समिति ने टी20 विश्व कप के लिए मोहम्मद जोहेब के स्थान पर हैदर शाह को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) टीम में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। आईसीसी की बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति में इसके कारण को विस्तार से बताए बिना कहा, ''16 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले हैदर को तब नामित किया गया जब जोहेब को खिलाड़ी की मानसिक स्वास्थ्य और टीम कल्याण संबंधी मुद्दों के कारण टीम से हटाया गया। '' किसी खिलाड़ी को बदलने के लिए टूर्नामेंट की तकनीकी समिति की मंजूरी जरूरी होती है तभी खिलाड़ी को आधिकारिक रूप से टीम में जोड़ा जा सकता है। तकनीकी समिति में वसीम खान, गौरव सक्सेना हेमांग अमीन और शॉन पोलाक शामिल हैं।

पेट में संक्रमण से जूझ रहे अभिषेक शर्मा को दो दिन बाद अस्पताल से मिली छुट्टी

नयी दिल्ली, (भाषा) भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पेट में संक्रमण के कारण दो दिन अस्पताल रहने के बाद छुट्टी मिल गई है लेकिन नामीबिया के खिलाफ बृहस्पतिवार को यहां होने वाले टी20 विश्व कप क्रिकेट मैच में उनका खेलना संदिग्ध है। मैच से पूर्व प्रेस कांफ्रेंस में भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा ने कहा कि अभिषेक के कल खेलने को लेकर अभी फैसला नहीं लिया गया है । तिलक ने पत्रकारों से कहा ,'' जब हम दिल्ली पहुंचे तो वह चेकअप के लिये अस्पताल गया था । उसे आज छुट्टी मिल गई है और वह ठीक है । मैच में अभी भी एक दिन का समय है । उम्मीद है कि कल इस पर फैसला लेंगे । देखना होगा कि वह कैसा महसूस कर रहा है ।'' अभिषेक अमेरिका के खिलाफ शनिवार को मुंबई में खेले गए पहले मैच में पहली गेंद पर आउट हो गए थे और इसके बाद उन्होंने इस मैच में आगे हिस्सा नहीं लिया था। उनकी जगह संजू सैमसन ने फील्डिंग की थी। समझा जाता है कि मैच के दौरान उनकी तबीयत खराब थी और दिल्ली पहुंचने के बाद और बिगड़ गई । भारत की प्राथमिकता नामीबिया के खिलाफ मैच नहीं है, बल्कि 15 फरवरी को कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला मैच है, जहां पिच थोड़ी अलग होगी। पाकिस्तान ने अभी तक अपने दोनों मैच जीते हैं। पेट के संक्रमण से दमखम और सहनशक्ति पर असर पड़ता है और यह देखना बाकी है कि क्या अभिषेक शुक्रवार को यात्रा करने, शनिवार को अभ्यास करने और रविवार को मैदान में उतरने की स्थिति में होंगे। सैमसन ने मंगलवार को यहां नेट पर बल्लेबाजी की और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक के साथ काफी समय बिताया, जो इस बात का संकेत है कि टीम प्रबंधन अभिषेक के पूरी तरह से फिट न होने की स्थिति में अपने विकल्प तैयार रख रहा है। भारतीय टीम प्रबंधन को हालांकि 25 वर्षीय अभिषेक के 15 फरवरी तक पूरी तरह फिट होने की उम्मीद है। अभिषेक रविवार को मुख्य कोच गौतम गंभीर के घर पर आयोजित रात्रिभोज में शामिल हुए थे लेकिन वह अपने बाकी साथियों से काफी पहले ही वहां से चले गए थे।

चेन्नई ओपन : एकल में शीर्ष वरीय जे क्लार्क बाहर

चेन्नई, (भाषा) ब्रिटेन के शीर्ष वरीय जे क्लार्क बुधवार को यहां चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर पुरुष अंतरराष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप में इयोनिस जिलास से हारकर एकल वर्ग के पहले दौर में ही बाहर हो गए ।युगल में शीर्ष दो वरीयता प्राप्त जोड़ियां क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं जिसमें निकी पूनाचा और प्रूच्या इसारो तथा साकेत माइनेनी और सिद्धांत बांठिया की जोड़ियां शामिल हैं। एटीपी रैंकिंग में 183वें नंबर पर काबिज क्लार्क को जिलास से 4–6, 4–6 से हार मिली। पहले दौर के एक और एकल मैच में भारतीय क्वालीफायर आर्यन लक्ष्मणन को पोलैंड के मैक्स कास्निकोवस्की से 5–7, 2–6 से हार मिली। दूसरे दौर के एकल मुकाबले में भारत के मुकुंद शशिकुमार ने पहला सेट जीता, लेकिन कजाखस्तान के डेनिस येवसेयेव से 6–3, 2–6, 3–6 से हार गए। युगल में पूनाचा और इसारो की शीर्ष वरीय जोड़ी ने हमवतन कार्तिक रेड्डी गंटा और दिग्विजयप्रताप सिंह की जोड़ी को 6–4, 6–2 से हराकर आखिरी आठ में जगह बनाई। माइनेनी और बांठिया की दूसरी वरीय जोड़ी ने एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए येवसेयेव और एरिक वैनशेलबोइम को टाई ब्रेक में 2–6, 6–1, 10–2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत की दो और जोड़ियां भी आखिरी आठ में पहुंच गईं। लोहितक्षा बथ्रीनाथ और अभिनव संजीव शनमुगम ने हमवतन मानस धामने और अथर्व शर्मा को 6–3, 2–6, 10–8 से हराया। इशाक इकबाल और मनीष सुरेशकुमार ने राघव जयसिंघानी और कार्ल होल्डर की जोड़ी को 3–6, 6–1, 10–3 से मात दी।

एफआईएच पुरूष प्रो लीग के पहले मैच में बेल्जियम से हारी भारतीय टीम

राउरकेला, (भाषा) आखिरी क्वार्टर में दो गोल गंवाने से भारत को एफआईएच पुरूष प्रो लीग 2025 . 26 के राउरकेला चरण में पहले मैच में बुधवार को बेल्जियम ने 3 . 1 से हराया । बेल्जियम के लिये नेल्सन ओनाना (23वां मिनट), थॉमस क्रोल्स (53वां) और अर्नो वान डेसेल (57वां) ने गोल किये जबकि भारत के लिये एकमात्र गोल शिलानंद लाकड़ा (29वां) ने दागा । हाफटाइम और तीसरे क्वार्टर के अंत तक स्कोर 1 . 1 से हराकर था लेकिन बेल्जियम ने आखिरी 15 मिनट में दो गोल कर दिये । पहले क्वार्टर में दोनों टीमों ने डिफेंस में कोई गलती नहीं की । बेल्जियम को चौथे मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन अलेक्जेंडर हेंडरिक्स की ड्रैग फ्लिक को भारत के पहले रशर विवेक सागर प्रसाद ने बचाया । भारत को चार मिनट बाद मिला पेनल्टी कॉर्नर बेकार गया । बेल्जियम ने गेंद पर नियंत्रण में बाजी मारी लेकिन भारत ने अधिक जवाबी हमले किये । बेल्जियम को 14वें मिनट में फिर पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन टॉम बून का शॉट बाहर से निकल गया । दूसरे क्वार्टर में बेल्जियम ने 21वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर बनाया जिस पर हेंडरिक्स का शॉट भारतीय गोलकीपर पवन ने शानदार तरीके से बचाया । इसके कुछ मिनट बाद पवन ने एक और गोल बचाया । बेल्जियम के लिये पहला गोल 23वें मिनट में क्रोल्स के पास पर ओनाना ने किया । भारत ने जवाबी हमले में 29वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर बनाया जिस पर लाकड़ा ने गोल किया । तीसरे क्वार्टर तक स्कोर बराबर था लेकिन आखिरी क्वार्टर में क्रोल्स और डेसेल के गोल के दम पर बेल्जियम ने जीत दर्ज की ।

अनीश ने रैपिड फायर पिस्टल में कांस्य जीता, कजाखस्तान को चार स्वर्ण

नयी दिल्ली, 11 फरवरी (भाषा) विश्व चैम्पियनशिप रजत पदक विजेता अनीश भानवाला ने एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप में पुरूषों की 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता जबकि आठवें दिन कजाखस्तान का दबदबा रहा । अनीश का एशियाई चैम्पियनशिप में यह तीसरा पदक है । एड्रियन कर्माकर ने 50 मीटर राइफल प्रोन जूनियर पुरूष वर्ग में और जूनियर पुरूष 25 मीटर आरएफपी में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता । भारत के अब 41 स्वर्ण, 19 रजत और 15 कांस्य पदक हो गए हैं जबकि स्पर्धा के दो दिन बाकी हैं । अनीश और आदर्श सिंह क्वालीफाइंग दौर में सातवें और आठवें स्थान पर रहे थे । कजाखस्तान के पूर्व चैम्पियन निकिता चिरयुकिन क्वालीफायर में शीर्ष रहे । फाइनल में आदर्श चौथी सीरिज के बाद बाहर हो गए जबकि अनीश , निकिता और जापान के दाइ योशिओका संयुक्त बढत पर थे ।

पता नहीं क्यों, हमें दूधिया रोशनी में ट्रेनिंग सत्र नहीं दिया गया: नामीबिया के कप्तान

नयी दिल्ली, (भाषा) नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने बुधवार को आयोजकों पर हल्का तंज कसा कि उन्हें भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच से पहले रात में दूधिया रोशनी में ट्रेनिंग नहीं करने दी।नामीबिया ने सोमवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ दिन का मैच खेला था और अगले दो दिन उनके दोनों ट्रेनिंग सत्र केवल दिन में रखे गए। इसके विपरीत भारत ने मैच से पहले दो बार रात में अभ्यास किया। नामीबिया के पास स्वदेश में दिन–रात्रि मैच के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं है तो वे भारत के खिलाफ बृहस्पतिवार को होने वाले मैच से पहले दूधिया रोशनी में कुछ अभ्यास करना पसंद करते। इरास्मस ने कहा, ''हां, हमें इस मैच से पहले रात का ट्रेनिंग सत्र नहीं दिया गया, मुझे नहीं पता क्यों। भारत को शायद दो रात के सत्र दिए गए और अब बाहर देख रहा हूं कि कनाडा को अब रात का ट्रेनिंग सत्र मिलेगा। आप इसका मतलब जो समझें, लेकिन हम अपनी नामीबियाई शैली में आएंगे जो चुनौती से लड़ना है। '' कनाडा शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ दोपहर का मैच खेलेगा। उसने फिरोजशाह कोटला मैदान में भारतीय टीम के साथ अभ्यास किया। इरास्मस ने कहा, ''हमारे पास दिन रात्रि मैच के लिए नामीबिया में दूधिया रोशनी नहीं है। बुनियादी ढांचे के हिसाब से यह हमारे लिए चुनौती है। उन खिलाड़ियों के लिए जिनके पास अनुभव नहीं है, उनके लिए यह आम बात नहीं है। '' उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि नेपाल प्रीमियर लीग, आईएलटी20 और हमने जो विश्व कप खेले हैं, उन्हें छोड़कर ज्यादातर खिलाड़ी दूधिया रोशनी के नीचे ट्रेनिंग करने के अभ्यस्त नहीं होते। '' नामीबिया अपने पहले मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ हार गया था। और अब बचे हुए लीग मैच अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। ये दोनों मैच दोपहर तीन बजे शुरू होंगे।

वैश्विक भरोसे का प्रतीक भारतवर्ष

भारतवर्ष कभी किसी देश पर आक्रमण करना नहीं चाहता और ना ही भारत कभी विश्व विजय की बात करता है। भारतवर्ष हमेशा विश्व के एकीकरण की बात करता है अर्थात विश्वबंधुत्व की बात करता है। वह सभी को एक साथ लेकर चलने की बात करता है। भारत स्वयं में एक विश्व है क्योंकि यहां की जो संस्कृति है, वह अपने आप में बहुत बड़ी है। हमने अपनी शुरुआती शिक्षा से ही सुना है कि भारत सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया का अर्थ धीरे–धीरे हमारी समझ में आया अर्थात भारत धन–धान्य से संपन्न और एक शांतिप्रिय देश रहा है। हमने किसी भी पड़ोसी देश पर या किसी टापू पर अपना अधिकार या कहीं स्वामित्व स्थापित नहीं किया और ना हमने कभी करने की सोची। हमने सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, अतिथि देवो भव का विचार हमने हमेशा अपने अंदर रखा है।हमारे देश की हर एक व्यवस्था हमें दुनिया से अलग और बहुत समृद्ध तथा संपन्न बनती है। यहां ऋतु चक्र के चलते अलग–अलग फैसलें, फल, फूल, सब्जियां आदि हमें मिलते रहते हैं। ऋतु चक्र के चलते ही हमारे अलग–अलग तीज–त्योहार हमारे अंदर संचार भर देते हैं। दुनिया का सबसे सुंदर सुखद यह देश अपने में अद्भुत है। यहां पर हर समय लोग आनंद उत्साह और नवसंचार के साथ रहते हैं। ऋतु चक्र के चलतेप्रकृति का बदलता स्वरूप, खान–पान, वेशभूषा आदि पर भी प्रभाव डालता है। बदलते मौसम चक्र के चलते व्यापार को भी अलग–अलग अंदाज में चलाया जाता है। यहां कोई स्थिरता या रुकावट नहीं है। चरैवेति चरैवेति का सिद्धांत हमारे यहां सभी अपनाते हैं। मौसम चक्र के साथ ही हमारे घूमने फिरने के स्थान भी बदल जाते हैं। हमारी संस्कृति विश्व की सबसे सुंदर और शांतिप्रिय है।

हमारी संस्कृति हमारा आभूषण है। हमारी संस्कृति, समाज, ऋतु चक्र, तीर्थ, पूजा–पाठ आदि सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इन सभी व्यवस्थाओं के चलते हमारा व्यापार, रोजगार, काम–धंधे आदि सभी कुछ अलग–अलग अंदाज में वर्ष भर चलते रहते हैं। यहां कभी कोई काम रुकता नहीं है। इसलिए हम सोने की चिड़िया कहे गए हैं। यहां पर हर समय लोगों को काम करने की आदत है जबकि विश्व के कितने ही देशों में एक ही ऋतु है और लोग उसी मौसम की मार झेलते रहते हैं। वहां कभी अलग–अलग अन्न धन होना संभव नहीं है। वहां तीज त्यौहार गिने चुने हैं, इसलिए लोगों में उत्साह कम नजर आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतवर्ष में परिवार के प्रति एक गहरा लगाव है। जबकि बहुत से देश में पारिवारिक व्यवस्था केवल नाम के लिए है। जब परिवार, समाज, संस्कृति, उत्सव कम होंगे तो स्वाभाविक है कि ऐसे देश की सोच और मानसिकता भी बहुत छोटी और अमानवीय ही होगी। चाहे वह अपने को धन संपन्न माने या कहते रहे, लेकिन यह धन किस काम का है। अपनी धन क्षमता के कारण ही इन विकसित देशों ने ही दो बड़े विश्व युद्ध को जन्म दे दिया। केवल अपने को बड़ा दिखाने के लिए और विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कहलाए जाने वाले अमेरिका ने तो मानवीयता का सबसे घिनौना प्रहार जापान पर किया। उसके दो शहरों को परमाणु शक्ति के प्रहार सेमिटा दिया। ऐसी विकसित अर्थव्यवस्था या ऐसे धन–धान्य का क्या लाभ? जो मानवीयता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाए?जिन देशों में धूप के लिए लोग तरसते हों, जो केवल एक ही ऋतु में रहते हो, वह अपने को कैसे विकसित और धन संपदा से भरे देश का सकते हैं? यह केवल एक मानसिकता है, यदि यह देश सभी चीजों से संपन्न होते तो दूसरे देशों पर आक्रमण क्यों करते हैं? क्यों संपूर्ण मानवता को बार–बार खतरे में डालते हैं? पूरी पृथ्वी की पर्यावरणव्यवस्था को खराब कर देते हैं और जाने कितना ही प्रदूषण फैला रहे हैं? सभी जीव खतरे में नजर आ रहे हैं। युद्ध कभी किसी को कुछ नहीं देते, यह केवल विनाश का रास्ता है। आज भारत को छोड़ बहुत सारे यूरोपीय और अन्य देश तीसरे विश्व युद्ध का खतरा झेलने के लिए खड़े हैं। एक बार फिर मानवता पर प्रहार किया जा रहा है।अब विश्व ऐसे महाविनास और युद्धों से बचना चाहता है।

उप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई के अन्तर्गत 250 शैय्या वाले लेवल–1 ट्रॉमा सेण्टर आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे के समीप स्थापित किया जाएगा : सीएम योगी

लखनऊ। फोकस न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई (इटावा) के अन्तर्गत 250 शैय्या वाले लेवल–1 ट्रॉमा सेण्टर की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया है। यह ट्रॉमा सेण्टर आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे के समीप स्थापित किया जाएगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं सहित अन्य आपात परिस्थितियों में घायलों को त्वरित एवं उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री लोक भवन में बतौर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की दूसरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे विश्वविद्यालय परिसर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके कारण दुर्घटना पीड़ितों के उपचार में बहुमूल्य समय नष्ट होता है। प्रस्तावित ट्रॉमा सेण्टर का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में 'सेण्टर फॉर रूरल हेल्थ' की स्थापना के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए, जिसमें टेली ओ0पी0डी0, वर्चुअल ओ0पी0डी0, डिजिटल डेटा एकीकरण तथा मोबाइल आउटरीच जैसी सेवाएं शामिल हों। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान को नई दिशा देने से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई को पश्चिमी एवं मध्य उत्तर प्रदेश के लिए उच्चस्तरीय चिकित्सा, शिक्षण एवं शोध के प्रभावी केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए। उपचार, शिक्षण और अनुसंधान के प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्ता, संवेदनशीलता तथा समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में नवाचारों को प्राथमिकता देने पर बल देते हुए कहा कि देश के अग्रणी चिकित्सा एवं शैक्षणिक संस्थानों की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों (बेस्ट प्रैक्टिसेज) का अध्ययन कर उन्हें विश्वविद्यालय की व्यवस्था में समाहित किया जाए। विश्वविद्यालय से समाज की उच्च अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं, जिनकी पूर्ति के लिए हब–एण्ड–स्पोक मॉडल को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, ताकि सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में समग्र सुधार हो सके।

उप्र सरकार ने बजट में नागर विमानन क्षेत्र के लिए 2,111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया

लखनऊ, (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को विधानसभा में पेश किए गए 2026–27 के बजट में परिवहन और नागर विमानन क्षेत्र के मद में उदारता दिखाई है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को प्रस्तावित बजट पेश करते हुए कहा कि बस बेडे के सुदृढ़ीकरण को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के लिए 400 करोड़ रुपये तथा बस अड्डा निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जीरो फैटलिटी विजन योजना दुर्घटनाओं की रोकथाम व दुर्घटना पश्चात कार्यवाही को 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बस अड्डे पर चार्जिंग स्टेशन के मद में 50 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है। खन्ना ने कहा कि नागर विमानन के लिए 2,111 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। इसकी पूर्ति के भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना के माध्यम से कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जेवर (नोएडा) में राज्य सरकार द्वारा बनने वाले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में दो रनवे की संख्या बढ़ाकर पांच रनवे बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। खन्ना ने कहा कि प्रदेश सरकार की हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा जमीन के लिए 1,100 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

नेपाल के पशुपतिनाथ से बिहार होते हुए झारखंड के बैद्यनाथधाम तक बनेगा हाई–स्पीड एक्सप्रेसवे

पटना, (भाषा) बिहार के पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि नेपाल के पशुपतिनाथ से बिहार होते हुए झारखंड के बैद्यनाथधाम तक 'पशुपतिनाथदृ बैद्यनाथधाम हाई–स्पीड कॉरिडोर' ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। मंत्री ने पथ निर्माण विभाग के बजट पर सरकार का पक्ष रखते हुए सदन को बताया कि लगभग 250 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे काठमांडू से भीमनगर और बीरपुर होते हुए बिहार के सुपौल जिला में भारतीय सीमा में प्रवेश करेगा। इसके बाद यह मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर और बांका जिलों से गुजरते हुए झारखंड के देवघर जिले स्थित बैद्यनाथधाम तक पहुंचेगा। जायसवाल ने कहा कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर को झारखंड के बैद्यनाथधाम से सीधे जोड़ना है, ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले और सांस्कृतिक आदान–प्रदान को गति मिल सके। उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर के निर्माण से बिहार और झारखंड के कई जिलों में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी तथा क्षेत्रीय संपर्क व्यवस्था सुदृढ़ होगी। मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे को रक्सौलदृ हल्दिया और दरभंगा–अमस एक्सप्रेसवे जैसे अन्य प्रमुख मार्गों से भी जोड़ा जाएगा, जिससे पूर्वी भारत में सड़क संपर्क का एक सशक्त नेटवर्क विकसित होगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि भारत–नेपाल सीमा सड़क परियोजना के तहत बिहार में कुल 554.08 किलोमीटर लंबाई में सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह परियोजना सीमावर्ती सात जिलों–पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से होकर गुजरती है। यह मार्ग पश्चिमी चंपारण के मदनपुर से शुरू होकर किशनगंज जिले के गलगलिया में समाप्त होगा। मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और सुरक्षा के लिहाज से भी राज्य को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा।

बिहार विधानसभा में 12,165 करोड़ रुपये का तृतीय अनुपूरक बजट पारित

पटना, (भाषा) बिहार विधानसभा ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025–26 के लिए 12,165 करोड़ रुपये से अधिक के तृतीय अनुपूरक बजट से संबंधित विनियोग विधेयक को विपक्ष के बहिर्गमन के बीच ध्वनि–मत से पारित कर दिया। बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष के लिए 12,165 करोड़ रुपये से अधिक का तृतीय अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया था। वित्त वर्ष 2025–26 के इस तृतीय अनुपूरक बजट में वार्षिक योजना मद के तहत 9,586.39 करोड़ रुपये और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के तहत 2,579.04 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक बजट में समग्र शिक्षा अभियान के लिए केंद्रीय अंश के रूप में 41.82 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 1,013 करोड़ रुपये और सक्षम आंगनवाड़ी पोषण–2.0 के लिए 633.63 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।सक्षम आंगनवाड़ी पोषण–2.0 कुपोषण से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है। इस योजना में बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषण सामग्री और सेवाओं की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समन्वित तंत्र विकसित किया जाता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के लिए केंद्रीय अंश के रूप में 1,184 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) का उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वरोजगार और कौशल आधारित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। चर्चा में भाग लेते हुए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और राज्य के पूर्व कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा, "वे (राजग) इसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं। लेकिन इसमें एक इंजन अपराध का है और दूसरा भ्रष्टाचार का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) पहले ही राज्य सरकार को 70,877 करोड़ रुपये से अधिक के उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं करने पर फटकार लगा चुका है। यह 70,000 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला है। ऐसे में सरकार का चालू वित्त वर्ष के लिए और धन मांगना समझ से परे है।" इसके अलावा, सदन ने वर्ष 2025–26 के लिए समाज कल्याण विभाग का 724 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट भी पारित किया। सदन ने इसी विभाग के लिए वर्ष 2026–27 हेतु 8,470 करोड़ रुपये की मांग को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया।

दिल्ली: 'एआई समिट' के लिए 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे

नयी दिल्ली, (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी में 16 से 20 फरवरी तक आयोजित 'इंडिया–एआई इम्पैक्ट समिट' के दौरान कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह पांच दिवसीय कार्यक्रम भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा और इसमें 30 से अधिक देशों के हजारों प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। अधिकारी ने बताया, "भारत मंडपम के आसपास और निकटवर्ती इलाकों में ही दिल्ली पुलिस के 10,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनमें जिला पुलिस बल, यातायात पुलिस, विशेष इकाइयां और आरक्षित बल शामिल होंगे।"

महाराष्ट्र : भाजपा नीत महायुति ने जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनाव में शानदार जीत दर्ज की

मुंबई, (भाषा) महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने जिला परिषदों की 731 सीट में से 560 और पंचायत समितियों की 1,462 सीट में से 1,143 सीट जीती हैं। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को यह अंतिम चुनाव परिणाम घोषित किया। चुनाव सात फरवरी को हुए थे। कराड़ पंचायत समिति की 24 सीट के परिणाम घोषित होने के बाद चुनाव नतीजे में संशोधन किया गया। राज्य में 125 पंचायत समितियों की 1,462 सीट में भारतीय जनता पार्टी ने 491, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने 327 और शिवसेना ने 325 सीट जीतीं। महाराष्ट्र की 12 जिला परिषदों की कुल 731 सीट में भाजपा ने 233, राकांपा ने 166 और शिवसेना ने 161 सीट जीतीं। भाजपा, शिवसेना और राकांपा महायुति गठबंधन का हिस्सा हैं। जहां तक विपक्ष की बात है तो, जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस ने 58 सीट, शिवसेना (उबाठा) ने 44 और राकांपा (शप) ने 26 सीट जीतीं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को दो सीट मिलीं, जबकि 41 सीट निर्दलीय और अन्य उम्मीदवारों को मिलीं। पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस ने 98, राकांपा (एसपी) ने 50, शिवसेना (उबाठा) ने 86 सीट जीतीं। मनसे दो सीट पर विजयी रही। निर्दलीय उम्मीदवारों एवं अन्य के खाते में 83 सीट गयीं।

एक भारत, एक कानून की नीतिगत कसौटी के सियासी निहितार्थ

विभिन्न तरह के पारस्परिक विरोधाभासों से जूझ रहे भारतीय गणतंत्र के लिए श्एक भारत, एक कानूनश की अवधारणा बदलते वक्त की मांग है। इसलिए इसको सरजमीं पर उतरना बेहद जरूरी है। सवाल है कि जब एक मतदाता, एक वोट का विधान सफल हो सकता है तो फिर एक भारत, एक कानून का विधान क्यों नहीं? इस बात में कोई दो राय नहीं कि ऐसी सकारात्मक कोशिशें अंततोगत्वा समतामूलक समाज की दिशा में निर्णायक साबित हो सकते हैं। लिहाजा यदि भारतीय संविधान के संघीय ढांचे और अन्यान्य विविधताओं को बनाए रखने वाले नानाविध प्रावधानों से श्एक देश, एक कानूनश की पावन और समदर्शी सोच टकराती है तो ऐसे किसी भी टकराव को नजरअंदाज कीजिए और एक समान नागरिक संहिता (न्ब्ब) या एकसमान कानूनी व्यवस्था की दिशा में एक यथार्थपरक व्यवहारिक कदम उठाइए। इससे दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, सवर्ण जैसे निरर्थक भेद भी मिटेंगे और राष्ट्र को अप्रत्याशित मजबूती मिलेगी। यह ठीक है कि इस राह में कई संरचनात्मक बाधाएं हैं लेकिन राष्ट्र के दूरगामी भविष्य के लिए इन कपोलकल्पित बाधाओं, वैधानिक जटिलताओं से निबटना भी तो सकारात्मक और आशावादी नेतृत्व की पहचान होती है। खासकर मोदी हैं तो मुमकिन है, वाली सोच यहां भी चरितार्थ की जा सकती है। योगी हैं तो यकीन भी किया जा सकता है। शाह हैं तो चिल्लपों भी नहीं मचेगा, ऐसा जनविश्वास है। जहां तक संघीय ढांचे की चुनौतियों की बात है तो भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का त्रिपक्षीय विभाजन (केंद्र, राज्य, समवर्ती) एक देश, एक कानून की राह का एक बड़ा रोड़ा समझा जाता है। उदाहरणतया पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि जैसे विषय राज्य सूची में हैं, जिनमें केंद्र का सीधा हस्तक्षेप संभव नहीं होगा बिना संशोधन के क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 246 इस विभाजन को मजबूत बनाता है जो एकसमान कानून लागू करने में राज्यों की सहमति या संविधान संशोधन की मांग करता है। वहीं, मौलिक अधिकारों का टकराव भी संभाव्य है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 25–28 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, जो व्यक्तिगत कानूनों (पर्सनल लॉ) को संरक्षण प्रदान करते हैं। वहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अनुच्छेद 44 के नीति–निर्देशक तत्व के रूप में रखा गया है लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है और मौलिक अधिकारों से टकरा सकता है। यही वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे लागू करने पर जोर दिया है (जैसे शाह बानो मामले में) लेकिन संघीय विविधता और अल्पसंख्यक अधिकारों के नाम पर राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी इस राह की सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है, वहीं व्यावहारिक और न्यायिक अड़चनों की बात भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एकीकृत न्यायपालिका (अनुच्छेद 214) होने के बावजूद, राज्यों में उच्च न्यायालयों की स्वायत्तता और लंबित मामलों (5 करोड़ से अधिक) की भारी संख्या एकसमान कानून के कार्यान्वयन को जटिल बनाती है। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया में राज्यों की सहमति जरूरी हो सकती है जो राजनीतिक मतभेदों से अवरुद्ध रहती है। जहां तक संभावित प्रभाव की बात है तो ये अड़चनें वास्तव में संविधान की विविधता–समर्थक भावना को दर्शाती हैं जो एकता के साथ बहुलवाद को संतुलित रखती हैं। हालांकि, डिजिटल युग में एकसमान कानून आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन बिना व्यापक सहमति के यह संघीय तनाव भी पैदा कर सकता है। इसलिए केंद्र सरकार और उसकी राज्य सरकारों को इस बाबत आम सहमति तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक भारत, एक कानून में ही न केवल देश बल्कि दुनिया का भी हित निहित, अंतर्निहित है। देखा जाए तो समान नागरिक संहिता, भारतीय संविधान की मौलिक व्यवस्था पर ज्यादातर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, खासकर समानता के अधिकार को मजबूत करके, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता जैसे क्षेत्रों में यह टकराव पैदा कर सकती है हालांकि, धर्म के आधार पर बंटवारे के बाद यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है बल्कि राजनीतिक कमजोरी का प्रतीक है। यह ठीक है कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत यह नीति–निर्देशक सिद्धांत राज्य को एकसमान नागरिक कानून बनाने का प्रयास करने को कहता है जो मौलिक अधिकारों से जुड़ता है।

जहां तक समानता अधिकारों पर प्रभाव की बात है तो यूसीसी संवैधानिक अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता) और 15 (भेदभाव निषेध) को मजबूत बनाएगा क्योंकि यह धर्म–आधारित व्यक्तिगत कानूनों को हटाकर लैंगिक न्याय सुनिश्चित करेगा। इसी के द्वारा तीन तलाक, असमान उत्तराधिकार जैसे मुद्दों का सम्यक समाधान हो सकता है, जो महिलाओं के अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) को प्रभावित करते हैं हालांकि, यदि गलत तरीके से लागू हुआ तो यह अल्पसंख्यकों के बीच भेदभाव का आरोप लगा सकता है। जहां तक धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव की बात है तो अनुच्छेद 25–28 धार्मिक स्वतंत्रता और प्रबंधन का अधिकार देते हैं जो यूसीसी से टकरा सकता है क्योंकि व्यक्तिगत कानून सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं। भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने शाह बानो और सारला मुद्गल मामलों में यूसीसी की आवश्यकता बताई लेकिन इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न मानते हुए संतुलित किया। फिर भी जनजातीय रीति–रिवाजों वाली समुदायों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। जहां तक अन्य मौलिक प्रावधानों पर यूसीसी के प्रभाव की बात है तो यूसीसी संवैधानिक अनुच्छेद 21 को सशक्त बनाएगा क्योंकि यूसीसी पितृसत्तात्मक प्रथाओं को चुनौती देगा और न्याय प्रक्रिया को सरल करेगा लेकिन समवर्ती सूची के विषय होने से राज्य स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है जो संघीय ढांचे से जुड़ी मौलिक भावना को कमजोर करेगी। कुल मिलाकर, यूसीसी मौलिक अधिकारों को आधुनिक संदर्भ दे सकता है यदि सहमति–आधारित हो तो। यही वजह है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल के वर्षों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर स्पष्ट निर्देश देने से इनकार किया है बल्कि इसे संसद के क्षेत्राधिकार में माना है। भले ही कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसलों में यूसीसी के सिद्धांत का समर्थन किया, लेकिन कार्यपालिका को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी। जहां तक कोर्ट के रुख की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 और 2024 में यूसीसी लागू करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, क्योंकि यह विधायी मामला है। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (ब्श्रप्) डीवाई चंद्रचूड़ ने मार्च 2023 में छह याचिकाओं को निस्तारित करते हुए कहा कि यूसीसी संसद बनाएगी। इससे पहले आये निम्नलिखित प्रमुख फैसले में भी यूसीसी की चर्चा है। शाह बानो (1985), सरला मुदगल (1995), और जॉन वल्लामट्टम (1997) जैसे मामलों में कोर्ट ने यूसीसी की आवश्यकता पर बल दिया लेकिन निर्देश नहीं दिए। इसी प्रकार जनवरी 2023 में उत्तराखंड यूसीसी समिति को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी खारिज हुईं। जहां तक वर्तमान स्थिति की बात है तो जनवरी 2026 तक कोई नया निर्देश नहीं आया क्योंकि कोर्ट यूसीसी को अनुच्छेद 44 के नीति–निर्देशक सिद्धांत के रूप में देखता है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के साथ संतुलन पर जोर देता है। यही वजह है कि भाजपा शासित उत्तराखंड सरकार ने 2024 में राज्य–स्तरीय यूसीसी लागू किया। समझा जा रहा है कि धीरे धीरे मोदी–शाह इसे पूरे देश में लागू करेंगे। हालांकि इससे भी एक कदम आगे बढ़कर सभी जनहितकारी मामलों में यदि एक देश, एक कानून जैसे अग्रगामी प्रावधानों को लागू कर दिया जाता है तो विगत 100 सालों से अनवरत रूप से जारी फूट डालो, शासन करो की नीति का जड़मूल से खात्मा हो जाएगा। यद्यपि मुट्ठी भर चतुर सुजान विदेशी टुकड़े पर विरोध अवश्य करेंगे लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू–कश्मीर में धारा 370 हटवाकर एक विधान, एक निशान की राष्ट्रीय नीति लागू करवा सकते हैं तो उनके लिए एक देश, एक कानून को मूर्त रूप देना–दिलवाना कोई बड़ी बात नहीं है बशर्ते कि इस मुद्दे पर भाजपा और आरएसएस की नीति साफ और नीयत स्पष्ट हो।

कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक

महाराष्ट्र सरकार ने पुरंदर हवाई अड्डे के लिए 6,000 करोड़ रुपये का ऋण लेने को मंजूरी दी

मुंबई, (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को पुणे जिले में प्रस्तावित पुरंदर हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए 6,000 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी), महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कंपनी (एमएडीसी), नगर एवं औद्योगिक विकास निगम (सीआईडीसीओ) और अन्य एजेंसियों को मिलाकर एक 'स्पेशल पर्पज व्हीकल' (एसपीवी) के गठन को मंजूरी दी। सरकार के अनुसार, परियोजना क्षेत्र के 96 प्रतिशत किसानों ने हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए अपनी सहमति दे दी है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, चूंकि अब बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है, इसलिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर धन जुटाया जाएगा।

संपादकीय

ट्रंप–मोदी : रणनीतिक स्वायत्तता, व्यापारिक सौदे और बदलता वैश्विक संतुलन

.... वर्ष 2025 में ट्रंप और मोदी के बीच तनाव के कई कारण सामने आए। सबसे प्रमुख कारण था अमेरिकी टैरिफ नीति। ट्रंप प्रशासन ने भारत के निर्यात पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ बढ़ा दिए, खासकर टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और जेम्स जैसे क्षेत्रों में। इससे द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं लगभग ठप हो गईं। भारत के लिए यह केवल आर्थिक झटका नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था कि अमेरिका अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके साथ ही रूस से भारत के तेल और हथियार खरीदने को लेकर अमेरिकी असंतोष भी खुलकर सामने आया। अमेरिका चाहता था कि भारत ऊर्जा और रक्षा जरूरतों के लिए उसके और उसके सहयोगियों पर अधिक निर्भर हो, जबकि भारत अपनी आपूर्ति श्रृंखला को विविध बनाए रखना चाहता था। पाकिस्तान के प्रति ट्रंप का अपेक्षाकृत नरम रुख भी भारत में असहजता का कारण बना। इन सभी कारकों ने व्यक्तिगत स्तर पर भी मोदी–ट्रंप के संबंधों को प्रभावित किया।

हालांकि राजनीति में स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होते, केवल हित स्थायी होते हैं। सितंबर 2025 में जब ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से मोदी की तारीफ करते हुए रिश्तों को "खास" बताया, तो यह संकेत था कि अमेरिका भी भारत की अनदेखी नहीं कर सकता। भारत ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से संयमित लेकिन सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इस बीच भारत की "चुप्पी कूटनीति" ने अपना असर दिखाया। शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर भारत की सक्रिय भूमिका, यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते की दिशा में प्रगति और वैश्विक दक्षिण में भारत की बढ़ती स्वीकार्यता ने अमेरिका को यह समझने पर मजबूर किया कि भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि उभरती हुई वैश्विक ताकत है। फरवरी 2026 में ट्रंप की मोदी से फोन कॉल ने इस समझ को औपचारिक रूप दे दिया और जमी बर्फ को काफी हद तक पिघला दिया।

इस फोन वार्ता का सबसे ठोस परिणाम व्यापार और टैरिफ विवाद में प्रगति के रूप में सामने आया। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमति जताई, जबकि भारत ने कुछ अहम रियायतें दीं। भारत ने रूसी तेल की खरीद में कटौती करने, अमेरिका और वेनेजुएला से अधिक ऊर्जा आयात करने तथा अमेरिकी उत्पादों पर कुछ मामलों में शून्य टैरिफ देने का वादा किया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर घोषणा की कि मोदी के अनुरोध पर रेसिप्रोकल टैरिफ में कमी की गई है। इससे पहले कुल टैरिफ 50 प्रतिशत तक पहुंच गए थे, जिनमें रूसी तेल से जुड़े 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क भी शामिल थे। इस समझौते से यह दंड समाप्त हो गया। यह समाधान अचानक नहीं हुआ, बल्कि अगस्त 2025 से जनवरी 2026 तक चली लंबी और जटिल वार्ताओं का परिणाम था। फोन कॉल ने केवल अंतिम मुहर लगाई। भारत ने इन वार्ताओं में यह सुनिश्चित किया कि कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा हो सके, क्योंकि ये न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। दूसरी ओर अमेरिका को अपने व्यापार घाटे को कम करने और अपने निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने का लाभ मिला। इस समझौते से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने का रास्ता साफ होता दिखाई देता है। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि सभी विवाद पूरी तरह समाप्त हो गए हैं।

स्टील, एल्यूमीनियम और कुछ टेक्सटाइल उत्पादों पर ऊंचे टैरिफ अभी भी प्रभावी हैं, भले ही निर्यात में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई हो। अमेरिकी सांसदों के एक वर्ग ने इन टैरिफ को खत्म करने की मांग की है, लेकिन ट्रंप की "अमेरिका फर्स्ट" नीति अब भी एक बड़ी बाधा है। फिर भी, यह स्पष्ट है कि फरवरी 2026 की फोन कॉल ने रिश्तों को नई गति दी है और पूर्ण समाधान के लिए बहुपक्षीय मंचों, खासकर एससीओ जैसे मंचों पर आगे की बातचीत महत्वपूर्ण होगी। द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक मायनों पर नजर डालें तो भारत और अमेरिका के बीच हालिया रक्षा और व्यापार समझौते विशेष महत्व रखते हैं। दोनों देशों ने 10 साल के रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 2015 में शुरू हुई रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाता है। इसका उद्देश्य केवल हथियारों की खरीद–फरोख्त नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता, सूचना साझाकरण और हिंद–प्रशांत क्षेत्र में उभरती चुनौतियोंकृविशेष रूप से चीन के बढ़ते प्रभावकृ का सामना करना है। टैरिफ तनाव के बावजूद रक्षा सहयोग का बढ़ना यह दर्शाता है कि दोनों देश दीर्घकालिक रणनीतिक हितों को तात्कालिक व्यापारिक विवादों से ऊपर रख रहे हैं। व्यापार के मोर्चे पर भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए गए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। टैरिफ में आंशिक कटौती, बाजार पहुंच में सुधार और निवेश को प्रोत्साहन इस दिशा में अहम कदम हैं। हालांकि दूध, कृषि उत्पादों और डेटा स्थानीयकरण जैसे मुद्दों पर मतभेद अभी भी बने हुए हैं।

रेसिप्रोकल टैरिफ और जीएसपी लाभों की बहाली जैसे प्रश्नों पर आगे की बातचीत आवश्यक होगी। इसके बावजूद, यह स्पष्ट है कि दोनों पक्ष चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि घरेलू राजनीतिक दबावों और आर्थिक वास्तविकताओं के बीच संतुलन बना रहे। इन समझौतों का प्रभाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे भारत में निर्यात को बढ़ावा, रोजगार सृजन और रक्षा तकनीक के हस्तांतरण के अवसर बढ़ेंगे। अमेरिका के लिए भारत एक विशाल बाजार, विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार और एशिया में संतुलन का महत्वपूर्ण स्तंभ है। भू–राजनीतिक अनिश्चितताओं के इस दौर में दोनों देशों का अभिसरण वैश्विक स्थिरता के लिए भी अहम है। अंततः ट्रंप और मोदी के बीच रिश्तों का यह नया अध्याय यह दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थिर नहीं होते, बल्कि परिस्थितियों, हितों और नेतृत्व की प्राथमिकताओं के साथ बदलते रहते हैं। बर्फ पिघली है, लेकिन मौसम पूरी तरह बदल गया है, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी।

फिर भी, संवाद की बहाली, व्यापारिक तनाव में कमी और रणनीतिक सहयोग की निरंतरता यह संकेत देती है कि दोनों देश टकराव से अधिक सहयोग को प्राथमिकता देना चाहते हैं। भारत के लिए यह एक अवसर है कि वह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को और मजबूत करे, जबकि अमेरिका के लिए यह स्वीकार करने का क्षण है कि 21वीं सदी की विश्व व्यवस्था में भारत को नजरअंदाज करना संभव नहीं है।

कृष्णा अग्रवाल
focusnews9@gmail.com

खूबसूरती को निखारता है आंखों का मेकअप

प्रकृति ने नारी को सुन्दर बनाकर वास्तव में इस धरा का श्रृंगार करने हेतु भेजा है। सृष्टि के प्रारंभ से ही नारी सौंदर्य आकर्षण का कारण बनता रहा है। नारी मेकअप द्वारा अपनी आंखों को और भी अधिक आकर्षक बना दे तो 'सोने पे सुहागा' वाली कहावत अवश्य ही चरितार्थ हो जाएगी। आंखों की सुन्दरता नारी के व्यक्तित्व को और भी अधिक बढ़ा देगी।

नारियों व व्यक्तियों में चार–चांद लगाकर उनके रूप–रंग का साक्षात्कार करने वाला प्रत्यक्षतः अगर कोई अंग है तो वह है आंखें। आंखों की तारीफ में जितने कसीदे पढ़े गए हैं,शायद ही किसी दूसरी चीज की तारीफ में पढ़े गये हों। सुरमई, कजरारी, मृगनयनी, झील–सी गहरी, नीलकमल, शरबती, जाम, मयखाना आदि न जाने कितने ही और अन्य नामों से कवियों और शायदों ने इन आंखों को पुकारा है। बड़े–बड़े काव्य, ग्रंथ और शायरी के दीवान इन आंखों की तारीफों से भरे पड़े हैं।

आंखें तो प्राकृतिक रूप से ही खूबसूरत होती हैं परन्तु अगर थोड़ा सा मेकअप का जामा पहना दिया जाए तो फिर कहना ही क्या? आपके समक्ष आंखों को मेकअप द्वारा आकर्षक व खूबसूरत बनाने के विभिन्न तरीके पेश किए जा रहे हैं। इन तरीकों को अपनाने से पहले कुछ खास बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक होता है।

आंखों का मेकअप करते समय इस्तेमाल की जाने वाली 'आई–शैडो' के रंग का चुनाव अपने चेहरे, बालों के रंग और आंखों को ध्यान में रखकर ही करें। 'आई–शैडो' के चुनाव में यह ध्यान रखने योग्य खास बात होती है कि वह न तो आपकी आंखों के रंग से मेल खाए और न ही कपड़ों के रंग से ही। अगर आंखों का रंग नीला है तो उन पर ग्रे कलर, कॉपर–कलर या खाकी रंग के 'आई–शैडो' का ही इस्तेमाल करें। अगर आंखें भूरी या काली हैं तो सुनहरे या जामुनी रंग का 'आई–शैडो' आप पर खूब फबेगा। कन्ट्रास्ट प्रकट करने वाला 'आई–शैडो' कुछ अधिक ही प्रभावी दिखाई देता है।

जहां तक संभव हो सके, पाउडर वाले आई–शैडो की बजाय क्रीम वाले आई–शैडो का इस्तेमाल ही करें। यदि उसमें भी पेंसिल वाला हो तो बेहतर होगा। क्रीम वाले आई–शेडो में पानी व तेल की समुचित मात्रा होती है, इसलिए वह सूखी त्वचा के लिए तो फायदेमंद हो सकता है क्योंकि वह त्वचा के साथ मिल जाता है परन्तु नमीदार त्वचा में क्रीम वाला आई–शैडो न मिलने के कारण इधर–उधर रिसने लगता है और त्वचा को दागदार बना देता है। तैलीय त्वचा पर क्रीम वाले आई–शैडो की बजाय पाउडर वाले आई–शैडो का इस्तेमाल करें। अंजन लगाने के बाद आपकी बरौनियां चिपकी न रह जाएं, इसके लिए कंघी या किसी साफ नर्म दांतों वाले ब्रश के जरिए अपनी बरौनियों को अलग–अलग कर लें। इससे उनकी सुन्दरता में भी निखार आ जाएगा।

बरौनियों (भौंहों) के प्राकृतिक रूप से सुन्दर न होने पर बनावटी बरौनियों के जरिए आंखों की सुन्दरता को निखारा जा सकता है। इसके लिए बाजार में अलग–अलग किस्म, साइज व रंगों वाली बनावटी बरौनियां भी मिलती हैं परन्तु अपनी आंखों के रंग के अनुरूप ही किसी बनावटी बरौनी का चयन करना चाहिए।

बरौनियों को चिपकाते समय गोंद की मात्रा पर ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। गोंद की अधिक मात्रा आंखों में जलन पैदा कर आपको हंसी का पात्रा बना सकती है। बरौनियों के इस्तेमाल से पहले उनकी लंबाई नाप लेनी चाहिए। बरौनी की लंबाई आंख के दोनों कोनों से ज्यादा न हों। बरौनी की पट्टी पर समान रूप से गोंद लगा लें, फिर अपनी उंगलियों के सहारे अपनी पलकों को हल्का–सा फैलाकर उसके बाद उस पर चिपकाएं।

बुझी–बुझी–सी दिखने वाली आंखों के लिए ऊपरी पलकों पर बिलकुल हल्के रंग के व निचली पलकों पर गहरे रंग के आईलाइनर का इस्तेमाल करें। गहरे रंगों के इस्तेमाल से बचें। आई शोकेट लाइन की भी शेडिंग करें। इससे आंखें सजीव नजर आएंगी।

दोनों आंखों के बीच ज्यादा दूरी वाली आंखों के लिए गहरे रंग के आईलाइनर के जरिए आंखों को आउटलाइन करें। बाहरी हिस्से पर हल्के रंग व शैडो का इस्तेमाल करें तथा दोनों आंखों के अंदरूनी कोनों पर गहरे रंग के आई–शैडो का ही इस्तेमाल करें।

गहरी धंसी हुई आंखों के लिए भौंहों पर किसी हाइलाइटर के और आई शोकेट की भीतरी लाइन पर किसी गहरे रंग के आई–शैडो के इस्तेमाल से बचें। अंजन या तो बिलकुल कम लगाएं या फिर लगाएं ही नहीं। पलकों के अन्दर वाले हिस्से पर बिलकुल हल्के रंग के व ऊपरी–निचली दोनों पलकों के बाहरी हिस्से में गहरे रंग के शैडो का ही इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपकी आंखें उभरी–उभरी दिखाई देंगी।

उभरी हुई आंखों के लिए ऊपरी पलक के बीच से कोने तक आईशैडो लगाएं तथा हल्के व फीके रंग के आई–शैडो के स्थान पर बिलकुल गहरे रंग के आई–शैडो का इस्तेमाल करें। भौंहों को किसी अच्छे हाइलाइटर की सहायता से 'हाइलाइट' करें।

दोनों आंखों के बीच कम दूरी वाली आंखों के लिए आंखों के अंदरूनी कोनों पर हाइलाइटर लगाएं तथा गहरे रंग के आई–शैडो का इस्तेमाल करें। आंखों के बाहरी कोनों पर आई–लाइनर के जरिये हल्की–सी लाइन खींचें ।

गोलाकार आंखों के लिए आंखों के अंदरूनी कोनों पर हल्के रंग के व बाहरी कोनों पर गहरे रंग के आई शैडो का इस्तेमाल करें। शेड को ऊपर की ओर ले जाकर मिलाएं। हाइलाइटर के इस्तेमाल से बचें। निचली पलक के अंदरूनी भाग को पेंसिल लाइनर की सहायता से लाइन करें । इससे आंखें गोलाकार न दिखाकर संकरी व फैली हुई दिखाई देंगी। इस प्रकार आंखों को खूबसूरती प्रदान की जा सकती है।

यूं पायें तनाव से मुक्ति

आजकल समय ही ऐसा आ गया है कि हर दूसरा आदमी तनाव से पीड़ित है। यदि आप तनावग्रस्त हैं तो आप निम्न सुझावों पर अवश्य अमल करें। आपको शीघ्र ही तनाव से मुक्ति मिल जायेगी। सर्वप्रथम तो अपने आप को कभी कमजोर न समझें। अपनी छोटी से छोटी सफलता को भी याद रखें एवं स्वयं को शाबाशी दीजिए। इन छोटी सफलताओं से गर्वित न हों बल्कि अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाते जाएं। अपना आत्मविश्वास कभी कमजोर न होने दें। एक लम्बे समय बाद परिणाम देने वाले कार्यो के साथ–साथ शीघ्र फल देने वाले कार्यों को भी करते रहिए जिसके फलस्वरूप आप तनाव से बचे रहेंगे। इससे खुशी कायम रहती है और आत्मविश्वास को बल मिलता रहता है। किसी भी कार्य को टालने या न करने के बहाने करना वास्तव में तनाव को अपने पास बुलाने के समान है। किसी भी कार्य के असफल एवं गलत होने पर दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। स्वयं में गलती ढूंढनी चाहिए कि हम से गलती कहां पर हो गयी। पुनः उसी कार्य को सही ढंग से प्रारम्भ करना चाहिए क्योंकि दूसरों में दोष तलाशने की आदत स्वयं की असफलता की ओर ही धकेलती है जिसका परिणाम यह होता है कि कि आपको तनाव का सामना करना पड़ता है। भविष्य की चिंता अधिक न करें। वर्तमान में ही जीना सीखें। वर्तमान से पीछे भागना एवं भविष्य की चिंता करना तनाव को आमंत्राण देना ही है। कभी भी जल्दबाजी में बिना परिणाम सोचे गये किसी भी कार्य के लिए हां करना या बिना सोचे विचारे करना जानबूझकर मुसीबत को मोल लेने के समान है, जिसके परिणामस्वरूप असफलता मिलने पर तनाव का सामना करना पड़ता है। हमें उन्हीं बातों एवं कार्यों के बारे में ही सोचना चाहिए जो हमारे बस में हों और जिन्हें हम कर सकते हैं। किसी प्राकृतिक विपदा, भय एवं अपनी मृत्यु के बारे में सोच–सोच कर तनावग्रस्त न हों। स्वस्थ रहकर परेशानी को झेलना व समस्याओं से जूझने की क्षमता अपने आप में पैदा करें। क्रोध तनाव का सबसे प्रमुख हथियार है इसलिए जहां तक संभव हो, अपने क्रोध पर काबू रखने का प्रयास करते रहें। क्रोध पर काबू करने के लिए आप अपना ध्यान उस बात पर से हटा लें जिसके कारण आपको क्रोध आया हो और कोई भी अपना रूचिपूर्ण कार्य करने लगें जैसे संगीत सुनना, घूमने फिरने बाहर जाना आदि, अपना ध्यान दूसरे कार्यों में लगा दे जिससे आपको तुरंत क्रोध से मुक्ति मिल जायेगी और आपके तनाव की समस्या अपने आप हल हो जायेगी। मनोचिकित्सकों का कहना है कि तनाव की स्थिति उत्पन्न होने पर हाथ रखकर बैठे रहना तनाव को और अधिक बढ़ाना है, अतः तनाव के मुख्य कारण जानकर उससे मुकाबला करने का दृढ़ निश्चय शक्ति स्रोत बढ़ाता है और इसी से हमें सफलता की प्राप्ति होती है अनिश्चितता, अकर्मण्यता को जन्म देती है पूरा जीवन इससे बचने के लिए सदैव गतिशील रहना चाहिए। किसी कार्य की योजना बनाकर उस पर अमल करना केवल दिवास्वप्न देखते रहना अंत में तनाव का कारण बन जाता है, अतः अपनी शक्ति, सामर्थ्य एवं योजना अनुसार कार्य क्षेत्रा चुनकर उसमें जुट जाने से ही सफलता मिलती है।

सुंदरता में चार चांद लगाते हैं नाखून

दांतों से नाखून काटते रहने की भी कई महिलाओं की आदत होती है, खास तौर पर उस समय जब वे किसी से बात कर रही होती हैं अथवा उनकी इच्छा के अनुरूप कोई कार्य न हुआ या वे गुस्से में हों। इस आदत से पीछा छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा नाखूनों में छिपे फंगस मुंह में चले जाते हैं और गर्भाशय तक पहुंचकर गर्भाशय को भी हानि पहुंचाते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध चिकित्सक सिम वोटंग का मानना है कि 35 प्रतिशत महिलाओं में बांझपन की बीमारी इसी कारण होती है।

नाखूनों को हमेशा खुरचते रहने अथवा उन पर बार–बार पैडिक्योर या मैनिक्योर करते रहने से भी नाखूनों में इंफेक्शन का खतरा हो जाता है।

आपकी सुंदरता की पहचान जहां एक ओर हाथ, पैर, चेहरे, गर्दन, आंख एवं नाक से होती है, वहीं सुंदरता बढ़ाने में आपके नाखूनों का भी काफी योगदान होता है। वैसे पैरों में नाखूनों का उतना योगदान नहीं होता क्योंकि वहां पर लोगों की नजर कम पड़ती है परन्तु हाथों के नाखूनों पर प्रायः सबकी नजरें पड़ती रहती हैं।

महिलाएं प्रायः अपने नख सौंदर्य की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया करती हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं, प्रथम तो जानकारी का अभाव और दूसरा लापरवाही।

गंदे, भद्दे, कटे–फटे नाखून आपकी उस पोल को खोल देते हैं जिसे आप छिपाना चाहती हैं। नाखूनों में अगर एक बार रोग अपना घर बना लेता है तो वह सहज ही ठीक नहीं हो पाता।

घर का कामकाज करने वाली महिलाओं को नाखूनों के रोग लगने की संभावना अधिक होती है। कपड़े इत्यादि धोते समय हाथ गीले रहने के कारण नाखूनों की सतह मुलायम और कमजोर हो जाती है जिसके कारण रोग का संक्रमण शीघ्र हो सकता है।

नाखून किरेटिन नामक प्रोटीन से निर्मित होते हैं। यदि आपके शरीर में इस प्रोटीन की कमी आ जाती है तो आपके नाखूनों की सुंदरता समाप्त हो जाती है। यदि आप भोजन में नियमित रूप से हरी सब्जी, दूध, मांस, अंडे, दही इत्यादि का सेवन करती हैं तो इससे मुक्ति मिल जाती है। नाखूनों की नियमित सफाई नाखूनों को उम्र प्रदान करती है। नाखूनों की सफाई न करने से संक्रमण होने का खतरा बना रहता है जिससे नाखूनों में विकृति अथवा क्षयकारक रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं।

नाखूनों पर आक्रमण करने वाले रोगों को या रोगाणुओं को फंगस कहा जाता है। ये कई तरह के होते हैं। अधिकतर मामलों में छूत के द्वारा ही नाखूनों को हानि पहुंचती है। नाखूनों का फंगस इंफेक्शन कैंडिडा समूह के फंगस द्वारा होता है जिसे पैरोनाइकिया और नाखूनों के दाद (रिंगवर्म) के नामों से जाना जाता है।

पैरोनाइकिया को उत्पन्न करने वाला फंगस मल में मौजूद रहता है और नाखूनों की ठीक ढंग से सफाई न होने के कारण यह रोग लग जाता है। इस तरह का इंफेक्शन गृहणियों को प्रायः हो जाता है, कारण, कपड़े साफ करते समय हाथ गीले तो रहते हैं, साथ ही उसमें साबुन डिटर्जेन्ट इत्यादि भी लग जाते हैं। इससे नाखूनों की ऊपरी सतह जिसे 'क्यूटिकल' कहा जाता है, कमजोर पड़ जाती है और जगह–जगह से दरार के समान फटने लगती है। रोग उत्पन्न करने वाले फंगस का प्रवेश इसमें आसानी से हो जाता है और नाखून भद्दे होने लगते हैं।

नाखूनों की कटाई प्रति सप्ताह होनी चाहिए। कभी भी नाखूनों को जमीन आदि पर नहीं घिसना चाहिए। रात में सोने से पहले नाखूनों को हल्के गुनगुने पानी के साथ साबुन से धोकर, अच्छी तरह पोंछकर जैतून का तेल अथवा नारियल के तेल से मालिश करने से नाखून मुलायम, खूबसूरत और चमकीले बने रहते हैं।

नाखूनों को बड़ा करने का शौक महिलाओं में दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है यद्यपि यह भी सौंदर्य बढ़ाने के लिए आवश्यक है. जिन महिलाओं को बड़े नाखून रखने का शौक हैं, उनके लिए यह आवश्यक है कि वे नाखूनों की सफाई की ओर पर्याप्त ध्यान दें। खाना बनाने के तुरन्त बाद नाखूनों के अंदर की गदंगी को साफ कर लें और गीले नाखूनों को नर्म कपड़े से पोंछ लें।

नाखूनों पर विभिन्न प्रकार की नेल पालिश लगाने का भी चलन आम है। नेल पालिश का चुनाव तो आपको अपनी इच्छानुसार ही करना होगा। वैसे हल्के गुलाबी रंग की नेल पालिश हर एक पर अच्छी लगती है। उचित होगा कि आप भिन्न–भिन्न रंग की नेल पालिश का प्रयोग न करें। इससे नाखून की मौलिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नाखूनों को सुरक्षित रखने तथा उन्हें खूबसूरत बनाने के लिए निम्नांकित उपायों को करना चाहिए।

नेल पालिश लगाने से पहले नाखूनों की सफाई अच्छी तरह कर लीजिए तथा सुखाने के बाद ही नेल पालिश लगाइए।

अधिक समय तक अथवा बार बार पानी एवं डिटर्जेंट साबुन के घोलों से नाखूनों को बचाइए।

कपड़े, बर्तन आदि धोने के पश्चात हाथों को साफ सूखे कपड़े से पोंछकर उस पर जैतून या नारियल तेल लगा लीजिए।

कम समय के अंतराल से बार–बार नेल पालिश के प्रयोग से भी नाखूनों को हानि पहुंचती है अतः इसकी अवधि अधिक होना आवश्यक है।

इस प्रकार के नेल पालिश या सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग न करें जिससे त्वचा को एलर्जी हो।

मधुमेह के रोगियों को बार–बार नाखूनों में इंफेक्शन हो जाया करता है अतः समय–समय पर चिकित्सकीय जांच भी करवाते रहना चाहिए।

मनोचिकित्साः एक सुलभ चिकित्सा

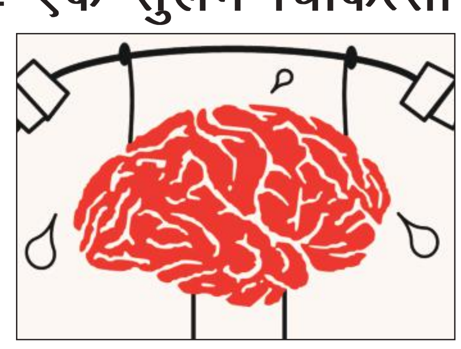

आज मनोचिकित्सा (जिसके अन्तर्गत चिकित्सक एवं रोगी में आपने–सामने बैठकर समस्याओं पर विचार होता है) दिनों–दिन प्रसिद्धि पाती जा रही हैं। मनोचिकित्सक, इस विधि के अन्तर्गत रोगी के साथ अत्यंत हमदर्दी एवं सहृदयता के साथ व्यवहार करता है तथा समस्याओं पर काबू पाने के लिए अत्यन्त सुगम एवं सुरीला रास्ता बताता है। भावनाओं के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए मनोचिकित्सा एक अत्यंत सुरक्षित एवं मान्यता प्राप्त साधन है जिससे हम अपनी जिंदगी को अत्यंत आसान एवं प्रसन्न बना सकते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग वही बातें करते हैं जिसे वह अनुभव करते हैं बजाय अपने हाव–भावों के अनुसार। इसके अलावा व्यक्ति का आचरण भी उसकी भावना के अनुसार हो जाता है। इस तरह की प्रक्रिया में वास्तविकता एवं बुद्धिमता मनोचिकित्सक से रोगी में स्थानांतरित हो जाती है, ऐसा प्रायः देखने में आया है, अर्थात रोगी अपने–आपको एक सामान्य एवं स्वस्थ व्यक्ति के रूप में अनुभव करने लगता है। मनोचिकित्सक का सीधा स्वभाव विचलित रोगी को प्रसन्नता का अनुभव कराता है लेकिन कभी स्वयं चिकित्सक को तीव्र हाव–भाव भी दिखाने पड़ सकते हैं अगर मामला उल्टा हो अर्थात रोगी असामान्य रूप से सीधे स्वभाव का होता है जिसे अपने कार्यकलापों के खतरे का अनुभव नहीं होता है लेकिन एक मनोचिकित्सक इस प्रकार की स्थिति को दूर करने में समर्थ हो जाता है क्योंकि वे आपस में विरोधी मान्यताओं को समझते हैं तथा उन्हीं मान्यताओं का प्रयोग करते हैं जो वास्तव में कारगर सिद्व हैं। एक अच्छा मनोचिकित्सक वह है जो लोगों की समस्याओं को समझ कर उनके दुख को दूर करता है। इसके अलावा एक अच्छा मनोचिकित्सक रोगी की हिचकिचाहट को दूर कर उसे वह सब कुछ करने को प्रेरित करता है जिसे वह कर पाने में असमर्थ पाता है। इसके रोगी को किन–किन परिस्थितियों से उबारने की जरूरत है। स्वाभाविक रूप से हमें उस मनोचिकित्सक की जरूरत नहीं है जो हमारी हर बात से सहमत हो। एक ऐसा मनोचिकित्सक चुनें जो व्यक्ति को उसके जीवन में अधिक जिम्मेदारियां संभालने के लिए प्रेरित करे। ऐसा चिकित्सक जो हमारे हावभावों, विचारों एवं बुद्धि के साथ तालमेल बैठाकर, जीवन में एक नयी उम्मीद का संचार करता है, ही कारगर सिद्व होता है। मनोचिकित्सा का सहारा लेना काफी लाभदायक सिद्ध होता है क्योंकि एक मनोचिकित्सक प्रायः स्थिति को एक भावनात्मक तरीके से देखता है, रोगी को असीमित धैर्य के साथ सुनता है, एक नयी उम्मीद का संचार करता है तथा अपने यकीन की भावना को बढावा देता है। यह चिकित्सा उस स्थिति में उत्तमरूप से कारगर सिद्व होती है जब व्यक्ति को वह सब कुछ करने के लिए कहा जाय जिसे वह करना नहीं चाहता। तभी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ अनुभव कर सकता है। मनोचिकित्सक की सहायता से व्यक्ति के आचरण का गहराई से अध्ययन किया जा सकता है तथा वह वह प्रतिकूल एवं हानिकारक वातावरण से भी कुछ हद तक छुटकारा पा लेता है। लोग मनोचिकित्सक को उनसे बात करने के लिए फीस देते हैं अतः एक मनोचिकित्सक का यह कर्तव्य है कि वह उनके जीवन को कठिनाइयों से उबार कर सरल एवं सजीव बनाए। यह कहा जा सकता है कि मनोचिकित्सा लोगों की मुसीबतों एवं दुखों को दूर करने के लिए एक अत्यंत सफल साधन है। जीवन दुखों से नहीं बल्कि प्रसन्नता से परिपूर्ण एक संगम है जिसमें सुख–दुख, उतार–चढ़ाव लगे ही रहते हैं। हमें यह जान लेना चाहिए कि पहले हम अपनी समस्याओं को अपने विचारों में बांधें तथा इसी विचारपूर्ण स्थिति में समस्या का समाधान करें। एक मनोचिकित्सक इसी विचारपूर्ण हल प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। मनोचिकित्सकों का यह मानना है कि बचपन में भोगी मुसीबतें आगे जाकर अनेक रूपों जैसे वैवाहिक मुसीबतों, आसामान्य रूप से खाना, अल्कोहल की लत एवं अन्य अनेक समस्याओं के रूप में उभरती हैं।

मनोचिकित्सक उन लोगों के लिए काफी प्रभावी सिद्व होता है जो अपने आचरण एवं जानकारी संबंधी गड़बड़ियों को स्थायी रूप से समाप्त करना चाहते हैं। लोगों के स्वयं के विचार एवं व्यवहार असामान्य रूप से तीखे एवं भर्त्सनापूर्ण होते हैं जो बिलकुल जरूरी नहीं है। इन्ही उदासीन एवं तकलीफदेह विचारों के बार–बार आने के कारण ही जीवन धीरे–धीरे पतन की तरफ चलता जाता हे। जीवन तब तक नीरस बना रहता है जब तक व्यक्ति को यह अनुभव नहीं होता कि जीवन एक हंसती–खेलती, सजीव, प्रभावकारी एवं उत्साहवर्धक प्रक्रिया है।

'वाराणसी' प्रियंका चोपड़ा जोनास की अगली बड़ी फिल्म होगी : निक जोनास

नयी दिल्ली, फोकस न्यूज, पॉप गायक निक जोनास को पूरा यकीन है कि उनकी पत्नी प्रियंका चोपड़ा जोनास की आने वाली तेलुगु भाषा की एक्शन–एडवेंचर फिल्म 'वाराणसी' शानदार होगी। 'आरआरआर' और 'बाहुबली' जैसी प्रशंसित फिल्मों के लिए मशहूर एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित इस फिल्म में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी नजर आएंगे। जोनास ने बताया कि प्रियंका पिछले 14 महीनों से फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। उन्होंने 'जैक सैंग शो' के एक पॉडकास्ट में कहा, "प्रियंका पिछले 14 महीनों से रुक–रुक कर शूटिंग कर रही हैं। यह एसएस राजामौली की दक्षिण भारतीय फिल्म है, जिन्होंने 'आरआरआर' का निर्देशन किया था। यह उनकी अगली बड़ी फिल्म है। यह शानदार होने वाली है।" फिल्म सात अप्रैल, 2027 को रिलीज होगी। 'वाराणसी' के अलावा, प्रियंका 'द ब्लफ' में भी नजर आएंगी। फ्रैंक ई फ्लावर्स द्वारा लिखित व निर्देशित फिल्म 'द ब्लफ' 25 फरवरी से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी।

बॉलीवुड में डेब्यू की तैयारियों में जुटी हैं ईशा मालवीय ?

टीवी शो उड़ारियां से फेम हासिल करने वाली एक्ट्रेस ईशा मालवीय इन दिनों अपने बॉलीवुड डेब्यू को लेकर चर्चा में हैं। इस तरह की खबरें है कि टीवी पर अपना जलवा बिखेरने के बाद जल्दी ही वह एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म और प्रोडक्शन हाउस की डिटेल्स फिलहाल एक खास स्ट्रेटेजी के तहत गुप्त रखी गई हैं लेकिन अंदर के सूत्रों का कहना है कि यह कोई साधारण फिल्म नहीं है बल्कि एक हाई–स्केल प्रोजेक्ट है। रिपोर्टस के अनुंसार ईशा मालवीय जल्द ही इस प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू करने वाली हैं। उम्मीद की जा रही है कि यह ईशा का बॉलीवुड में बड़ा डेब्यू साबित हो सकता है। फिलहाल ईशा एक पंजाबी फिल्म इश्कां दे लेखे की शूटिंग में बिजी है, जिसके दारा वह पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रही हैं। इस फिल्म में वो पंजाबी सिंगर और एक्टर गुरनाम भुल्लर के संग रोमांस करती हुई दिखाई देंगी। मनवीर बराड़ दारा निर्देशित उनकी ये रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म 6 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। पिछले कुछ दिनों से ईशा मालवीय के पब्लिक अपीयरेंस में भी एक बड़ा बदलाव देखने में आ रहा है। फैंस तो जैसे उनकी अपीयरेंस और लुक पर मर ही मिटे हैं। ईशा मालवीय सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी नई–नई तस्वीरों से ऑडियंस को अपना मुरीद बना लेती हैं। हर बार ही वह अपने लुक्स और फैशन सेंस से ऑडियंस का दिल चुरा लेती हैं। फैंस उनकी हर एक अदा पर अपना दिल हार बैठते हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 3.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

साई पल्लवी, जुनैद खान की 'एक दिन' के लिए गाना गाएंगे अरिजीत सिंह

नयी दिल्ली, (भाषा) पार्श्च गायन से संन्यास लेने की घोषणा कर प्रशंसकों को चौंका देने वाले गायक अरिजीत सिंह ने साई पल्लवी और जुनैद खान अभिनीत फिल्म 'एक दिन' के लिए गाना गाने की हामी भर दी है। निर्माताओं ने सोमवार को यह घोषणा की। 'एक दिन' के निर्देशन की जिम्मेदारी सुनील पांडे संभाल रहे हैं, जो बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म है। यह फिल्म एक मई को सिनमेघरों में दस्तक देगी। निर्माता 'आमिर खान प्रोडक्शंस' ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में जानकारी दी कि अरिजीत 'एक दिन' के गाने को आवाज देंगे। कंपनी ने लिखा, "'एक दिन' के संगीत में इस कदर जान फूंकने के लिए धन्यवाद अरिजीत।" अरिजीत ने 27 जनवरी को पार्श्व गायन से संन्यास लेने की स्तब्ध कर देने वाली घोषणा की थी। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था, "नमस्कार। आप सभी को नये साल की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं के रूप में इतने वर्षों तक मुझे इतना प्यार देने के लिए मैं आप सभी का आभार जताना चाहता हूं। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब से मैं पार्श्व गायक के रूप में कोई नया काम नहीं लूंगा। मैं पार्श्व गायन को अलविदा कह रहा हूं। यह एक शानदार सफर रहा।"

अमिताभ बच्चन ने पड़ोसी को 'जलसा' में आमंत्रित किया

नयी दिल्ली, (भाषा) बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने पड़ोसी व प्रशंसक निर्मित जेसरानी को अपने घर आमंत्रित कर चौंका दिया। निर्मित एक वायरल वीडियो में अपनी बालकनी से अमिताभ बच्चन का अभिवादन करते हुए नजर आए थे, जिसमें बाद उन्हें यह आमंत्रण मिला। निर्मित ने सोमवार को 'इंस्टाग्राम' पर अमिताभ बच्चन के साथ एक तस्वीर साझा की और कहा कि इस अवसर के लिए वह बेहद आभारी हैं। उन्होंने कहा, "विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा हुआ। अमिताभ बच्चन जी से मिलने का सौभाग्य मिला। इस अवसर और उनके इस प्यारे व्यवहार के लिए मैं बहुत आभारी हूं। उनके घर से 'संडे दर्शन' का सीधा प्रसारण देखा और वाह। ऊर्जा तो बिल्कुल अद्भुत थी। सचमुच अविस्मरणीय।" निर्मित ने बताया कि उन्हें अमिताभ की टीम से मुलाकात का संदेश मिला था। निर्मित और अमिताभ बच्चन की मुलाकात रविवार को हुई थी। उन्होंने वीडियो में कहा, "मुझे बिग बी (अमिताभ बच्चन) की टीम से संदेश मिला कि सर हमसे शाम पांच बजे मिलेंगे। हमने सर का इंतजार किया, वे आए और हमने अपनी आंखों से, उनके घर से ही, 'संडे दर्शन' लाइव देखा। जब वे आए, तो हमने उनके पैर छुए लेकिन उन्होंने हमें ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने बड़े प्यार से ग्रुप फोटो खिंचवाई, फिर मैंने उनसे अकेले फोटो खिंचवाने का अनुरोध किया और वे मान गए। उन्होंने हमें अपने फोन से फोटो खींचने की भी इजाजत दी।" निर्मित ने कहा, "वह (अमिताभ) इतने विनम्र और सरल स्वभाव के हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पहली बार मुझे उनके घर जाने का मौका मिला। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अमिताभ सर के घर गया और उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला। यह बहुत बड़ी बात है। मुझे आपसे मिलने का मौका देने के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद, सर। सपने सच होते हैं!" अमिताभ बच्चन हर रविवार को अपने उन प्रशंसकों का अभिवादन करते हैं, जो उनकी एक झलक पाने के लिए उनके घर के आसपास जमा होते हैं।

राजस्थान के बजट में राज्य स्तरीय परीक्षा एजेंसी बनाने की घोषणा

जयपुर, (भाषा) राजस्थान के आगामी वित्त वर्ष के बजट में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा एजेंसी (आरएसटीए) बनाने, किसानों को कार्बन क्रेडिट दिलवाकर प्रोत्साहन राशि दिलाने के लिए परियोजना शुरू करने और सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर विचार के लिए उच्चस्तरीय समिति बनाने जैसी दूसरी घोषणाएं शामिल हैं। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए बजट बुधवार को राज्य विधानसभा में पेश किया। बजट का कुल आकार छह लाख 10,956 करोड़ रुपये है। आलोच्य वर्ष के बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियां 3.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक व राजस्व व्यय लगभग 3.50 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इसमें राजस्व घाटा 24,313 करोड़ रुपये रहना अनुमानित है। वहीं बजट में राजकोषीय घाटा लगभग 79,492 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 3.69 प्रतिशत है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि यह बजट 'विकसित राजस्थान 2047' दृष्टिकोण दस्तावेज को वास्तविकता में बदलने की कार्ययोजना है। बजट के बाद उन्होंने कहा, "आज हमने 2026–27 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया है जो हमारे 'विकसित राजस्थान 2047' दृष्टिकोण दस्तावेज को वास्तविकता में बदलने की कार्ययोजना है।" उन्होंने कहा कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय पहली बार दो लाख रुपये से अधिक हो गई है। दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में कहा, '' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास व सबका प्रयास' के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रदेश को आर्थिक समृद्धि, सतत व समावेशी विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं।''

उन्होंने कहा, '' विकसित राजस्थान/2047 को साकार करने के लिए इस विकास यात्रा में गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी शक्ति की अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नीत हमारी सरकार ने सेवा, समर्पण एवं सुशासन को प्राथमिकता दी है। '' नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की तर्ज पर राज्य में आरएसटीए बनाने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाएं बड़े पैमाने पर निर्बाध एवं समयबद्ध रूप से सप्ताह के सभी दिवसों में हो सके, इसके लिए ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधायुक्त टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिभावान विद्यार्थियों के नवाचार व्यावहारिक रूप से स्टार्टअप के रूप में विकसित हो सके, इसके लिए 'मेंटरशिप, आंत्रप्रेन्योरशिप, इनक्यूबेशन' सुविधाएं उपलब्ध करवाना आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक जिले के चयनित महाविद्यालय में 'वाइब्रेंट' (वैल्यू–ड्रिवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एस्पिरेशन एंड नर्चरिंग टैलेंट) कार्यक्रम चलाया जायेगा। उन्होंने कहा कि 'नशामुक्त राजस्थान' की संकल्पना को साकार करने के लिए अंतर विभागीय समन्वित कार्यक्रम राज–सवेरा (स्टेटवाइड एंटी–ड्रग्स विजिलेंस, एनफोर्समेंट, रिहैबिलिटेशन एंड अवेयरनेस) शुरू किया जाएगा। इसके तहत दवा विक्रेता स्तर पर 'साइकोट्रोपिक' दवाओं की बिक्री पर नजर रखने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनेगा, जिला चिकित्सालयों में नशामुक्ति वार्ड बनेंगे। साथ ही विश्वविद्यालयों एवं चयनित महाविद्यालयों में भी नशा मुक्ति केंद्र शुरू किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए रोजगारपरक कौशल, करियर मार्गदर्शन व 'डिजिटल मेंटरिंग' के उद्देश्य से ड्रीम (डिजिटल रेडिनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेड मेंटरिंग) कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके पहले चरण में लगभग 50 हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इसी तरह सेवा सुश्रूषा, सूचना प्रौद्योगिकी व स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में वैश्विक रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए एक हजार युवाओं को अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और कोरियाई जैसी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि घुमंतू एवं अर्ध–घुमंतू समुदाय यानी खानाबदोश परिवारों के बच्चों के लिए 'पहल' (पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग) कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके पहले चरण में हर जिले में एक 'स्कूल ऑन व्हील्स' बनाया जाएगा और विस्थापन वाले इलाकों में अस्थायी शिक्षा शिविर संचालित किये जायेंगे। दिया कुमारी ने इस बजट में कृषि बजट भी पेश किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य किया जाना आवश्यक है। इसके लिए किसानों को 'चेंज एजेंट' के रूप में स्थापित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई, कृषि वानिकी जैसे अच्छे कृषि व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जायेगा। इससे हुए सकारात्मक बदलाव के आधार पर किसानों को कार्बन क्रेडिट दिलवाकर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में पहली बार 'कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट' शुरू किया जाएगा।

राजस्थान का वार्षिक बजट 2026–27 : विकास, संतुलन और जनकल्याण की भावनाओं से भरा

गोपेन्द्र नाथ भट्ट

राजस्थान विधानसभा में बुधवार को राज्य की उप मुख्यमंत्री और वित्त मन्त्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026–27 का वार्षिक बजट राज्य की आर्थिक दिशा, विकास प्राथमिकताओं और राजनीतिक संकल्पों का प्रतिबिंब माना जा रहा है। यह बजट ऐसे समय में आया है जब राज्य एक ओर बुनियादी ढांचे के विस्तार, औद्योगिक निवेश और पर्यटन विकास की नई संभावनाओं की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर वित्तीय अनुशासन, बढ़ते राजकोषीय दबाव और सामाजिक दायित्वों की चुनौतियों से भी जूझ रहा है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि बजट को केवल घोषणाओं के संदर्भ में नहीं, बल्कि उसके दीर्घकालिक प्रभावों के आधार पर परखा जाए। बजट भाषण में भाषण के दौरान दिया कुमारी ने शेरों शायरियाँ से अपनी बात रखी और कहा कि हमें आता है दरिया पार करना!!बजट में आधारभूत संरचना और कनेक्टिविटी पर फोकस किया गया है विशेष कर सड़कों, ग्रामीण संपर्क मार्गों, शहरी परिवहन, रेल परियोजनाओं के सहयोग और औद्योगिक कॉरिडोर के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। राजस्थान जैसे विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्य के लिए कनेक्टिविटी आर्थिक विकास की धुरी है। नए औद्योगिक क्षेत्रों, लॉजिस्टिक पार्कों और पर्यटन सर्किटों के विकास के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश सकारात्मक संकेत है। यदि इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से होता है, तो यह राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्राथमिकता से रखा गया है । राजस्थान की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। बजट में सिंचाई परियोजनाओं, जल संरक्षण, फसल बीमा और कृषि यंत्रीकरण के लिए प्रावधान किए गए हैं। मरुस्थलीय और अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि जल संसाधनों के संरक्षण, माइक्रो इरिगेशन और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा मिलता है, तो किसानों की आय में स्थायी वृद्धि संभव है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र का भी बजट में विशेष ध्यान रखा है।मानव संसाधन विकास किसी भी राज्य की दीर्घकालिक प्रगति की आधारशिला होता है। बजट में स्कूलों के उन्नयन, डिजिटल शिक्षा, मेडिकल कॉलेजों के विस्तार और जिला अस्पतालों की सुविधाओं में सुधार की घोषणाएं की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों और शिक्षकों की कमी एक स्थायी समस्या रही है। यदि भर्ती प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता लाई जाती है, तो यह क्षेत्र वास्तविक सुधार देख सकता है। 'राइजिंग राजस्थान' जैसे निवेशक सम्मेलनों के बाद राज्य सरकार पर निवेश को जमीन पर उतारना चाहती है। बजट में उद्योग, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने की दृष्टि से एमएसएमई, स्टार्टअप, टेक्सटाइल, स्टोन उद्योग और पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की नीति स्पष्ट दिखाई देती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र और कौशल विकास कार्यक्रम रोजगार सृजन में मददगार हो सकते हैं। हालांकि, यह देखना होगा कि घोषित एमओयू वास्तविक निवेश में कितने परिवर्तित होते हैं। बजट में सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण योजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य की राजनीति में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। पेंशन, महिला सशक्तिकरण, छात्रवृत्ति और कमजोर वर्गों के लिए आवास योजनाओं का विस्तार बजट की प्रमुख विशेषता है। लेकिन इन योजनाओं पर बढ़ता व्यय राजकोषीय संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सरकार को आय के स्रोत बढ़ाने और व्यर्थ व्यय पर नियंत्रण की रणनीति स्पष्ट करनी होगी।

वित्तीय अनुशासन और राजकोषीय स्थिति: किसी भी बजट की सफलता केवल व्यय बढ़ाने से नहीं, बल्कि संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन से तय होती है। यदि राजस्व संग्रह में वृद्धि, कर सुधार और केंद्र से मिलने वाले अनुदानों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाता है, तो राज्य वित्तीय स्थिरता की ओर बढ़ सकता है अन्यथा बढ़ता घाटा भविष्य में विकास योजनाओं पर दबाव डाल सकता है। राजस्थान की पहचान उसके पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी है। बजट में पर्यटन सर्किट, धार्मिक स्थलों के विकास और विरासत संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं। इससे स्थानीय रोजगार और विदेशी निवेश दोनों को बढ़ावा मिल सकता है। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर जैसे शहरों के साथ–साथ नए गंतव्यों को विकसित करना समय की मांग है। राजस्थान का बजट 2026–27 संतुलित विकास की दिशा में एक प्रयास प्रतीत होता है, जिसमें आधारभूत संरचना, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग सभी को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि किसी भी बजट की असली परीक्षा उसके क्रियान्वयन में होती है। यदि सरकार घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से लागू कर पाती है और वित्तीय अनुशासन बनाए रखती है, तो यह बजट राज्य को आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन की दिशा में आगे ले जा सकता है। राजस्थान के वार्षिक बजट 2026–27 में कई प्रमुख घोषणाएँ की गईं, जो सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत ढांचा, रोजगार, जल, ऊर्जा और युवाओं के सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। जल आपूर्ति और पेयजल सुरक्षा के अंतर्गत टैप वाटर कनेक्शन: बजट में लगभग 6,800 करोड़ का प्रावधान किया गया है ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर घर तक पाइप्ड पानी की सुविधा पहुंच सके। सीएम जल जीवन मिशन के अंतर्गत 6,500 से अधिक गाँवों को जोड़ने और लाखों नए कनेक्शनों के लिए काम जारी रहेगा। स्वच्छ ऊर्जा और सौर परियोजनाएँ के राहत नए सोलर पार्क: बीकानेर और जैसलमेर में लगभग 3,000 करोड़ की लागत से बड़े सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिससे राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी। रोजगार और स्वरोजगार के अधीन मुख्यमंत्री सेल्फ–एम्प्लॉयमेंट योजना के तहत 10 लाख तक के ब्याज–रहित ऋण और अनुदान प्रदान किए जाएंगे, जिससे लगभग 30,000 युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल सकेंगे। सड़क विकास के तहत लगभग 42,000 किमी सड़क नेटवर्क का विकास और 250 'अटल प्रगति पथ' का निर्माण किया जाएगा, जिससे ग्रामीण व शहरी कनेक्टिविटी में सुधार होगा। राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के समान एक राज्य–स्तरीय टेस्टिंग एजेंसी स्थापित की जाएगी, जो प्रतियोगी परीक्षाओं/ऑनलाइन टेस्ट का संचालन करेगी। कॉलेज छात्रों के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें लगभग 50,000 छात्रों को शामिल किया जाएगा। 1,000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियाई भाषा में प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी। राज्य में नए टेक्नो हब्स विकसित किए जाएंगे (लगभग 30 करोड़ खर्च), जो तकनीकी उद्यमों को बढ़ावा देंगे। एल कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 20,000 तक की सहायता ई–वाउचर के रूप में मिलेगी। पानी सप्लाई परियोजनाओं के लिए 24,000 करोड़ के कार्य आदेश जारी किए गए हैं, जिनके अंतर्गत अगले वर्ष लाखों नए कनेक्शनों को जोड़ा जाएगा। नए औद्योगिक पार्कों के निर्माण के लिए लगभग 350 करोड़ आवंटित किए जाएंगे, और 3,600 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाएगा (जोधपुर–पाली–मारवाड़ उद्योग क्षेत्र में)। राज्य में इनलैंड कंटेनर डिपो स्थापित कर लॉजिस्टिक नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 14 नए अध्याय शुरू किए जाएंगे (जैसे दक्षिण अफ़्रीका और कनाडा में), जो राज्य की सांस्कृतिक विरासत को विश्व स्तर पर प्रमोट करेंगे। लगभग 15 करोड़ का प्रावधान के साथ मिट्टी के कुम्हारों को इलेक्ट्रिक कुम्हार घड़ियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। कुल मिला कर –2026–27 वर्ष का राजस्थान बजट विकासोन्मुख है और विशेष रूप से पेयजल, स्वच्छ ऊर्जा, रोजगार सृजन, सड़क एवं शिक्षा क्षेत्र पर जोर देता है। यह बजट युवाओं, किसानों, ग्रामीण आबादी और स्वरोजगार चाहने वालों के पक्ष में कई सकारात्मक घोषणाएँ प्रस्तुत करता है।

भारत–अमेरिका व्यापार करार से कुछ फल उत्पादक परेशान, तो कुछ ने बताया अवसर

श्रीनगर, (भाषा) जम्मू–कश्मीर में कुछ फल उत्पादक और डीलर भारत–अमेरिका व्यापार समझौते के स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बुरे असर को लेकर परेशान हैं, लेकिन इस समूह में कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इस समझौते से कीमतें स्थिर होंगी और स्थानीय पैदावार की गुणवत्ता बेहतर होगी। हालांकि, फल उत्पादकों की आम बिरादरी को लगता है कि यह व्यापार समझौता कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका होगी, जो राज्य काफी हद तक बागवानी पर निर्भर है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के अखरोट उगाने वाले किसान और डीलर जावेद अहमद लोन ने कहा कि अमेरिका से आयातित सामान स्थानीय किसानों को अपना स्टॉक बेहतर करने पर मजबूर करेगा, यदि वे व्यवसाय में बने रहना चाहते हैं। लोन ने पीटीआई भाषा से कहा, ''संरक्षणवाद हर समय किसानों के लिए अच्छा नहीं होता। वे लापरवाह हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एक स्थापित बाजार होता है। उदाहरण के लिए, कश्मीर में स्थानीय बादाम और अखरोट की कीमत शेयर बाजार की तरह ऊपर–नीचे होती रहती है। किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है।'' उन्होंने कहा कि अमेरिका से अखरोट और बादाम के लगातार आने से स्थानीय पैदावार के दाम भी स्थिर हो जाएंगे। उन्होंने कहा, ''आयातित अखरोट और बादाम की गुणवत्ता बेहतर है और शुल्क के कारण वे पहले से ही बहुत प्रतिस्पर्धी थे। स्थानीय किसानों को भी अपनी गुणवत्ता सुधारनी होगी। प्रतिस्पर्धा का यही फायदा है।'' फल उगाने वालों और डीलर यूनियन के अध्यक्ष, बशीर अहमद बशीर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि आयातित सेबों पर कम शुल्क से कश्मीर और हिमाचल के सेबों को बहुत नुकसान होगा। बशीर ने कहा, ''ईरान, अमेरिका, न्यूज़ीलैंड से सेब के आयात से छोटे किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बढ़ती लागत, मौसम में अचानक बदलाव और कीटों के फैलने से पूरा बागवानी क्षेत्र वित्तीय संकट में आ गया है। शुल्क में कमी ताबूत में आखिरी कील साबित होगी।'' उन्होंने कहा कि विदेशी सेबों पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगाना समय की मांग है। उन्होंने कहा, ''अगर भारत में आयातित सेबों को खुली छूट मिल गई, तो बागवानी अर्थव्यवस्था संकट में पड़ जाएगी।'' बागवानी विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जम्मू–कश्मीर में करीब 20 लाख लोग सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर बागवानी की गतिविधियों से अपनी रोजी–रोटी कमाते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को भारत–अमेरिकी अंतरिम व्यापार समझौते पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि इससे केंद्र शासित प्रदेश की सूखे मेवे और बागवानी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। अब्दुल्ला ने कहा कि अखरोट और बादाम जैसे मेवों और फलों के शुल्क मुक्त आयात से स्थानीय किसानों को नुकसान हो सकता है। अब्दुल्ला ने कहा, ''पेडों से प्राप्त होने वाले खाद्य उत्पाद (ट्री नट्स), अखरोट और बादाम जम्मू–कश्मीर से आते हैं। इन उत्पादों के बाहर से शुल्क मुक्त आयात की इजाज़त देना हमारे किसानों के लिए ठीक नहीं है।'' विपक्षी पार्टी पीडीपी ने दावा किया कि अगर अमेरिका से खेती और बागवानी के सामान के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया तो भारत–अमेरिका व्यापार समझौता, जम्मू–कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए बर्बादी का कारण बनेगी। पीडीपी के प्रवक्ता मोहम्मद इकबाल ट्रंबू ने कहा, ''उन्होंने जम्मू–कश्मीर के बागवानी क्षेत्र पर भारत अमेरिका व्यापार समझौता के असर के बारे में नहीं सोचा है। अमेरिका से आयात होने वाले कृषि उत्पादों पर शून्य शुल्क होगा। ऐसे में जम्मू–कश्मीर में पैदा होने वाले सेब और अखरोट का क्या होगा?''

सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा हिंदू हैं: महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे

मुंबई, (भाषा) मुंबई में आरएसएस के एक कार्यक्रम में अभिनेता सलमान खान की मौजूदगी को लेकर विवाद के बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता एवं महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए मंगलवार को कहा कि अभिनेता सलमान खान उनसे ''अधिक हिंदू'' हैं। खान समेत सिनेमा जगत की विभिन्न हस्तियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया था। पिछले सप्ताहांत नेहरू केंद्र में यह कार्यक्रम आरएसएस के शताब्दी समारोह के तहत आयोजित किया गया था। ठाकरे के करीबी सहयोगी, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत ने आरएसएस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अभिनेता सलमान खान पर निशाना साधा था। एक पत्रकार के सवाल पर राणे ने खान की प्रशंसा की और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी ठाकरे पर हमला बोला।

क्या हम डिजिटल दुनिया की मानसिक गुलामी की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहे हैं?

डिजिटल इंडिया बहुत तेजी के साथ साकार हुआ । सरकार की मंशा डिजिटल क्रांति के माध्यम से व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचाने के साथ नवाचार को प्रोत्साहित कर युवा ऊर्जा को ज्ञान बिज्ञान के शोध में प्रबृत्त कर मानवता के कल्याण के लिए उत्साहित प्रोत्साहित करना है और परिणाम आ भी रहे हैं भारतीय तकनीकी संस्थानों द्बारा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र नये नये शोध और उपकरण विकसित कर असाध्य रोगों की पहचान उनका उपचार इन सब क्षेत्रों में बड़े सराहनीय कार्य हो रहे हैं । डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से व्यावसायिक लेन देन खरीद फरोख्त में पारदर्शिता आई है. यह सब डिजिटल इंडिया साकार होने के सकारात्मक पहलू हैं लेकिन डिजिटल इंडिया साकार होने का चिंतित करने वाला कारक यह है कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के मानसिक गुलामी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं सरकार और समाज को इस पर गंभीर चितन कर प्रभावी मार्ग निकालना होगा अन्यथा आज टेक्नोलॉजी और हथियारों के विकास से अपने को दुनिया का बॉस अपने को बताने वाले मुल्क के बॉस जैसे लोगो की कारगुजारी कहाँ तक पहुंचेगी ठिकाना नहीं. भारतीय उपमहाद्बीप में श्रीलंका, बांग्लादेश , पाकिस्तान और नेपाल इसके प्रमाण है जहाँ इंटरनेट के माध्यम से परोसे जा रहे विषय वस्तु या डिजिटल भाषा में कंटेंट को दुनिया के बॉस कहने वाले मुल्क ने अपना मनचाहा बदलाव करा दिया । हम उस पर न भी सोचे तो भी वर्तमान में डिजिटल माध्यम से जो विषय वस्तु इंटरनेट प्लेटफार्म पर परोसी जा रही है, उसका दुष्प्रभाव आज हम अपने समाज में स्पष्ट देख सकते हैं । औसतन 6–7 घंटे प्रतिदिन लोग मोबाइल फोन के साथ बिता रहे हैं. युवा पीढ़ी रील बनाने और देखने में कितना समय लगा रही है, किसी से छुपा नहीं है. परिवारों में, चौपालों पर, ट्रेनों में, पार्कों में प्रत्येक स्थानों से आपसी संवाद, चर्चाएं–परिचर्चाएं गायब हो गई हैं. समाज में आपसी संवाद सहकार सौहार्द की भावना लुप्त प्राय है जो भारतीय समाज की रीढ़ थी. अब सबके हाथ में मोबाइल गुरु है. सब उसी में व्यस्त हैं । स्कूल, कॉलेज से दैनन्दिनी सांस्कृतिक और स्पोर्ट्स गतिविधियां समाप्त प्राय होती जा रहीं हैं. आज युवा वर्ग तेजी के साथ मोटापे का शिकार हो रहा है और डायबिटीज, हृदय रोग, रक्तचाप और लीवर की बीमारियों से ग्रसित हो रहा है. जो रोग वृद्धावस्था में घेरते थे, वह वर्तमान में युवापीढ़ी को अपने चपेट में ले रहे हैं जो अत्यंत चिताजनक है । सरकारों के पुरजोर और प्रभावी प्रयास के बावजूद समाज में महिला अपराध बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. बलात्कार, हत्या जैसी घिनौनी प्रबृत्ति 6 माह, 8 माह तक की बच्चियों को भी नहीं छोड़ रही जो राक्षसी प्रबृत्तियों से मीलों आगे निकल गई है .आए दिन लिब इन में, अवैध संबंधों तथा अनेक तरह से यन्हा तक कि अपने माता पिता भाई बहन और अपने बच्चो की ही जिस जघन्यतम और क्रूरतम तरीके से हत्या और हिसा की घटनाये मीडिया माध्यमों से आये दिन सामने आती है, अंतर्मन को बुरी तरह झकझोर देता है. यह सब ओटीटी, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब तथा इंटरनेट पर परोसी जाने वाली सेक्स सामग्री, अश्लीलता, क्रूरतम हिसा और गाली गलौज की भाषा की ही देन है । भारत में परिवार को प्रथम पाठशाला कहा जाता था. अब प्रथम पाठशाला मोबाइल फोन हो गया है जहाँ 2 वर्ष के बच्चे भी मोबाइल चला रहे हैं। पति–पत्नी को अपनी नौकरी की व्यस्तताएं हो गई हैं. सब एकाकी परिवार हो गए हैं. बाबा. दादी. चाचा चाची से अब किसी को मतलब नहीं है. बच्चों को मोबाइल ही पकड़ा दिया जाता है । भारतीय समाज में संयुक्त परिवार होते थे. सब एक साथ रहते थे. बड़े बूढ़े बच्चों की देख रेख करते थे. किस्से कहानियाँ सुना कर उनमे सनातन संस्कृति के संस्कार पिरोते थे. निज गौरव स्वाभिमान, राष्ट्र प्रेम की गाथाये सुनाकर उन्हें राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते थे । आज के दौर में दलीले दी जाती हैं कि पति–पत्नी दोनों नहीं काम करेंगे तो घर नहीं चलेगा. तब एक व्यक्ति नौकरी करता था और अपने बच्चों परिवार सभी की शिक्षा पालन पोषण करता था.

आवश्यकताएं सीमित थी. आज तो हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं. परिणाम समाज के सामने है. हमने जो पश्चिमी दुनिया का तौर तरीके अपनाया, उसका परिणाम संक्रामक बीमारी की तरह विस्तारित होता अवसादजनित बीमारियों का जाल, आत्महत्या की प्रबृत्ति और असाध्य रोगों का विस्तार है । हम आज सनातन धर्म और संस्कृति की बहुत बात करते हैं. क्या सनातन धर्म और संस्कृति के मूल्यों की रक्षा ओटीटी ,नेटफ्लिक्स यूट्यूब या इंटरनेट जगत में व्याप्त सामग्री से कर सकेंगे ? वर्षों से टीवी और ओटीटी पर प्रसारित किए जाने वाले सीरियल्स ने हमारे परिवारों के परस्पर विश्वास भरोसे को तोड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है. हमारा सेंसर बोर्ड और नियामक संस्था पूरी तरह मौन हैं क्योंकि आज पूरी दुनिया के लिए भारत सबसे बड़ी बाजार है. दुनिया जो भी परोसेगी, यहाँ खपत हो जाएगा और यही हो रहा है । तथाकथित विकसित देशों का सारा कचरा जिसमे प्लॉस्टिक जैसा कचरा जो पर्यावरण को तहस नहस कर रहा है अब सबका डंपिग ग्राउंड भारत है क्योकि दुनिया के लिए हम सबसे बड़ा बाजार और यहाँ के निवासी उनके लिए वस्तु है । आज महानगरों या शहरों में पले बढ़े बच्चों और युवाओ को तो छोड़ दीजिए, गांवो की संस्कृति में पले बढ़े लोग भी गूगल गुरु में आँख बंद करके भरोसा करते है. परिणाम यह है जो गूगल महाराज के कारण बीभत्स हृदय बिदारक दुर्घटनाएं सामने आती है । कभी गूगल कार को सड़क से सीधा नदी में ले जाकर समा गए, कभी सीधा गड्ढे में कभी सीधा कुए में या 1०० –5० किमी किसी अन्यत्र मार्ग पर लेकिन बावजूद इसके आज युवा सड़क के किनारे कन्ही रुक कर मार्ग का स्पष्टीकरण लेने के बजाय गूगल महाराज के प्रति अंधभक्ति यह है कि हम भले भटकते रहे पर लेकिन टेक्नोलॉजी को सहायक के बजाय हमने अपनी बागडोर ही उसी को सौंप दी है जो भयावह है । टेक्नॉलजी मनुष्य मस्तिष्क की देन है. उसके एप्लिकेशन में त्रुटि हो सकती है, इसीलिए हमारे यहाँ बुद्धि से आगे विवेक को महत्व दिया गया है और टेक्नोलॉजी विवेक का विकल्प कभी भी नहीं बन सकती है। इंटरनेट युग ने हमारी चितन प्रक्रिया को अवरुद्ध कर दिया है. अध्ययन प्रक्रिया से हम दूर हो रहे हैं. व्यक्तित्व और व्यक्ति के निर्माण में अच्छे साहित्य, महापुरुषों के विचार उनके जीवन चरित्र उनका कृतित्व महापुरुषों की वाणी, ऋषियों मनीषियों का चितन प्रेरक प्रस किस्से कहानिया आदि महत्वपूर्ण कारक रहे है जिनका स्थान इंटरनेट की सामग्री ने ले लिया है. कम संख्या है जो इंटरनेट प्लेटफार्म का उपयोग प्रेरक और सकारात्मक विचारों को विकसित करने के लिए कर रही है. वह परसेंटेज बहुत अधिक है जो प्रदूषित सामग्री के प्रति आकर्षित है । हम श्रमशीलता से दूर हो रहे है . घरेलू उपयोग की आवश्यकताओं के लिए थोड़ी दूर टहलना हम भूल गए . दूध सब्जी के लिए भी अब गूगल का सहारा ले लिया है । हमारे बच्चे अब भवनों मे दो तीन तल की सीढ़िया चढ़ना उतरना नहीं चाहते. अपने निजी भवनों तक में लोग लिफ्ट लगाने लगे हैं । सहज ही आंकलन किया जा सकता है कि इस तरह की व्यवस्था जो टेक्नोलॉजी और उपभोक्ता बड़ी संस्कृति का नतीजा है, हमारे स्वास्थ्य की गुणवत्ता को कहाँ ले जाएगा ।

हमारी संस्कृति एकल परिवार की नहीं रही लेकिन हमने एकल संस्कृति को अपनाया. परिवारों में पति पत्नी अपने नौकरी और कार्यो में व्यस्त हो गए. छोटे छोटे बच्चों की देख रेख बाबा दादी करते थे, अब मोबाइल कर रहा है. बाबा दादी किस्से कहानियाँ सुनाकर उनमें सनातन संस्कृति के संस्कार पिरोते थे, अपनी मातृभूमि के प्रति भक्ति भरते थे. अब हम ग्लोबल हो रहे हैं. हमारी आवश्यकताएं सीमित थी. त्याग वृत्ति हमारी जीवन शैली थी. एक व्यक्ति संयुक्त परिवार का पालन पोषण करता था. आज हमारी आवश्यकताएं और अराजक महत्वाकांक्षाएँ सुरसा की तरह हैं । आज हम सनातनी होने का बहुत स्वांग रचते हैं. डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से जो कचरा हमारी युवा पीढ़ी को सेक्स, हिसा, नशा और व्यसनों का गुलाम बना रहा है. क्या हम उन्हें रोक सकते हैं। आंकड़े उपलब्ध होंगे जो बता सकते हैं कि डिजिटल प्लेटफार्म के सकारात्मक ज्ञान का उपयोग कितने प्रतिशत लोग कर रहे हैं और कितने प्रतिशत लोग कचरा अपने मन मस्तिष्क में भर रहे हैं, आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि संयम, अनुशासन और सकारात्मक ज्ञान ग्रहण करना कठिन होता है जबकि अवमूल्यन की तरफ ले जाने वाली सामग्री अत्यंत सहज है । आज वैश्विक संस्कृति अंगीकार करने का ही नतीजा है कि आने वाले 35–4० वर्ष बाद आज का युवा भारत पाश्चात्य दुनिया की तरह रिटायरमेंट ले रहा होगा और हम अपने देश में ही अल्पसंख्यक बन कर रह जाएँगे । रूस चीन जैसे देशों में इंटरनेट प्लेटफार्म पर कुछ भी डालने की अनुमति नहीं है अमेरिका में भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर पैरेंटल कंट्रोल है. बच्चे , किशोर और वयस्क होने से पहले युवाओं को भी इंटरनेट के अत्यंत सीमित उपयोग की स्वीकृति है न कि बच्चे से लेकर सभी इंटरनेट प्लेटफार्म पर पड़ी गंदगी मन मस्तिष्क में भरे । डिजिटल प्लेटफार्म हमे मानसिक गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं जहाँ चितन प्रक्रिया अध्यवसायिता और विवेक कुंद होता जा रहा है । अब ए आई ने तो कमाल ही कर दिया है. हम भी उसके प्रचार प्रसार में जोरो से लगे हैं । टेक्नोलॉजी का उपयोग मानवीय विकास के लिए जितना आवश्यक है, निश्चित होना चाहिए लेकिन टेक्नोलॉजी के हम मानसिक गुलाम न बने. टेक्नोलॉजी हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित न करने लगे जो अब हो रहा है. इस खतरे को समय रहते हमे पहचानना होगा और समाज के जागरूक लोगों को इसके चितन कर मार्ग निकालना होगा अन्यथा सब चलता है की हमारी सोच रही तो डोर हाथ से निकल जाएगी ।

हरीशचंद्र श्रीवास्तव

'न्यू स्टार्ट' संधि का तभी तक पालन करेंगे जब तक अमेरिका करेगाः रूस

मॉस्को, (एपी) रूस के एक शीर्ष राजनयिक ने बुधवार को कहा कि मॉस्को अमेरिका के साथ की गई अंतिम परमाणु हथियार संधि 'न्यू स्टार्ट' के तहत तय की गई सीमाओं का पालन करेगा, बशर्ते वाशिंगटन भी ऐसा ही करे। हालांकि, दोनों देशों के बीच की इस संधि की मियाद पिछले सप्ताह ही समाप्त हो चुकी है। 'न्यू स्टार्ट' संधि पांच फरवरी को समाप्त हो गई, जिससे आधी सदी से अधिक समय में पहली बार दो सबसे बड़े परमाणु शस्त्रागारों पर कोई अंकुश नहीं रह गया और अनियंत्रित परमाणु हथियारों की होड़ का डर बढ़ गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल घोषणा की थी कि अगर वाशिंगटन संधि का पालन करता है तो वह एक और साल के लिए संधि की सीमाओं का पालन करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तर्क है कि वे चाहते हैं कि चीन भी नई संधि का हिस्सा बने, जिसे बीजिंग ने अस्वीकार कर दिया है। बुधवार को संसद के निचले सदन को संबोधित करते हुए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भले ही अमेरिका ने पुतिन के प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन रूस न्यू स्टार्ट संधि की सीमाओं का तब तक सम्मान करेगा जब तक अमेरिका भी उनका पालन करता रहेगा। लावरोव ने सांसदों से कहा, "राष्ट्रपति द्वारा घोषित रोक तब तक लागू रहेगी जब तक अमेरिका इन सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता। हम अमेरिकी सैन्य नीतियों के विश्लेषण के आधार पर जिम्मेदारीपूर्ण और संतुलित तरीके से कार्य करेंगे।" लावरोव का बयान एक्सियोस की उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें दावा किया गया था कि रूसी और अमेरिकी वार्ताकारों ने पिछले सप्ताह अबू धाबी में हुई बातचीत के दौरान कम से कम छह महीने तक समझौते की सीमाओं का पालन करने के लिए एक संभावित अनौपचारिक समझौते पर चर्चा की थी। इस रिपोर्ट पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शुक्रवार को कहा कि ऐसा कोई भी विस्तार केवल औपचारिक हो सकता है। उन्होंने कहा कि "इस क्षेत्र में किसी भी अनौपचारिक विस्तार की कल्पना करना मुश्किल है।" इसी बीच, पेस्कोव ने पुष्टि की कि रूसी और अमेरिकी वार्ताकारों ने अबू धाबी में भविष्य में परमाणु हथियार पर नियंत्रण को लेकर चर्चा की, जहां मॉस्को, कीव और वाशिंगटन के प्रतिनिधिमंडलों ने यूक्रेन में शांति समझौते पर दो दिवसीय वार्ता की थी। 'न्यू स्टार्ट' संधि पर 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके रूसी समकक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने हस्ताक्षर किए थे। 'न्यू स्टार्ट' मॉस्को और वाशिंगटन के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए हुए समझौतों की लंबी श्रृंखला का अंतिम समझौता था, जिसकी शुरुआत 1972 में हुए साल्ट–एक समझौते से हुई थी। न्यू स्टार्ट समझौते के तहत दोनों पक्षों को अधिकतम 700 मिसाइलों और बमवर्षक विमानों पर अधिकतम 1,550 परमाणु हथियार रखने की अनुमति थी। यह समझौता मूल रूप से 2021 में समाप्त होने वाला था, लेकिन इसे पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया था। इस समझौते में अनुपालन की पुष्टि के लिए व्यापक स्तर पर निरीक्षण की परिकल्पना की गई थी, हालांकि कोविड–19 महामारी के कारण 2020 में ये निरीक्षण रोक दिए गए और फिर कभी शुरू नहीं किये गए।

एसबीआई बाजार पूंजीकरण के मामले में चौथे स्थान पर, टीसीएस को पीछे छोड़ा

मुंबई, (भाषा) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) मजबूत तिमाही नतीजों के बाद आई तेजी के दम पर बुधवार को बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की चौथी सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। अक्टूबर–दिसंबर तिमाही के मजबूत नतीजों के बाद बैंक के शेयरों में तीन प्रतिशत से अधिक की तेजी आने से उसने दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को पीछे छोड़ दिया। बीएसई पर एसबीआई का शेयर 3.40 प्रतिशत बढ़कर 1,183 रुपये पर बंद हुआ, जबकि एनएसई पर यह 3.23 प्रतिशत चढ़कर 1,181.10 रुपये पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान यह शेयर लगभग चार प्रतिशत चढ़कर अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर बीएसई पर 1,187.70 रुपये और एनएसई पर 1,187.50 रुपये तक पहुंच गया। कारोबार के अंत में एसबीआई का बाजार पूंजीकरण 10,91,982.06 करोड़ रुपये रहा, जो बीएसई पर टीसीएस के 10,52,646.38 करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण से अधिक है। इस बीच टीसीएस का शेयर 2.5 प्रतिशत टूटकर बीएसई और एनएसई पर क्रमशः 2,909.40 रुपये और 2,909 रुपये के भाव पर बंद हुए। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है। इसके बाद एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, एसबीआई, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो का स्थान रहा। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2025–26 की दिसंबर तिमाही में एकल आधार पर 21,028 करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक लाभ दर्ज किया है जबकि एकीकृत आधार पर उसका शुद्ध लाभ 13.06 प्रतिशत बढ़कर 21,317 करोड़ रुपये रहा।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 62 प्रतिशत घटकर 89.67 करोड़ रुपये

नयी दिल्ली, (भाषा) प्रमुख उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माता कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का वित्त वर्ष 2025–26 की अक्टूबर–दिसंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 61.58 प्रतिशत की गिरावट के साथ 89.67 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी ने बुधवार को तीसरी तिमाही के अपने वित्तीय परिणामों की जानकारी दी। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ने पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 233.45 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।

चालू वित्त वर्ष में 10 फरवरी तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 9.4 प्रतिशत बढ़कर 19.44 लाख करोड़ रुपये पर

नयी दिल्ली, (भाषा) चालू वित्त वर्ष में 10 फरवरी तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 9.4 प्रतिशत बढ़कर लगभग 19.44 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह बढ़ोतरी कॉरपोरेट कर की बेहतर वसूली और कर रिफंड की धीमी गति का परिणाम है। आयकर विभाग की तरफ से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह 14.51 प्रतिशत बढ़कर 8.90 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं गैर–कॉरपोरेट कर संग्रह, जिसमें व्यक्तिगत आयकर और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) से मिले कर शामिल हैं, 5.91 प्रतिशत बढ़कर लगभग 10.03 लाख करोड़ रुपये रहा। शेयरों एवं अन्य प्रतिभूतियों के लेनदेन पर लगाया जाने वाला प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) का संग्रह एक अप्रैल, 2025 से 10 फरवरी, 2026 के दौरान 50,279 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले की समान अवधि के लगभग समान है। इस अवधि में कर रिफंड जारी करने में 18.82 प्रतिशत की गिरावट आई और यह घटकर 3.34 लाख करोड़ रुपये रह गया। रिफंड में कमी से शुद्ध कर संग्रह की वृद्धि दर को सहारा मिला। आंकड़ों के मुताबिक, देश का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 4.09 प्रतिशत बढ़कर 22.78 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसमें 10.88 लाख करोड़ रुपये का सकल कॉरपोरेट कर और 11.39 लाख करोड़ रुपये का सकल गैर–कॉरपोरेट कर शामिल हैं। सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान (आरई) में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 24.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया है।

जनवरी में क्विक कॉमर्स क्षेत्र में कार्यालय वाली भूमिकाओं में भर्ती 21 प्रतिशत बढ़ीः रिपोर्ट

मुंबई, (भाषा) त्वरित आपूर्ति वाले ऑनलाइन खुदरा कारोबार यानी क्विक कॉमर्स क्षेत्र में जनवरी के दौरान पेशेवर एवं प्रबंधन स्तर के पदों की भर्ती में सालाना आधार पर 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। बुधवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। 'फाउंडइट इनसाइट्स ट्रैकर' की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक, क्विक कॉमर्स क्षेत्र अब सिर्फ विस्तार पर केंद्रित रहने के बजाय लाभप्रदता, मांग के अनुमान और परिचालन दक्षता को प्राथमिकता दे रहा है। रिपोर्ट कहती है कि डेटा एनालिटिक्स, उत्पाद प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला रणनीति जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ प्रतिभा की मांग मजबूत बनी हुई है। डिजिटल भर्ती मंच फाउंडइट की उपाध्यक्ष (विपणन) अनुपमा भीमराजका ने कहा, "कंपनियां अब पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाने, भंडार प्रबंधन को अनुकूलित करने और ग्राहक अनुभव सुदृढ़ करने पर जोर दे रही हैं। यह अब टिकाऊ और प्रौद्योगिकी–आधारित विस्तार की ओर बढ़ने का संकेत है।" रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी में सभी उद्योगों में कुल कार्यालय स्तर के पदों पर भर्ती में सालाना नौ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो उच्च कौशल वाली भूमिकाओं में नियोक्ताओं के भरोसे को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार, क्विक–कॉमर्स क्षेत्र में होने वाली कुल भर्ती में कार्यालय स्तर के पदों की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत है। भौगोलिक दृष्टि से बेंगलुरु इस क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।

उत्पादन में भारी कमी से लाल मिर्च और तेजी की उम्मीद

नई दिल्ली, (एनएनएस) लाल मिर्च की बोई हुई फसल भी प्रतिकूल मौसम से काफी क्षेत्रों में गल गई थी। दूसरी ओर किसानों द्वारा इस बार बिजाई भी 20 प्रतिशत कम किया गया था। गुंटूर एवं खम्मम लाइन में लाल मिर्च की आवक हो रही है। दक्षिण भारत की उत्पादक मंडियों में स्टॉक की कमी होने से तेजा माल 2 दिनों में 15/20 रुपए प्रति किलो और बढ़ गया है। आपूर्ति में कमी से बाजार जल्दी 30/35 रुपए प्रति किलो और बढ़ सकता है। इस बार मौसम प्रतिकूल होने से लाल मिर्च की फसल बिजाई के बाद ही काफी खराब हो गई थी तथा कुछ नीचे वाले क्षेत्रों में पानी से फसल गल गई थी, उसके बाद भी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह वाली बरसात से फसल को भारी नुकसान हुआ है। जिस कारण दक्षिण भारत के सभी उत्पादक क्षेत्रों में लाल मिर्च के उत्पादन में कमी आ गई है। फलतः फरवरी के प्रथम सप्ताह में भी आवक नहीं बढ़ पा रही है। लाल मिर्च की गुंटूर वारंगल दुग्गीराला खम्मम सहित तेलंगाना राज्यों में बिजाई के बाद अगस्त से 31 अक्टूबर तक भारी बरसात होने से 45–46 प्रतिशत भूमि में पौधे नष्ट हो गए थे, तत्पश्चात लगे हुए फूल एवं फली अक्टूबर के अंत में काफी खराब हो गई, जिस कारण प्रति हेक्टेयर हरी व लाल मिर्च का उत्पादन 23–24 प्रतिशत कम हो गया है। अभी खम्मम एवं गुंटूर लाइन का नया माल आ रहा है, जो 3 दिन में 15/20 रुपए बढ़ गया है पुराने फुल कट मालों में 10 रुपए तक तेजी आई है। गौरतलब है कि जनवरी के दूसरे पखवाड़े में 50/60 रुपए की उल्लेखनीय तेजी आने के बाद पिछले सप्ताह थोड़ा करेक्शन आ गया था लेकिन फरवरी पहले सप्ताह में भी आवक का दबाव नहीं बन पा रहा है, जिस कारण दोबारा तेजी आ गई है। इधर उत्तर भारत के किसानों को मिर्च में इस बार सीजन पर काफी नुकसान लगा है तथा उत्पादन व मिर्च की तुड़ाई की लागत महंगी हो जाने से 22–23 प्रतिशत बिजाई कम हुई थी। इसके अलावा दक्षिण भारत में गुंटूर वारंगल ब्यादगी, कडप्पा लाइन में भी विगत दो वर्षों से लाल मिर्च के भाव नहीं मिलने से किसानों ने बिजाई कम किया है तथा उसकी बजाय मक्की पर ज्यादा रुझान बना हुआ था। इसकी पुरानी फसल फरवरी में आई थी तथा इस बार गुंटूर लाइन के सभी कोल्ड स्टोर में गत वर्ष की तुलना में स्टॉक कम बचेगा, डंडीदार तेजा हल्का एवं मीडियम माल का स्टॉक ज्यादा था, वह माल पंजाब हिमाचल एवं बिहार बंगाल में ज्यादा गया है, क्योंकि इंदौर लाइन की फसल इस बार पहले की अपेक्षा कम आई थी। इस समय इंदौर लाइन का डंडीदार 200/215 रुपए प्रति किलो बिक रहा है तथा खम्मम का तेजा 265/270 रुपए हो सकता है। फुल कट 255/270 रुपए के बीच बिक रहा है। वह 300 रुपए बन सकता है। फसल में पोल आने से इसमें 35/40 रुपए प्रति किलो क्वालिटी अनुसार माल में और तेजी लग रही है। इस वजह से अब कोल्ड स्टोरों का माल 85 प्रतिशत निपट गया है तथा कोई भी कारोबारी स्टॉक के प्रेशर में नहीं है। दूसरी और सर्दी बढ़ने ग्राहकी चौतरफा पहले की अपेक्षा अच्छी है। वर्तमान भाव में बाजार तेज लग रहा है। उधर हिमाचल में अधिक बरसात से पिछले दिनों तबाही हुई थी, अब वहां के कारोबारी माल खरीदने लगे हैं। चालू महीने शादियों के चलते चालानी मांग फिर अच्छी हो गई है। गुंटूर लाइन के कोल्ड स्टोर में गत वर्ष की तुलना में स्टाक कम है तथा वारंगल दुग्गीराला ब्यादगी लाइन में भी माल ज्यादा नहीं है तथा वहां जो स्टाक में माल पड़ा है, उसके ऊंचे भाव बोल रहे हैं।

एयरटेल का ओटीपी से संबंधित बैंक धोखाधड़ी से निपटने को एआई–आधारित समाधान पेश

नयी दिल्ली, भारती एयरटेल ने ग्राहकों को वन–टाइम–पासवर्ड (ओटीपी) से संबंधित बैंक धोखाधड़ी के तेजी से बढ़ते खतरे के खिलाफ तत्काल आधार पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए बुधवार को एआई–संचालित समाधान फ्रॉड अलर्ट का अनावरण किया। एयरटेल की विज्ञप्ति में बताया गया कि जालसाज अक्सर डिलिवरी जैसी रोजमर्रा की सेवाओं के लिए ओटीपी से जुड़ी तात्कालिकता का फायदा उठाते हैं। वे ग्राहकों से उनके बैंकिंग लेन–देन के ओटीपी शेयर करवा लेते हैं, जिससे उनके खाते का पैसा चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है। एयरटेल की नई एआई–संचालित प्रणाली ऐसे संभावित खतरे की पहचान करती है और ग्राहकों को तुरंत सचेत करती है। जब किसी संभावित जोखिम भरी कॉल के दौरान बैंकिंग ओटीपी का पता चलता है, तो एयरटेल तुरंत एक फ्रॉड अलर्ट भेजता है और ग्राहक को यह बताता है कि कॉल के दौरान बैंकिंग ओटीपी देने से उन्हें धोखाधड़ी का खतरा हो सकता है। एयरटेल इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) शाश्वत शर्मा ने कहा, "...हमने महसूस किया है कि डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित करने में वन–टाइम पासवर्ड (ओटीपी) द्वारा निभाई गई मूलभूत भूमिका के बावजूद, आपराधिक रणनीति द्वारा उनकी दक्षता को अक्सर कम किया जा रहा है।"

विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश के लिए 24.5 करोड़ डॉलर के कर्ज को मंजूरी दी

नयी दिल्ली, (भाषा) विश्व बैंक ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश में अधिक मजबूत बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और सामुदायिक स्वामित्व वाली कंपनियों को अधिक भरोसेमंद रोजगार में निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए 24.5 करोड़ डॉलर के ऋण की मंजूरी दी। विश्व बैंक ने बयान में कहा कि हिमाचल प्रदेश पिछले तीन साल में प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से प्रभावित रहा है। इसके परिणामस्वरूप अनुमानित एक अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। बयान में कहा गया है कि 2023 और 2025 के मानसून के मौसम में भारी बारिश के कारण जानमाल का नुकसान हुआ, घरों और बुनियादी ढांचे को व्यापक क्षति पहुंची और स्कूलों, बाजारों और रोजगार तक पहुंच सीमित हो गई। जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में व्यवधान ने कृषि और बागवानी उत्पादन को भी प्रभावित किया है। बयान में कहा गया है कि 'विकास और आपदा पुनरुद्धार हिमाचल प्रदेश परियोजना (24.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर) के लिए मजबूत कार्ययोजना' राज्य के आपदा बाद पुनरुद्धार प्रयासों का समर्थन करेगी और मजबूत बुनियादी ढांचे की बेहतर योजना और डिजाइन के माध्यम से भविष्य में आपदा के प्रभावों को कम करने में मदद करेगी। कृषि, स्थानीय हस्तशिल्प और ग्रामीण पर्यटन क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच और आजीविका के बेहतर अवसरों से दस लाख से अधिक महिलाओं को लाभ होगा। बयान के अनुसार, सामुदायिक स्वामित्व वाले व्यवसायों में निवेश से 12,000 लोगों को नए या बेहतर रोजगार मिलेंगे और कारीगरों, उत्पादकों तथा किसानों के लिए नए बाजार संबंध बनेंगे।

मांग कमजोर रहने से अधिकांश तेल–तिलहन कीमतों में गिरावट, सोयाबीन तिलहन में सुधार

नयी दिल्ली, (भाषा) भारत–अमेरिका व्यापार समझौते के बाद तेल–तिलहन बाजार की कारोबारी धारणा कमजोर रहने तथा मांग सुस्त रहने के बीच देश के तेल–तिलहन बाजार में बुधवार को अधिकांश तेल–तिलहन के दाम टूट गये। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में प्लांट वालों द्वारा सोयाबीन का दाम बढ़ाने के कारण सोयाबीन तिलहन के दाम सुधार दर्शाते बंद हुए। शिकॉगो एक्सचेंज में घट–बढ़ है। जबकि मलेशिया एक्सचेंज दोपहर साढ़े तीन बजे गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार सूत्रों ने बताया कि सरसों के भाव पहले ही ऊंचे हैं जिससे मांग कमजोर है। इसके अलावा, मौसम खुलने के बाद सरसों की नई फसल भी 10–15 दिन में बाजार में आ जायेगी तो आगे दाम में और गिरावट आ सकती है। इसी प्रकार, खराब बाजार धारणा के बीच, पैसों की तंगी की वजह से आयातकों की ओर से लागत से नीचे दाम पर की जा रही बिकवाली के कारण सोयाबीन तेल के दाम भी टूट गये। उन्होंने बताया कि मलेशिया एक्सचेंज में गिरावट तथा जाड़े में मांग कमजोर रहने के बीच पाम–पामोलीन तेल के दाम में भी गिरावट देखी गई। सूत्रों ने बताया कि बाजार धारणा खराब होने के बीच बाकी तेल–तिलहनों की तरह बिनौला तेल कीमतें भी गिरावट के साथ बंद हुई। सूत्रों ने बताया कि सोयाबीन तिलहन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 5,328 रुपये क्विंटल है। मध्य प्रदेश में 12–15 दिन पहले सोयाबीन तिलहन का दाम घटाकर 5,900–5,950 रुपये क्विंटल कर दिया था। जबकि किसानों को पहले जैसा इससे कहीं अधिक दाम फिर से मिलने की उम्मीद है। कल दाम घटाये जाने के बाद किसानों ने बाजार में आवक लाना कम कर दिया जिसके बाद आज प्लांट वालों ने आवक की कमी को दूर करने के लिए सोयाबीन के दाम में 200–250 रुपये क्विंटल की वृद्धि की। इस वजह से सोयाबीन तिलहन कीमतों में सुधार है। हालांकि, गत दिनों दाम घटाये जाने के बावजूद घटा हुआ दाम एमएसपी से अधिक ही था पर किसानों को पहले की तरह इससे भी ऊंचे दाम मिलने की उम्मीद है।

तेल–तिलहनों के भाव इस प्रकार रहे: सरसों तिलहन – 6,935–6,960 रुपये प्रति क्विंटल।
मूंगफली – 6,975–7,350 रुपये प्रति क्विंटल।
मूंगफली तेल मिल डिलिवरी (गुजरात) – 17,000 रुपये प्रति क्विंटल।
मूंगफली रिफाइंड तेल – 2,710–3,010 रुपये प्रति टिन।
सरसों तेल दादरी– 14,225 रुपये प्रति क्विंटल।
सरसों पक्की घानी– 2,395–2,495 रुपये प्रति टिन।
सरसों कच्ची घानी– 2,395–2,540 रुपये प्रति टिन।
सोयाबीन तेल मिल डिलिवरी दिल्ली– 14,450 रुपये प्रति क्विंटल।
सोयाबीन मिल डिलिवरी इंदौर– 14,050 रुपये प्रति क्विंटल।
सोयाबीन तेल डीगम, कांडला– 11,310 रुपये प्रति क्विंटल।
सीपीओ एक्स–कांडला– 11,825 रुपये प्रति क्विंटल।
बिनौला मिल डिलिवरी (हरियाणा)– 13,050 रुपये प्रति क्विंटल।
पामोलिन आरबीडी, दिल्ली– 13,700 रुपये प्रति क्विंटल।

RBI Rolls Out Measures to Strengthen Cooperative Banks' Financial Health, Governance and Digital Inclusion

New Delhi, Focus News: The Reserve Bank of India (RBI), in consultation with the Government of India, has announced that loans sanctioned by banks to National Cooperative Development Corporation (NCDC) w.e.f. January 19, 2026, for on-lending to cooperative societies are eligible for classification as priority sector lending under the respective categories. These apply to banks other than Regional Rural Banks, Urban Cooperative Banks, Small Finance Banks and Local Area Banks. These loans are for purposes and activities as laid down in the Master Direction on Priority Sector Lending, 2025. National Cooperative Development Corporation (NCDC), a statutory corporation under the administrative control of the Ministry of Cooperation, provides financial assistance to Cooperatives and contributes directly in accelerating the growth of cooperative movement The Government of India and RBI have taken various measures to strengthen cooperative banks' financial health, governance and digital inclusion along with enhancing deposit security, credit availability and prudent regulation, which inter-alia include:

Urban Cooperative Banks (UCBs) have been allowed to open new branches

Housing loan limits have been increased from 10% to 25% of their total loans and advances for UCBs

The Banking Regulation Act has been amended to increase the terms of directors of Cooperative Banks from 8 to 10 years

Licensing fee for onboarding of cooperative banks to Aadhar enabled Payment System (AePS) have been reduced

The National Urban Co-operative Finance and Development Corporation Limited (NUCFDC), which is a non-deposit taking Non-Banking Financial Company (NBFC), has been set up as an Umbrella Organization for Urban Cooperative Banks to provide Information Technology (IT) infrastructure and operational support

A Shared Services Entity (SSE), Sahakar Sarthi, has been established to provide technological services to Rural Cooperative Banks

Rural Cooperative Banks have been included by RBI in the Integrated Ombudsman Scheme

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) insures various types of deposits up to ₹ 5,00,000 per depositor per bank (including principal and interest) for all cooperative banks

This information was given by the Minister of State in the Ministry of Finance Pankaj Chaudhary in Rajya Sabha.

Fiji Finance Minister Mr. Esrom Immanuel visits Mahalekha Niyantrak Bhawan in New Delhi; meets Controller General of Accounts Ms. T.C.A. Kalyani

New Delhi, Focus News: The Controller General of Accounts of India (CGA), T.C.A. Kalyani, hosted a delegation led by the Finance Minister of the Republic of Fiji, Mr. Esrom Immanuel, at Mahalekha Niyantrak Bhawan, in New Delhi. A detailed discussion took place about the Public Finance practices in both the nations, including the digital transformation made by India in its Public Financial Management processes. The discussion also included the role played by the Public Financial Management System (PFMS) in helping transfer the benefits directly into the Bank accounts of the beneficiaries. Esrom Immanuel appreciated the advances made by India in the field of Public Finance and discussed ways to further deepen the cooperation in this field, including inter-alia, asset management, capacity building, budget ecosystem and internal audit.

Delhi-NCR to be strengthened with expansion of Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations

New Delhi, Focus News: The air quality monitoring framework in Delhi-NCR is being significantly strengthened through systematic augmentation of the Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations (CAAQMS) network to ensure spatial coverage, improved data reliability and robust scientific assessment of air pollution across the region. The initiative is aimed at enhancing real-time air quality surveillance and supporting evidence-based policy interventions for effective air pollution abatement in Delhi-NCR. As part of the ongoing strengthening of the air quality monitoring network, the Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas (CAQM) has been reviewing the status of augmentation of 27 new CAAQMS across Delhi-NCR [06 in Delhi, 07 in Haryana (NCR), 04 in Rajasthan (NCR) and 10 in Uttar Pradesh (NCR)], over and above the existing network of 84 monitoring stations (40 in Delhi, 22 in Haryana-NCR, 04 in Rajasthan-NCR and 18 in Uttar Pradesh-NCR) operated by concerned agencies in the region.

Out of the 27 new CAAQMS across Delhi-NCR:

- 06 CAAQMS have been installed in Delhi;
- 07 new CAAQMS in Haryana (NCR), 04 in Rajasthan (NCR) and 10 in Uttar Pradesh (NCR) are in the process of installation.

In addition to the ongoing augmentation, the scientific criteria for future expansion of the air quality monitoring network in Delhi-NCR has also been deliberated in detail. It was emphasised that monitoring density must adequately reflect population distribution, land-use characteristics such as residential, traffic, industrial and background areas, urban contiguity and the rapid expansion of peri-urban/suburban regions. The need for grid-based spatial coverage has been considered. Further, background and border stations are also required to better understand regional transport of pollutants and baseline air quality levels influencing Delhi-NCR.

Accordingly, in addition to existing population-based norms for Delhi and contiguous cities of Ghaziabad, Noida, Greater Noida, Faridabad, Ghaziabad, Sonepat, norms have been framed for installation of air quality monitoring stations at approximately one station in each 25 sq. km. (5 km × 5 km grid), while other district headquarters and cities would have one station per 50 sq. km. area. Monitoring coverage in peri-urban and suburban areas has also been identified as critical for assessing inflow and outflow of pollution and understanding the impact of urban sprawl on regional air quality.

Further, based on above-mentioned criteria, 46 additional stations, including 14 in Delhi, 16 in Haryana (NCR), 01 in Rajasthan (NCR) and 15 in Uttar Pradesh (NCR), shall be installed to strengthen the air quality monitoring infrastructure and ensure comprehensive and uniform air quality monitoring across Delhi-NCR. Taking into account the additional stations, the total number of CAAQMS in Delhi-NCR would be 157, comprising 60 stations in Delhi, 45 in Haryana, nine in Rajasthan, and 43 in Uttar Pradesh (NCR).

A Grand Celebration of Talent and Music at the Finale of Ghaziabad Idol – Season 3

Ghaziabad, Focus News: The grand and successful finale of Ghaziabad Idol – Season 3, organized under the aegis of Dhindhora Music Private Limited, was held on January 8, 2026, at Hindi Bhawan, Lohia Nagar, Ghaziabad. The event was conducted under the able leadership and guidance of Chairman Dr. Mahesh Kumar White and Managing Director Dr. Mamta Goyal.

The event witnessed the gracious presence of distinguished personalities from the music fraternity who served as the esteemed jury members. The panel of judges included Dr. Omkar Bhardwaj, Mr. Gopal Gaur, Dr. Sandhya Rathi, Mr. Gyandeep, Mr. Sanjay Phillips, Ms. Seema Saxena, and Mr. Sanam Khan. The respected judges appreciated the performances of the participants and provided valuable guidance and encouragement.

The program was energetically and professionally hosted by Mr. Ashish Bhatnagar and Shaan Hindustani, who kept the audience engaged and ensured the event was conducted in a disciplined and lively manner.

Participants from various parts of the country mesmerized the audience with their melodious voices and outstanding performances. The auditorium resonated with soulful music, leaving the audience spellbound and emotionally moved.

The event was the result of months of dedicated effort by the team of Dhindhora Music Private Limited. After conducting extensive auditions over a long period, deserving talents were selected, and the remarkable outcome was witnessed on the grand finale stage.

On this occasion, Chairman Dr. Mahesh Kumar White stated, "Ghaziabad Idol is not merely a competition for us, but an initiative to recognize emerging talents across the country and provide them with a powerful platform."

Managing Director Dr. Mamta Goyal added, "The objective of Dhindhora Music Private Limited is to promote art and music at the grassroots level and continuously encourage new artists."

The Chief Guest of the program, Mr. Mayank Goyal (Metropolitan President, BJP, Ghaziabad), in his address said, "Platforms like Ghaziabad Idol play a significant role in nurturing young talent and giving them national recognition. Such events provide a positive direction to society."

During the program, Chief Guest Mr. Mayank Goyal also formally unveiled the cover page of the official magazine of Dhindhora Music Private Limited. Additionally, two books authored by Chairman and renowned litterateur Dr. Mahesh Kumar White, titled "Tamanna" and "Tahrir," were ceremoniously launched. The book launch added literary dignity to the event.

The Special Guest, Mr. Man Singh Goswami (Vice President, Western Uttar Pradesh, BJP), remarked,

"Music and art are the soul of any society. Platforms like Ghaziabad Idol not only bring forward young talent but also strengthen our cultural heritage. The efforts of Dhindhora Music Private Limited are truly commendable."

On this occasion, Dr. Mahesh Kumar White honored all the guests by presenting his books, calendars, and mementos, adding warmth and grace to the ceremony.

Winners of the Competition:

Junior Category

Winner – Aryaman Chhabra

First Runner-up – Ada Srivastava

Second Runner-up – Shraddha Bal

Senior Category

Winner – Damini Kumari

First Runner-up – Rohit Vishwas

Second Runner-up – Prateek Saraf

The success of the program was made possible by the dedicated efforts of the entire team of Dhindhora Music Private Limited. Directors Mr. Alok Kumar and Mr. Chirag Chaudhary, Manager Mrs. Riya Singh, Mrs. Ankita Singh, and organizing team members Mr. Naresh Kumar Gautam, Mr. Gaurav Singh, Mr. Ritik, Ms. Yogita, Ms. Neha, Ms. Isha, and Mr. Jitendra played highly commendable roles. The finale of Ghaziabad Idol – Season 3 emerged not just as a music competition, but as an inspiring and memorable platform celebrating art, literature, and emerging talent.

Union Budget 2026–27 Drives Passenger-Centric Railway Modernisation, Enhanced Safety, and All-Round Regional Development

New Delhi, Focus News: Railway development across the country has received a major boost under the Union Budget, with record allocations to states aimed at strengthening connectivity, enhancing passenger safety, modernising infrastructure, and expanding freight networks. This sustained investment reflects the government's commitment to all-round development, positioning railways as a key driver of economic growth and logistics efficiency nationwide. In the Union Budget 2026–27, the Ministry of Railways has firmly positioned rail investment as a driver of regional integration, passenger convenience, and economic opportunity across states, aligned with priorities such as high-speed connectivity, multi-modal mobility, electrification, and secure logistics. Major states like Uttar Pradesh are poised for transformation through new bullet-train corridors between Delhi–Varanasi and Varanasi–Siliguri, aimed at sharply reducing travel time between key economic and cultural centres, strengthening tourism flows, and connecting secondary cities along the route. The proposed Varanasi–Siliguri corridor will connect important religious, educational, and medical centres across Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. The Delhi–Varanasi high-speed corridor will enable travel in around 3 hours 50 minutes. Further, the high-speed rail corridor from Varanasi via Patna to Siliguri in West Bengal will enable travel between Varanasi and Siliguri in about 2 hours and 55 minutes. This connectivity is expected to create a new economic corridor across the belt spanning Delhi, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal, significantly boosting regional development and economic activity. West Bengal is similarly set to benefit from the first high-speed rail service in eastern India linking Siliguri to Varanasi, improving inter-regional mobility and expanding trade and service opportunities. Across the Northeast and adjoining regions, record allocations have triggered new line construction, station redevelopments, and safety enhancements, improving connectivity within remote areas and strengthening links with the rest of the country. These works are expanding access to education, healthcare, tourism, and formal markets, while supporting local enterprises. A key strategic priority is the planned 40-km underground rail corridor, connecting the North East with the rest of the country. The planning is on to lay underground railway tracks, and also make the existing tracks four-line, creating additional capacity and ensuring uninterrupted, resilient rail movement through this critical transit zone for both passengers and freight. States such as Punjab, Haryana and Himachal Pradesh have completed 100% electrification and are upgrading stations under the Amrit Bharat Station Scheme, improving rail safety, sustainability, and passenger facilities. In mineral and industrial belts, projects in Jharkhand and the Rowghat–Jagdalpur line in Chhattisgarh are strengthening freight linkages and regional economic activity. In Southern India, the state-wise railway allocations are clearly geared towards high-impact passenger connectivity, anchored around the emerging high-speed rail "diamond" linking Hyderabad, Bengaluru, Chennai and adjoining urban centres. This network will significantly compress travel times between the south's major economic engines, enabling seamless movement across the IT, manufacturing and services corridors. Bengaluru, as India's principal technology hub, stands to gain the most, becoming far more accessible for business travel, talent mobility and inter-state commuting. After the completion of the high speed corridor, Chennai–Bengaluru will take about 1 hour 13 minutes, Bengaluru–Hyderabad around 2 hours, and Chennai–Hyderabad around 2 hours 55 minutes. This network is expected to serve as a powerful growth multiplier for Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Puducherry, significantly boosting regional development. In Maharashtra, the major share of the allocation is focused on high-impact, capacity-enhancing projects, particularly the Mumbai–Pune high-speed rail corridor, expansion of congested trunk routes, modernisation and redevelopment of key stations, and strengthening of suburban and inter-city rail services to support the state's rapidly growing passenger and freight demand. In western and central India, the upcoming Mumbai–Pune high-speed corridor will reduce travel time to around 48 minutes, effectively integrating the two major urban centres. Further connectivity from Pune to Hyderabad in around 1 hour 55 minutes, and onward links to southern hubs, will create a continuous high-speed spine across regions, benefiting passengers and regional economies alike. In the Himalayan and northern regions, the budget is set to boost economic access, tourism, and all-weather mobility. Uttarakhand's Rishikesh–Karnaprayag line, featuring complex tunnels, will improve access to remote areas, reduce travel time, and support pilgrim and tourist flows, alongside broader investments in electrification and safety upgrades. Himachal Pradesh will see focused support for network expansion, modernisation, and electrification, enhancing passenger convenience in hilly terrain. In Jammu & Kashmir, strengthened rail links, including extensions toward Uri, will ensure year-round connectivity despite winter disruptions, benefiting passengers and local economies. Freight efficiency is being strengthened through the East–West Dedicated Freight Corridor from Dankuni (West Bengal) to Surat (Gujarat), passing through Jharkhand, Bihar, Odisha, and Maharashtra. This corridor will enable faster and more reliable movement of goods, ease congestion on passenger lines, reduce logistics costs, and support industrial and trade growth across these key economic states. For passengers, these initiatives mean shorter travel times, safer and more comfortable trains, modernised stations, reduced overcrowding, and improved last-mile connectivity. At the same time, Indian Railways' long-term goal of 3,000 million tonnes of freight loading will be supported through dedicated freight corridors, modern locomotives, upgraded tracks, and advanced signaling, allowing goods to move faster without disrupting passenger services. Higher capital investment across states will create jobs, boost regional development, and strengthen local economies. With strong coordination between the Union and state governments, the vision of Viksit Bharat can be realised. Following the policy announcement, detailed planning and implementation will now begin to turn this vision into reality.

State-wise Rail Budget Allocation Details: Andhra Pradesh: Andhra Pradesh has witnessed a remarkable transformation in its railway infrastructure, with the annual average budget for the state and Telangana increasing elevenfold from ₹886 crore in 2009–14 to ₹10,134 crore in 2026–27. This significant investment has supported ongoing projects worth ₹92,649 crore.

India's Ease of Doing Business Performance Strengthened; World Bank B-READY Assessment Scheduled in 2026

New Delhi, Focus News: In the last 5 years, India have improved by 79 ranks in EoDB rankings published by World Bank Group as Doing Business Report. As per the latest DBR ranking published in 2019, India ranked at 63. Following the discontinuation of the DBR Report in 2020, the World Bank launched the B-Ready Assessment in 2024 to evaluate 180+ countries over three years across 10 topics spanning the entire business lifecycle: Business Entry, Business Location, Utility Services, Labor, Financial Services, International Trade, Taxation, Dispute Resolution, Market Competition, and Business Insolvency. India is to be part of the Third B-Ready Report, schedule to release in 2026. With a view to improve India's business climate, attract investments, and foster economic growth, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) has launched several initiatives including Business Reforms Action Plan (BRAP) under the overall umbrella initiative of Ease of Doing Business. BRAP initiative was launched in 2014 by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT). It focuses on streamlining regulations, reducing compliance burdens, and implementing digital solutions to improve the business environment in India. Key reforms include establishing single window systems, simplifying building permissions, enhancing inspection procedures, and digitizing various business processes. These reforms aim to make India a more attractive destination for both domestic and foreign investment. So far, seven editions of BRAP (2015, 2016, 2017-18, 2019, 2020, 2022 and 2024) have been completed, wherein States/UTs have been assessed. The seventh edition, BRAP 2024, is currently in progress. Over 9,700 reforms have been carried out across States and Union Territories. State/UT Ranking on Ease of Doing Business. Under the Regulatory Compliance Burden (RCB) initiative, launched by the Government of India in 2020, Central Ministries/Departments and States/UTs undertook a self-identification exercise to reduce burdensome compliances for businesses and citizens. As a result, over 47,000 compliances have been reduced during the last five years.

Of the total compliances reduced:

16,109 compliances were simplified, 22,287 compliances were digitized, 4,623 compliances were decriminalized, and

4,270 compliances were eliminated by removal of redundant and duplicative requirements.

Further, under the RCB+ initiative, 4,846 compliances have been reduced out of 6,262 identified compliances across 23 Acts commonly implemented by States/UTs.

The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 was passed in both Houses of the Parliament (Lok Sabha on 27th July 2023, Rajya Sabha on 02nd August 2023) and received President's Assent on 11th August 2023. The Act decriminalizes 183 provisions under 42 Acts administered by 19 Ministries/ Departments. The Act employs various approaches to decriminalization, including the removal of both imprisonment and fines, conversion of imprisonment and/or fine into penalties, and the introduction of compounding of offenses in certain cases. DPIIT on recommendations of the Joint Parliamentary Committee initiated the process of further identifying minor criminal provisions to be compiled for another common amendment bill. The Jan Vishwas (Amendments of Provisions) Bill, 2025 was approved by the Union Cabinet on 12.08.2025 and was subsequently laid before the Lok Sabha on 18 August 2025. Thereafter, the Bill was referred to the Select Committee constituted under the Chairmanship of Shri Tejasvi Surya. At present, the Bill is under examination by the said Committee.

This exercise builds on the success of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 by expanding the reform agenda to cover 16 Central Acts administered by 10 Ministries/Departments. A total of 355 provisions are proposed to be amended 288 provisions decriminalized to foster Ease of Doing Business, and 67 provisions proposed to be amended to facilitate Ease of Living. To systematically reduce regulatory overlaps and eliminate redundant compliances, the Government adopted a multi-stage institutional and analytical approach under the RCB initiative. Key measures undertaken include:

Conducting self-identification exercises by Central Ministries/Departments and States/UTs to identify overlapping, obsolete and duplicative compliances, which led to the identification of over 47,000 compliances for review.

Analytical mapping by DPIIT of more than 42,000 reduced compliances across over 670 unique Acts to identify common regulatory provisions and overlapping compliance requirements across States/UTs.

Identification of 23 Acts under which more than 10 States/UTs had undertaken compliance reduction, and inclusion of these Acts under the RCB+ initiative for focused harmonisation and rationalisation.

Review of 6,262 compliances under these Acts, resulting in the reduction of 4,846 compliances, thereby addressing inter-State and intra-regulatory duplication.

These measures have enabled elimination of redundant compliances, reduction of regulatory overlaps, and harmonisation of regulatory frameworks across jurisdictions.

The Government of India has undertaken a series of comprehensive reforms under the Business Reform Action Plan (BRAP), which cut across critical areas such as Labour, Environment, Land Administration, and Taxation. These measures have significantly reduced both turnaround time and cost for setting up and operating businesses in the country. The intent of the Government is clear—to create a favorable and enabling environment for enterprises, thereby strengthening India's position as an attractive investment destination.

BRAP, true to its dynamic nature, has continuously evolved to incorporate additional reforms, focus sectors, and the adoption of Information and Communication Technology (ICT) for delivering quality and efficient services to businesses.

All India Institute of Ayurveda Signs MoU with General Insurance Council to Provide Cashless Treatment Facility under 32 Insurance Companies

New Delhi, Focus News: In a significant milestone towards integrating Ayurveda with the mainstream health insurance ecosystem, the All India Institute of Ayurveda (AIIA), New Delhi, an autonomous institute under the Ministry of Ayush, has signed a Common Empanelment Memorandum of Understanding (MoU) with the General Insurance Council (GIC) on 10 February 2026. With this agreement, AIIA has been empanelled with all 32 general insurance companies under the General Insurance Council, enabling patients to avail cashless treatment facilities for eligible Ayurveda-based healthcare services. The MoU was formally signed by Prof. (Vaidya) P. K. Prajapati, Director, AIIA, and Shri Segar Sampathkumar, Director (Health), General Insurance Council, in the august presence of Prof. Bejon Kumar Misra, Chairman, Core Group of Experts on Ayush Health Insurance. The event was also attended by Prof. (Dr.) Mahesh Vyas, Dean (Ph.D.), Prof. (Dr.) R. K. Yadav, Dean (PG), Dr. Alka Kapoor, Director Medical Services (DMS), and other senior faculty members of AIIA. Speaking on the occasion, Prof. (Vaidya) P. K. Prajapati, Director, AIIA, said that with the signing of this MoU, AIIA has become eligible to provide cashless treatment services under all 32 insurance companies associated with the General Insurance Council. He expressed gratitude to the Ministry of Ayush and the entire AIIA team for their sustained efforts and stated that this initiative would significantly benefit patients by improving access, affordability, and trust in Ayurveda-based healthcare. Congratulating the AIIA team, Prof. Bejon Kumar Misra, Chairman, Core Group of Experts on Ayush Health Insurance, stated that this was the first time in the country that an Ayush institution has entered into a formal empanelment agreement with the General Insurance Council. He added that the availability of cashless treatment facilities at AIIA is expected to enhance patient confidence, expand outreach to a wider population, strengthen institutional credibility, and contribute to increased patient inflow and sustainable growth of Ayush healthcare services. On the occasion, Prof. Misra also highlighted a key initiative of the Ministry of Ayush aimed at facilitating insurance-related support for Ayush treatments. For the first time, the Ministry has launched a dedicated Ayush Health Insurance Helpline to assist beneficiaries in resolving insurance-related queries and improving awareness about Ayush insurance coverage.

PM GatiShakti Network Planning Group Evaluates 352 Infrastructure Projects Worth ₹16.10 Lakh Crore

New Delhi, Focus News: PM GatiShakti National Master Plan (PMGS NMP), a transformative approach for planning and development of infrastructure in the country, was launched in October 2021. The Network Planning Group (NPG), constituted under the PM Gati Shakti National Master Plan (PMGS-NMP) framework, evaluates the critical infrastructure projects of the Central Government to ensure integrated planning, multimodality, inter-modality, synchronization of efforts, last mile connectivity, comprehensive development in and around the project location, data-driven decision makings, etc at the planning stage. As on date, 352 infrastructure projects with total estimated cost of ₹ 16.10 Lakh Crore have been evaluated through the NPG mechanism. Out of these 352 projects, 201 projects have been sanctioned - out of which, 167 projects are under implementation. Ministry of Finance, Department of Expenditure through Part-II (for PM Gati Shakti related expenditure) of the "Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2022-23" made a provision of ₹ 5000 crores for disbursement among the States for infrastructure development in the form of 50 years interest-free loan. Details of projects of the States, approved under the Part-II of the "Scheme for Special Assistance to the States for Capital Investment" and funds allocated. Monitoring of implementation of ongoing Central Sector Projects, including the infrastructure projects planned and evaluated under the PM Gati Shakti framework, costing ₹150 crore and above are carried out by the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI). A detailed flash report, showing status, cost overruns etc., is being published from July 2025 onwards on PAIMANA (Project Assessment Infrastructure Monitoring and Analytics for Nation Building) portal (i.e. https://ipm.mospi.gov.in/ReportPage). Further, an institutional mechanism, i.e. Project Monitoring Group (PMG), has been set up with the objective of milestone-bases monitoring of projects and for expediting issue resolution and fast tracking the execution of large-scale infrastructure projects (having estimated cost of Rs.500 Crore & above). PMG has implemented a unique 5-tier Escalation framework that ensures issues are addressed at the appropriate level, beginning with the respective Ministry for regular issues and escalating upto the PRAGATI (Pro-Active Governance and Timely Implementation) forum for complex issues. This approach streamlines the review mechanism, prevents duplication and enables higher authorities to focus on critical issues. To resolve bottlenecks and ensure timely completion of projects, the PM GatiShakti National Master Plan has been integrated with the PMG that has expedited resolution of issues and regulatory bottlenecks in implementation of the projects. This information was given by the Minister of State for Ministry of Commerce & Industry, Jitin Prasada, in a written reply in the Lok Sabha.

हक़, हुनर, और हौसला: दिव्यांगजनों के लिए बदला बजट का नज़रिया

केंद्रीय बजट 2026–27: दिव्यांगजनों पर 30% ज्यादा निवेश

डॉ. वीरेन्द्र कुमार
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026–27 को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी दस्तावेज़ के रूप में देखा जा रहा है।

दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के बजट में लगभग 30 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि न केवल आंकड़ों की बढ़ोतरी है, बल्कि यह उस बदले हुए सरकारी नज़रिये का संकेत है जिसमें दिव्यांगजन अब सहानुभूति के पात्र नहीं, बल्कि अधिकारों के साथ विकास की मुख्यधारा के साझीदार माने जा रहे हैं। वर्ष 2025–26 में 1,275 करोड़ के बजटीय प्रावधान को बढ़ाकर वर्ष 2026–27 में 1,669.72 करोड़ किया जाना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सरकार दिव्यांगजनों के समावेशी, गरिमापूर्ण और आत्मनिर्भर भविष्य के प्रति गंभीर है।

देश में दिव्यांगजन आबादी में बीते वर्षों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 किए जाने से जरूरतों का दायरा और व्यापक हुआ है। इसी पृष्ठभूमि में बजट 2026–27 में घोषित 'दिव्यांग सहारा योजना' को एक निर्णायक हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है, जिसके तहत ALIMCO को आधुनिक, उच्च गुणवत्ता वाले और तकनीक–आधारित सहायक उपकरणों के निर्माण के लिए सशक्त किया जा रहा है। केंद्र सरकार के मिनीरत्न सार्वजनिक उपक्रम ।स्प्डब्, जिसके पास ISO प्रमाणन, सात विनिर्माण इकाइयाँ और अब तक 35 लाख से अधिक लाभार्थियों का अनुभव है, अब AI–एकीकृत गतिशीलता उपकरणों, ई–ब्रेल तकनीक, श्रवण एवं संज्ञानात्मक सहायक उपकरणों के उन्नत उत्पादन की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इसके लिए स्टार्ट–अप्स और वैश्विक तकनीकी संस्थानों के साथ अनुसंधान एवं नवाचार आधारित साझेदारियाँ भी की जा रही हैं, जिससे आयात पर निर्भरता घटेगी और ADIP जैसी योजनाओं के तहत सस्ती व सुलभ सहायता सुनिश्चित होगी।

बजट में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों के उन्नयन और आधुनिक Assistive Technology Mart के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि अंतिम व्यक्ति तक सहायता समय पर और सम्मान के साथ पहुंच सके। इसके साथ–साथ 'दिव्यांगजन कौशल योजना' के माध्यम से कौशल विकास को रोजगार से सीधे जोड़ा गया है।

यह योजना उन क्षेत्रों पर केंद्रित है जहां भविष्य की संभावनाएं सबसे अधिक हैं– जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जिसका आकार 2030 तक 19–20 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, तेजी से बढ़ता OTT और मीडिया क्षेत्र, तथा ग्रीन जॉब्स जैसे नए अवसर। समावेशी शिक्षण पद्धति, ऑन–द–जॉब प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के बाद सहयोग के ज़रिये यह योजना दिव्यांगजनों के लिए स्थायी आजीविका का रास्ता खोलती है।

मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बजट 2026–27 एक नया भरोसा लेकर आया है। NIMHR, NIEPID और NIEPMD जैसे संस्थानों के सुदृढ़ीकरण, न्यूरो–डाइवर्जेंट व्यक्तियों के लिए उन्नत निदान एवं पुनर्वास सेवाओं तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से दिव्यांग कल्याण को नई ऊँचाई देने की तैयारी है।

कुल मिलाकर, बजट 2026–27 दिव्यांगजनों के लिए रहम या रियायत का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि हक़, हुनर और हौसले के साथ आगे बढ़ने का रोडमैप है। यह बजट कल्याण से सशक्तिकरण की ओर बढ़ते भारत की उस तस्वीर को मजबूत करता है, जहां समावेशी विकास ही विकसित भारत की असली पहचान है।

केरल के लिए 2016 में ही एम्स की घोषणा की गयी थी, लेकिन राज्य ने कदम नहीं उठाये: केंद्रीय मंत्री गोपी

कोल्लम (केरल), केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि 2016 के केंद्रीय बजट में केरल के लिए एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की घोषणा की गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए। केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री ने कहा कि केरल सरकार को एम्स की स्थापना के लिए लगभग चार प्रस्तावित स्थल उपलब्ध कराने चाहिए थे और तब उसके बाद केंद्र सरकार निर्णय लेती। उन्होंने 2026–27 के केंद्रीय बजट के लाभों पर यहां आयोजित प्रेसवार्ता में कहा, ''कश्मीर में एम्स की स्थापना इसी तरह हुई थी।'' जब गोपी से पूछा गया कि उनके विचार से एम्स कहां स्थापित किया जाना चाहिए तो उन्होंने कहा कि 2015 से ही उनकी इच्छा रही है कि यह प्रमुख चिकित्सा सुविधा अलप्पुझा में स्थापित हो, जहां बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य सुविधाएं दयनीय स्थिति में हैं। त्रिशूर के लोकसभा सदस्य गोपी ने कहा, "लेकिन, अगर अलप्पुझा में नहीं, तो इसे त्रिशूर में होना चाहिए, जो केंद्र में है, विकास संबंधी बाधाएं नहीं हैं और जहां अधिक विकास की गुंजाइश है।" गोपी ने साथ ही कहा कि यद्यपि मैने केरल में एम्स लाने का आश्वासन दिया है, " (लेकिन) क्या मैंने कहा था कि यह 2026 में आएगा?" गोपी ने कहा कि अगर राज्य सरकार अभी से तैयारियां शुरू कर दे तो एम्स 2027 या 2028 में हकीकत बन सकता है। उन्होंने यह भी पूछा कि केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान, जब केरल से कई मंत्री थे, तब ऐसी मांगें और सवाल क्यों नहीं उठाए गए। प्रेसवार्ता में गोपी ने केंद्रीय बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसे इस दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है कि 2047 में देश कैसा होना चाहिए।

जटिलताओं के बावजूद भारत को गगनयान कार्यक्रम को पूरी लगन से आगे बढ़ाना चाहिए : शुभांशु शुक्ला

बेंगलुरु, भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने बुधवार को कहा कि अंतर्निहित जटिलताओं और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत को अपने महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को निरंतर उत्साह और लगन के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। अशोक चक्र से सम्मानित शुक्ला ने कहा कि गगनयान अभियान की सफलता भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण करने वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल करा देगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "मुझे लगता है कि एक राष्ट्र के रूप में, मिशन गगनयान के माध्यम से हम जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसा दुनिया के केवल तीन अन्य देशों ने ही किया है।" भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अनुसार, भारत का लक्ष्य 2027 में गगनयान का प्रक्षेपण करना है। ग्रुप कैप्टन शुक्ला इस मिशन के लिए चयनित चार अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। उन्होंने कहा, "ये अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण मिशन हैं। हम एक साहसिक प्रयास कर रहे हैं, और चाहे इसमें कितना भी समय लगे, हमें उसी उत्साह के साथ काम करते रहना होगा।

एसएमई की पूंजी बाजार में पहुंच अब भी सीमित, सूचीबद्धता से कंपनियों का संचालन हो सकता बेहतर: तुहिन कांत पांडेय

मुंबई, फोकस न्यूज, सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि पिछले कुछ समय में हुए विकास के बावजूद, पूंजी बाजार के नजरिये से लघु एवं मझोले उद्यम (एसएमई) क्षेत्र की पहुंच अभी भी सीमित बनी हुई है। पांडेय ने यहां इंडिया एसएमई वित्तपोषण और निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि सूचीबद्धता से ऐसी छोटी कंपनियों में संचालन व्यवस्था बेहतर हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि नियामक संस्था को अतीत में इस मोर्चे पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा, ''भारत की क्षमता के मुकाबले एसएमई पूंजी बाजार अभी भी सीमित बना हुआ है....। कंपनियां पूंजी बाजारों से अपरिचित होने और मर्चेंट बैंकरों तक सीमित पहुंच के कारण बाजार में आने से हिचकिचाती हैं।'' पिछले कुछ वर्षों में सूचीबद्धता में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए पांडेय ने कहा कि आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से पूंजी जुटाने की लागत भी एक बाधा हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियां खुलासा और अनुपालन को 'बोझिल' मानती हैं और दस्तावेज दाखिल करने संबंधी व्यावहारिक मार्गदर्शन अक्सर अस्पष्ट होता है। सेबी प्रमुख ने बाजार से पूंजी जुटाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ऐसा कदम संचालन व्यवस्था को बेहतर बनाता है, जिससे पूंजी की लागत कम हो सकती है क्योंकि बाजार विश्वसनीयता को पुरस्कृत करते हैं। उन्होंने कहा, ''कुछ समय पहले, बाजार से पूंजी प्राप्त करने में एक और बाधा तब उत्पन्न हुई जब कुछ एसएमई ने एसएमई ढांचे के तहत उपलब्ध रियायतों का दुरुपयोग किया। ऐसे मामलों ने एसएमई आईपीओ में निवेशकों के भरोसे को बुरी तरह प्रभावित किया।'' पांडेय ने कहा कि ऐसे भी मामले सामने आए जहां कुछ एसएमई ने सकारात्मक माहौल बनाने और निवेशकों को अपने शेयर खरीदने के लिए प्रेरित करने को अनुचित व्यापार गतिविधियों का सहारा लिया। उन्होंने यह भी बताया कि सेबी और शेयर बाजार दोनों ने इस पर सुधार किया है। उन्होंने कहा कि 1,400 कंपनियां अलग से बनाये गये एसएमई स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं और उनका कुल बाजार पूंजीकरण 4.1 लाख करोड़ रुपये है। इनमें से 350 से अधिक कंपनियां मुख्य शेयर बाजार में स्थानांतरित हो चुकी हैं। पांडेय ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में कंपनियों ने 98 आईपीओ के माध्यम से 9,800 करोड़ रुपये जुटाए। यह वित्त वर्ष 2025–26 में जनवरी तक 232 सूचीबद्धता के साथ बढ़कर 10,500 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने छोटे और मझोले उद्यमों (एसएमई) द्वारा शेयर बाजार के माध्यम से कर्ज जुटाने को स्वागत योग्य कदम बताया। हालांकि, पांडेय ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र से आईपीओ का अधिक चलन है। वित्त वर्ष 2025–26 में इस क्षेत्र का आईपीओ में 44 प्रतिशत हिस्सा था। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण एसएमई की भागीदारी बढ़ाने के लिए पारंपरिक केंद्रों से परे व्यापक पहुंच की आवश्यकता पर जोर दिया।

वाणिज्य सचिव जिनेवा में डब्ल्यूटीओ प्रमुख से मिलेंगे

नयी दिल्ली, (भाषा) वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल अगले महीने कैमरून में बहुपक्षीय निकाय की मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले इस सप्ताह जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की प्रमुख नगोजी ओकोंजो–इवेला से मुलाकात करेंगे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अग्रवाल दूसरे देशों के राजदूतों से भी मुलाकात करेंगे। वाणिज्य सचिव बनने के बाद जिनेवा में सचिव की अपनी टीम और डब्ल्यूटीओ प्रमुख के साथ विभिन्न मुद्दों पर यह पहली आधिकारिक बातचीत होगी। डब्ल्यूटीओ महानिदेशक के साथ बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन इस वर्ष 26–29 मार्च तक कैमरून के याउंडे में होना निर्धारित है। यह सम्मेलन 166 सदस्यीय निकाय का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। अधिकारी ने कहा, ''सचिव 12 और 13 फरवरी को जिनेवा में रहेंगे। वह डब्ल्यूटीओ के मुद्दों पर अपनी टीम के साथ जायजा लेंगे।''

भारत–चीन रणनीतिक वार्ता में व्यापार संबंधी चिंताओं, एलएसी पर स्थिरता को लेकर रहा ध्यान

नयी दिल्ली, (भाषा) भारत और चीन ने व्यापार से संबंधित ''चिंताओं'' को दूर करने के तरीकों पर मंगलवार को चर्चा की और अपने संबंधों में समग्र प्रगति के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया। बातचीत में, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके चीनी समकक्ष मा झाओक्सू ने मुख्य रूप से द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने और पुनर्निर्माण के लिए दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित किया, जो पूर्वी लद्दाख में चार साल से अधिक समय के सैन्य गतिरोध के बाद गंभीर तनाव में आ गए थे। चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री मा ब्रिक्स शेरपा बैठक में भाग लेने के लिए भारत में हैं। भारत–चीन रणनीतिक वार्ता के ढांचे के तहत आयोजित बैठक में दोनों पक्षों ने एक अद्यतन हवाई सेवा समझौते को अंतिम रूप देने की आवश्यकता को रेखांकित किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में ''सकारात्मक गति'' की समीक्षा की और लोगों के बीच आदान–प्रदान को बढ़ाकर तथा ''संवेदनशील मुद्दों पर चिंताओं को दूर करके'' संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। जायसवाल ने ''संवेदनशील मुद्दों'' के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन समझा जाता है कि भारतीय पक्ष दुर्लभ पृथ्वी खनिजों से संबंधित चीन के निर्यात नियंत्रण उपायों को लेकर चिंतित है।

Share your ideas & Suggestions with PM for
my GOV मेरी सरकार
Mann की Baat
on 22nd Feb 2026

visit MyGov.in or
Dial 1800 11 7800 (Toll-Free)
The phone lines shall remain open from 3rd - 20th February 2026